 RNI No. RAJHIN/2020/11458

वर्षः 5 अंकः4 अप्रैल, 2025 मूल्यः 60 रु.

राजस्थान टुडे

विधानसभा...
गरिमा और जवाबदेही पर उठते सवाल
21

टैरिफ की नई... चुनौतियां
31

किरोड़ी VS सरकार
बाबा रे बाबा
5

कब्र में ही रहने दें दफ़न
13

राम नवमी पर शुभकामनाएं

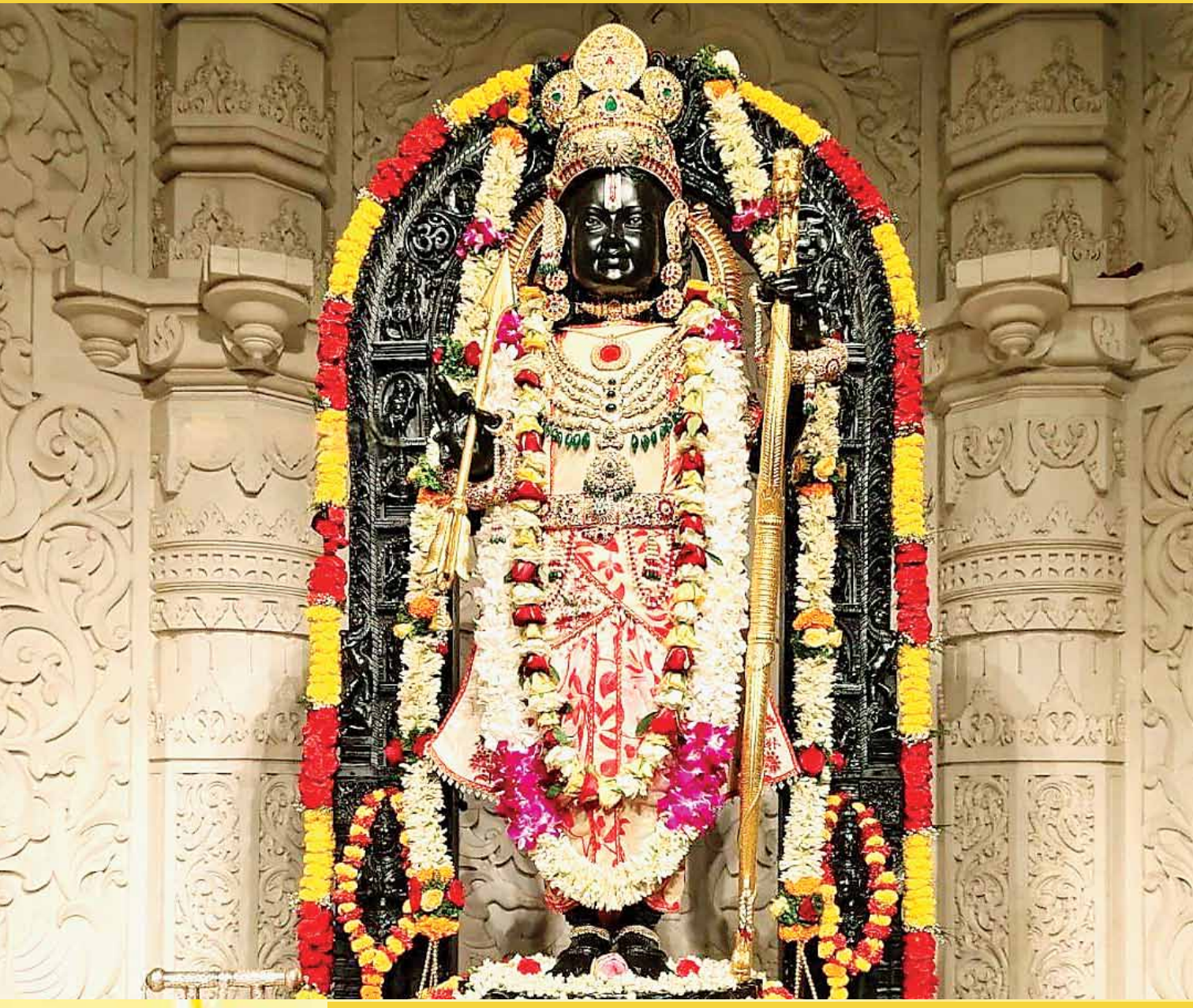

श्री रामनवमी महोत्सव समिति, जोधपुर

शुभेच्छु

पप्पूराम डारा
समिति अध्यक्ष

तरुण सोतवाल
समिति महामंत्री

जितेन्द्र शर्मा
समिति महामंत्री

हिमांशु वाण्डक
समिति महामंत्री

राजस्थान टुडे

आपकी पत्रिका, आपकी बात
www.rajasthantoday.online

RNI No. RAJHIN/2020/11458
वर्ष 5, अंक 4, अप्रैल, 2025
(प्रत्येक माह 15 तारीख को प्रकाशित)

प्रधान सम्पादक
दिनेश रामावत

राजनीतिक सम्पादक
सुरेश व्यास

सम्पादक
अजय अस्थाना

प्रबंध सम्पादक
राकेश गांधी

ब्यूरो प्रभारी
जयपुर- बलवंत राज मेहता

रेखाचित्र- राजेंद्र यादव

संपादकीय कार्यालय
बी-4, फोर्थ फ्लोर, एम.आर. हाईट्स
महावीर कॉलोनी, भास्कर सर्किल,
रातानाड़ा, जोधपुर - 342011
व्हाट्सएप नंबर - 9828032424
ई-मेल - rajasthantoday@gmail.com

सभी विवादों का निपटारा जोधपुर की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

• मारवाड़ मीडिया प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक पूनम अस्थाना द्वारा बी-4, फोर्थ फ्लोर, महावीर कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर-342011 से प्रकाशित और डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 01 पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीयल एरिया, रिलायंस वेयर हाउस के पास, मोगरा कलां, जोधपुर-342802 में मुद्रित, संपादक : अजय अस्थाना।

अंदर के पेजों पर

5

8. किंकर्तव्यविमूढ़ कांग्रेस

12. बाबर को हरा चुके थे राणा सांगा

13. कब्र में ही रहने दें दफन

15. इतिहास होगी तारीख

17. कोटा, एक जिद्दी शहर

19. 'झूठ': कोई दल ऐसा नहीं, जिसने सहारा लिया नहीं

13

22. गरिमा और जवाबदेही पर उठते सवाल

25. डॉ. लुइजि पिओ तैस्सितोरी... इटली का बेटा, राजस्थान की माटी का अपना

26. बोल हरि बोल

27. स्ट्रेटेजिक टाइम आउट! और गेम चेंज

31

29. राजनीति का अपराधीकरण

31. टैरिफ की नई चुनौतियां

34. शब्द भाव का खोल है

37. वह विश्व विजय

41. मानवीय संवेदनाओं का चितेरा

राजस्थान टुडे में प्रकाशित आलेख लेखकों की राय है। इसे राजस्थान टुडे की राय नहीं समझा जाए। राजस्थान टुडे के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी भावना किसी वर्ग या व्यक्ति को आहत करना नहीं है। विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व राजस्थान टुडे का नहीं होगा।

काश, फिर खिल जाए बसंत

दिनेश रामावत ✍

अप्रैल का यह अंक खास रहेगा, इस उम्मीद के साथ इस बार हमने कई मामलों की इनडेप्थ स्टडीज के साथ हर वर्ग की रूचि के अनुरूप सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

भारत को भूगोलीय भाषा में उत्तरी गोलार्द्ध का हिस्सा माना जाता है और अप्रैल का महीना इस गोलार्ध पर बसंत ऋतु की शुरुआत का महीना माना गया है। हम फाल्गुनी रंगों से निकल कर गर्मियों के दिनों की ओर बढ़ रहे हैं।

बसंत की शुरुआत के साथ नए पेड़-पौधों के खिलने के इस मौसम में पहले कभी सुहावने मौसम के साथ परीक्षाएं खत्म होती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते अब बसंत और सुहावना मौसम बेमानी सी लगता है। फिर भी अप्रैल का महीना देश और दुनिया के लिए खास रहता है। अप्रैल फूल यानी मूर्खता दिवस से शुरुआत के साथ यह महीना दुनिया भर में कई वैश्विक उत्सवों और जागरुकता दिवसों के लिए मशहूर है। पूरी दुनिया जहां हर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाती है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। भारत के लिए भी यह महीना काफी महत्वपूर्ण है, खासकर कला, संस्कृति और तीज त्योहारों के कारण।

इसी अप्रैल में जहां भारतीय नवसंवत्सर के साथ नया साल शुरू होता है। गणगौर, चैत्री नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती जैसे कई उत्सव इस महीने को बासंती बना देते हैं। खुशियों के फूल खिलते हैं, उल्लास के रंग फिजां में बिखरते हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लिए इस बार अप्रैल में पवित्र रमजान महीने की विदाई के साथ ईद की खुशियां बरस रही हैं। ईसाई समुदाय के लिए गुड फ्राइडे व ईस्टर की वजह से यह महीना खास है।

आपके लिए भी अप्रैल का यह अंक खास रहेगा, इस उम्मीद के साथ इस बार हमने कई मामलों की इनडेप्थ स्टडीज के साथ हर वर्ग की रूचि के अनुरूप सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस बार एक प्रमुख विश्लेषण देश की ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की दशा और दिशा पर फोकस कर लिखा गया है। कांग्रेस ने देश पर एक छत्र राज किया, लेकिन जिस उत्तर भारत की वजह से वह सिरमौर बनी रही, वहां आज उसे अंगुलियों पर गिना जा सकता है। लगभग एक दशक से ज्यादा वक्त हो गया, कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों को खोती जा रही है। मात्र दक्षिण भारत के दो-तीन राज्यों को छोड़ दें तो कांग्रेस कहीं बची ही नहीं। कभी कांग्रेस के गढ़ रहे उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान व मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस की हालत पहचाने न जा सकने वाले खण्डहर की तरह दिखती है। चुनाव दर चुनाव हार के बावजूद कांग्रेस उबर ही नहीं पा रही। उसका हर प्रयोग उल्टा पड़ रहा है। विरोधी तो यहां तक कह देते हैं कि कांग्रेस के पास न नीति है और न ही नीयत। हालांकि पिछले साल हुए आम चुनाव के बाद कांग्रेस के दिन फिरने की उम्मीद जगी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में हार ने जैसे कांग्रेस को झकझोर दिया। अब हालांकि कांग्रेस जिला स्तर पर तैयारी कर 'बैक टू द रूट्स' की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह पार्टी नेतृत्व पर गांधी-नेहरू परिवार की छाप है और निचले स्तर पर चल रही खींचतान और गुटबाजी अनियंत्रित हो रही है, उसे देखकर सवाल उठाया जा सकता है कि पार्टी नया नेतृत्व कैसे तैयार करेगी।

यूं देखा जाए तो समय काफी बदल गया है। राजनीति पर धनबल-बाहूबल हावी होने लगे हैं। जाहिर है राजनीति में अपराधीकरण भी बढ़ा है। हर पार्टी पर इसके दाग लगे हैं। यहां तक कि सत्ताधारी भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही। कांग्रेस पर

तो पहले ही इसे लेकर आरोप लगते रहे हैं। क्षेत्रीय दल भी इस मामले में कहां पीछे रहे। इसे लेकर हमारी खास रिपोर्ट कहती है कि राजनीति भी अब जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी हो गई है। हालत यह है कि कोई भी इस पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जवाब में सरकार कहती है कि दागदार छवि के लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग तो संविधान को नए सिरे से लिखने जैसी है। इसी तरह के जवाबों से कई बार प्रतीत होता है कि सरकारें खुद नहीं चाहती कि ऐसे कोई प्रभावी कदम उठाए जाएं कि अपराधी राजनीति में न आ सके। दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमें इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

हमनें गढ़े मुर्दे उखाड़ने की होड़ के बीच ताजा पैदा हुए मुगल आततायी औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के मुद्दे पर मचे बवाल के भीतर भी झांकने की कोशिश की है। दरअसल, फिल्मी दुनिया में कमाई के आंकड़ों से धमाका करने वाली फिल्म 'छावा' से यह मुद्दा ऐसा गर्माया कि नागपुर जैसे शहरों में दंगे तक हो गए। औरंगजेब और मराठों के बीच संघर्ष भारत के इतिहास का वह हिस्सा है, जिसने देश में हिन्दु राष्ट्रवाद के विचार को पनपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ताजा विवाद को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से हम कितने ही आगे बढ़ गए, लेकिन मानसिक स्तर पर कुछ मान्यताओं और धारणाओं को आज भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो आमआदमी की भावनाओं से जुड़े हैं, लेकिन क्या हमें किसी की बातों में आकर आपसी सद्भाव भुलाकर इन जज्बातों को हावी हो देना चाहिए।

दुनिया की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने सुर्खियां लूट रखी है। कभी टैरिफ वार तो कभी अवैध प्रवासियों के निष्कासन को लेकर। भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा। कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी इसका अच्छा-बुरा असर दिख ही रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि हम चुपचाप सहन करते रहेंगे या कोई प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आज दुनिया के सामने भारत की जो साख बन रही है, उसे देखते हुए मोदी सरकार की वैट एंड वॉच की नीति को सराहा जाना चाहिए। साथ ही इसने हमें स्वदेशी को बढ़ावे का जो मौका दिया है, उस पर भी गम्भीरता से साथ ही साथ घरेलू मोर्चे पर भी काम हो तो काफी असर हो सकता है।

देश-दुनिया की राजनीति व हलचल के साथ हम कोशिश कर रहे हैं आपको विविधतापूर्ण सामग्री परोसने की। चाहे राजस्थान के लिए खास रहे तैस्सितौरी से रूबरू कराने की कहानी हो या फिर अप्रैल के महीने में ग्रह-गोचर का नए कलेवर में प्रस्तुतिकरण। उम्मीद है, आपको अंक पसंद आएगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूरत अवगत करवाइएगा।

शुभकामनाओं के साथ

किरोड़ी VS सरकार : सरकार के खिलाफ खड़े कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा

बाबा रे बाबा

राजेश कसेरा ✍ वरिष्ठ पत्रकार

भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित हुआ तो किरोड़ी के समर्थकों ने भाजपा मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था। बाद में मंत्री बनाने के बाद उन्हें आधे-अधूरे विभाग मिले तो उनका नाराज होना भी लाजिमी था। उनको दिए कृषि विभाग के साथ वाले विभाग दूसरे मंत्री को दे दिए गए। लोकसभा चुनाव तक वे शांत रहे लेकिन चुनाव परिणाम आते ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो सरकार से नाराजगी की वजह से दिया, लेकिन बहाना पार्टी की हार का बना दिया।

राजस्थान की राजनीति में कितनी ही बड़ी उठा-पटक हो, कुछ दिनों बाद या तो वह शांत हो जाती है या फिर पक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे को लेकर खींचतान चलती रहती है। लेकिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की सियासत की बात करें तो उसमें दशकों से कोई बदलाव नहीं आया है। वे सत्ता में हो या विपक्ष में उनकी राजनीति करने का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला है। मौजूदा भाजपा सरकार में कृषि समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री किरोड़ी ज्यादातर समय अपनों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करते हैं। वे विपक्ष को बैठे-बिठाए भजनलाल सरकार को घेरने के मुद्दे दे देते हैं। बाबा के नाम से ख्यात किरोड़ी बीते सवा साल से प्रदेश की भजनलाल सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। उनके निर्णय और फैसले इतने अप्रत्याशित होते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता कि वे सरकार के अंदर हैं या बाहर। सरकार के साथ हैं या उनके विरोध में। कब, कैसे, कहां और किस बात पर वे सरकार से नाराज हो जाएं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। माटी और आंदोलन के बूते राजस्थान की सियासत के जमीनी नेता माने जाने वाले किरोड़ी लंबे समय से मंत्री पद से इस्तीफा देकर भी बतौर मंत्री काम कर रहे हैं।

> राजनीति में उनके कद और जमीनी नेता की छवि का ही दम है कि न तो भजनलाल शर्मा सरकार, न प्रदेश भाजपा संगठन और यहां तक की दिल्ली बैठा शीर्ष नेतृत्व भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। बीते दिनों सिर्फ नोटिस देकर उनकी लगाई आग पर केवल छींटें देने काम किया गया। इतना ही नहीं, उनकी अपने समाज के बीच जबरदस्त पकड़ है। उनके खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई का मतलब मीणा समाज को नाराज करना होगा। इस समाज का कितना प्रभाव है, इसकी अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश की दो सौ में करीब एक चौथाई यानी पचास सीटें या तो मीणा बहुल हैं या वहां इतने ज्यादा मीणा वोट हैं जो चुनावी हार-जीत को तय करते है। हालांकि किरोड़ी संघ निष्ठ भी हैं और उनकी दिल्ली तक सीधी पहुंच भी है।

हाल ही करौली जिले के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब कभी उन पर राजनीतिक संकट आया जनता ने उनका समर्थन किया। हर परिस्थिति में उन्हें भारी मतों से जीताकर विधानसभा भेजा। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें पार्टी से निकाला गया तब भी उन्हें जनता का साथ मिला। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके कई मायने सियासी गलियारों में निकाले गए। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से उनके कामकाज करने की शैली को देखें तो वे सरकार के साथ कम और बगावती रूप में ज्यादा दिखाई दिए हैं।

अपनी ही सरकार पर लगाए जासूसी के आरोप

इसी साल फरवरी महीने में जयपुर के आमागढ़ मंदिर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में किरोड़ीलाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फोन टैपिंग का बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैंने राज्य में भ्रष्टाचार के कुछ मामले उठाए। इनमें पेपर लीक प्रकरण भी शामिल था। इसके आधार पर 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था, वैसा किया गया। मुझ पर नजर रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर सीआईडी लगा दी। मेरे फोन भी रिकॉर्ड होने लग गए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही बाबा के इन तेवरों का वीडियो सामने आया तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। विधानसभा में भारी हंगामा हुआ और सरकार की किरकिरी हुई। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तक प्रकरण पहुंचा तो उनके निर्देशों पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

उपेक्षा से भड़के, इस्तीफा दे दिया

किरोड़ी प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से रूठे हैं। आलाकमान की ओर से सबसे जूनियर नेता को मुख्यमंत्री बना दिए जाने और वरिष्ठ नेताओं को पीछे धकेलने की रणनीति उनको रास नहीं आई। भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित हुआ तो किरोड़ी के समर्थकों ने भाजपा मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था। बाद में मंत्री बनाने के बाद उन्हें आधे-अधूरे विभाग मिले तो उनका नाराज होना भी लाजिमी था। उनको दिए कृषि विभाग के साथ वाले विभाग दूसरे मंत्री को दे दिए गए। लोकसभा चुनाव तक वे शांत रहे लेकिन चुनाव परिणाम आते ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो सरकार से नाराजगी की वजह से दिया, लेकिन बहाना पार्टी की हार का बना दिया। इसके एक और पहलू को समझें तो किरोड़ी लाल सरकार में अपनी मौजूदा हैसियत से खुश नहीं हैं। वे सरकार में ऐसी प्रभावी भूमिका चाहते हैं, जिसमे उन्हें निर्णय की ताकत मिले। ऐसा कोई पद जैसे उप मुख्यमंत्री या कोई बड़े सरकारी विभाग जैसे गृह, वित्त आदि। उनका एक दर्द यह भी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दीया कुमारी उनके राजनीतिक जीवन के लिहाज से छोटे हैं।

एसआई भर्ती को लेकर सरकार से भिड़े

प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद एसआई भर्ती-2021 में हुए गड़बड़झाले और पेपर लीक प्रकरण की परतें खुलती गईं। 51 ट्रेनी एसआई, आरपीएससी के वर्तमान और पूर्व सदस्य सहित 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। किरोड़ी ने इस मामले को लेकर प्रदेश में लंबा आंदोलन छेड़ रखा था। सरकार बनने के बाद उन्होंने भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की। शुरुआती दिनों में वे मुख्यमंत्री भजनलाल से मिले और भर्ती रद्द करने की मांग की। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। बार-बार आग्रह करने के बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो किरोड़ी सरकार के खिलाफ मीडिया में बयान देने लगे कि यह उनकी समझ से परे है कि भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने एसआई भर्ती को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया।

विधानसभा उप चुनाव में भाई की हार से बौखलाए

विधानसभा चुनाव के बाद से सरकार और पार्टी से नाराज चल रहे किरोड़ी लाल मीणा को मनाने के लिए लिए पार्टी ने उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा को उप चुनाव में टिकट दिया। लेकिन वे चुनाव जीत नहीं सके। भाई की हार से वे काफी आहत हुए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। जगमोहन की हार के लिए उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जगमोहन को जीताने के लिए जोर नहीं लगाया। हार से नाराज होकर उन्होंने नाम लिए बिना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को अभिमन्यु की तरह घेर कर मारा गया। भाई बनाकर पीठ में छुरा घोंप दिया गया।

थानाधिकारी से विवाद में रपट दर्ज होना नागवार गुजरा

इसी साल दो महीने पहले किरोड़ीलाल मीणा का महेश नगर थाने की तत्कालीन थानाधिकारी कविता शर्मा से विवाद हो गया। कविता और कैबिनेट मंत्री के बहस करने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। बाद में एसएचओ ने मंत्री के खिलाफ रोजनामचे में रपट डाल दी। इसके बाद डॉ. मीणा ने भी एसएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंत्री मीडिया सामने आए और एसएचओ कविता के काले कारनामों को सामने रखा। उन्होंने पुलिस अधिकारी को तुरंत हटाने की मांग की, लेकिन सरकार ने मंत्री के उठाए मुद्दों को अनदेखा कर दिया। बाद में ट्रांसफर दूसरे थाने में कर दिया, लेकिन तथ्यों सहित काले कारनामे उजागर करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसे लेकर मीडिया ने सवाल किए तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार में सुनवाई नहीं होती, इसीलिए मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाता हूं।

फिर बोले- मेरा अपमान, मैं हां में हां मिलाने वालों में नहीं

गत 31 जनवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो उस दिन किरोड़ी सदन पहुंचे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वे मौजूद रहे। दोपहर को मीडिया से चर्चा में फिर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में भी उनका अपमान होता था और वर्तमान सरकार में भी हो रहा है। जिन मुद्दों को लेकर हम सत्ता में आए उनको भुला दिया गया। पेपर लीक होना साबित होने के बावजूद भर्ती को रद्द नहीं किया। सरकार की आंखों के सामने रोज सात करोड़ रुपए की बजरी चोरी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि जमाना मिलावट का है पर वे हां में हां मिलाने वाले नेताओं में नहीं हैं।

मंत्री होकर भी विधानसभा से दूर रहे... प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी के पास कृषि विभाग का अहम जिम्मा है। लेकिन जुलाई 2024 में हुए विधानसभा सत्र में भी उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी ले ली। फिर 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ तो वे 1 फरवरी से सदन में नहीं गए। उनके विभाग से जुड़े सवालों के जवाब दूसरे मंत्रियों को देने पड़े। वे सरकार से सीधे तौर पर खफा दिखे, इसलिए विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार में गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे करेंगे।

बाबा को रास नहीं आता सत्ता का साथ

राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी के संघर्ष की बात करें तो उन्होंने सदैव सरकारों के खिलाफ अपने मुद्दों पर संघर्ष किया। उनको सत्ता का साथ कभी रास नहीं आया। उनका यह अंदाज काफी पुराना है। जानकारों की मानें तो भैरों सिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब भी किरोड़ी ने इसी तरह के तेवर दिखाए थे। सदन में इसी तरह मुद्दे उठाते रहे। उनका शेखावत से कई मुद्दों पर सामंजस्य नहीं बैठ पाया। इसके लिए काफी प्रयास भी किए गए, लेकिन किरोड़ी ने अपना अंदाज नहीं बदला। वसुंधरा राजे सरकार से भी उनकी अदावत रही। 2003 में वसुंधरा मुख्यमंत्री बनीं तब किरोड़ी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन दोनों के बीच टकराव बना रहा। वसुंधरा के आगे उनकी नहीं चली तो उन्होंने भाजपा छोड़ दी और नेशनल पीपुल्स पार्टी का हाथ थाम लिया। बाद में वसुंधरा ने ही उनसे सुलह की और फिर से भाजपा में एंट्री करवाई। इसके बाद उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया। साल 2008 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तब किरोड़ी की पत्नी गोलमा देवी विधायक बनीं। उन्होंने पत्नी को मंत्री बनाया, लेकिन खुद सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सदन हो या सड़क मीणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा और धरने-प्रदर्शन तक किए। सड़कों पर संघर्ष के लिए ख्यात बाबा ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान भी उनकी नाक में दम किया। पूरे पांच साल किरोड़ी ने गहलोत सरकार को चेन से राज नहीं करने दिया। पेपर लीक, युवाओं के रोजगार का मुद्दे, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार, उद्योग भवन के बेसमेंट में सोना, नकदी मिलने और पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के मुद्दों को लेकर जमकर ईंट से ईंट बजाई। इस दौरान गहलोत उनसे काफी परेशान रहे। उन्होंने यहां तक कहा था कि किरोड़ी लाल नॉन इश्यू को भी इश्यू बनाने में माहिर हैं।

डॉक्टर से बने राजनेता, खूब लोकप्रिय हुए

भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। डॉक्टर से लेकर, विधायक और सांसद बनने तक का सफर उन्होंने अपनी मेहनत, जनता से जुड़ाव और जनसेवा के बूते पर तय किया। वे वर्तमान समय में राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में से एक हैं। वे युवाओं, गरीबों, पीड़ितों और शोषितों की सबसे बुलंद आवाज माने जाते हैं। वे पहली बार 1985 में दौसा जिले के महवा से भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1989 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में किरोड़ी ने दौसा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनको सवाई माधोपुर से टिकट दिया, जहां से जीत दर्ज की।

क्या पूरा हो जाएगा भाजपा का सपना!!

किंकर्तव्यविमूढ़ कांग्रेस

सुरेश व्यास ✍ वरिष्ठ पत्रकार

लोकसभा के बाद राज्यों में मिली हार का कारण भी कांग्रेस का नीति बदलना रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में वह खुद को कमजोर मानकर एनसीपी-शिवसेना (उद्धव) नीत महाअघाड़ी गठबंधन पर निर्भर हो गई। इसके पीछे उसका एक मात्र लक्ष्य भाजपा को हराना था। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को भाजपा के मुकाबले खड़ा होने का मौका मिल गया और इनकी आमने- सामने की लड़ाई में भाजपा बाजी मार ले गई।

देश में मोदी राज के उदय के बाद से कांग्रेस की हालत पतली होती जा रही है। कभी पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस आज दक्षिण भारत तक सिमट पर रह गई है। उत्तर, पश्चिम व पूर्वोत्तर राज्यों में एक-एक कर कांग्रेस के किले ऐसे ढहे कि आज खण्डहर के रूप में भी पहचानने में नहीं आ रहे। कांग्रेस के लिए मुफीद रहे राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी उसके हाथ से निकल गए और हार का असर यह हुआ कि इन प्रदेशों में भी कांग्रेस अब तक 'कोमा' से निकल नहीं पा रही।

जिस तरह के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, इन्हें देखकर कांग्रेस फिलहाल तो अपने पैरों पर दुबारा खड़े होने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए भी खुद उससे टूटकर अलग हुए दलों और क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है और मौका मिलने पर ये क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस को आंख दिखाने में शर्म नहीं कर रही। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का भाजपा का सपना कांग्रेस खुद ही पूरा कर लेगी, या उसे नई दिशा देने के लिए कोई चमत्कारिक नेतृत्व सामने आएगा।

अपना खोया अस्तित्व हासिल करने के लिए देश की 'ग्रांड ओल्ड पार्टी' कांग्रेस खुद पशोपेश में है। वह भाजपा को हराने के लिए क्षेत्रीय या कभी सहयोगी रही पार्टियों से किनारा करने का आत्मघाती कदम उठाती है तो कभी क्षेत्रीय दलों को नागवार फैसले कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। रही सही कसर पार्टी के नेताओं के बयान पूरी कर देते हैं।

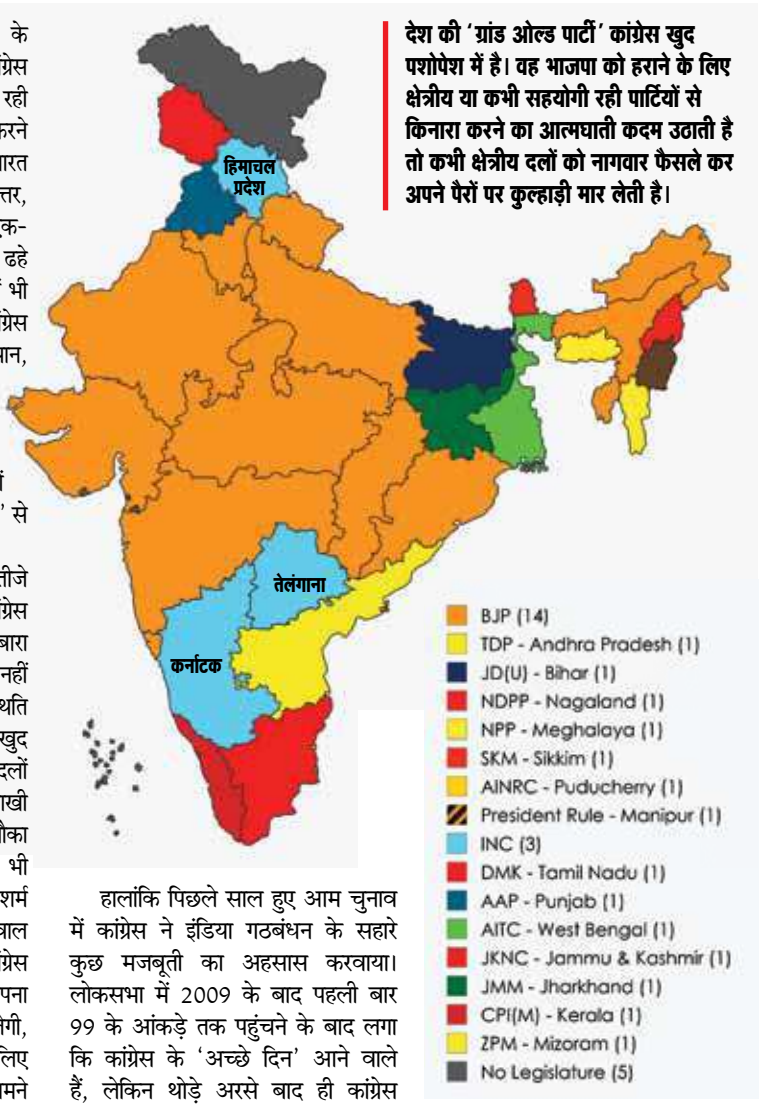

देश की 'ग्रांड ओल्ड पार्टी' कांग्रेस खुद पशोपेश में है। वह भाजपा को हराने के लिए क्षेत्रीय या कभी सहयोगी रही पार्टियों से किनारा करने का आत्मघाती कदम उठाती है तो कभी क्षेत्रीय दलों को नागवार फैसले कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है।

हालांकि पिछले साल हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहारे कुछ मजबूती का अहसास करवाया। लोकसभा में 2009 के बाद पहली बार 99 के आंकड़े तक पहुंचने के बाद लगा कि कांग्रेस के 'अच्छे दिन' आने वाले हैं, लेकिन थोड़े अरसे बाद ही कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस और उसके समर्थकों को ऐसा झकझोरा कि अब तक न नेता और न ही पार्टी संगठन इस झटके से उबर पाया है। इधर, लोकसभा चुनाव के बाद समर्थकों की नजर में हीरो बनकर उभरे राहुल गांधी की छवि फिर कमजोर हुई और एक बार फिर उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं।

दरअसल, लोकसभा के बाद राज्यों में मिली हार का कारण भी कांग्रेस का नीति बदलना रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में वह खुद को कमजोर मानकर एनसीपी-शिवसेना (उद्धव) नीत महाअघाड़ी गठबंधन पर निर्भर हो गई। इसके पीछे उसका एक मात्र लक्ष्य भाजपा को हराना था। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को भाजपा के मुकाबले खड़ा होने का मौका मिल गया और इनकी आमने-सामने की लड़ाई में भाजपा बाजी मार ले गई। इस कारण बंगाल, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर कांग्रेस से छिटकते गए।

हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों के नतीजे तो यही बताते हैं कि खुद अपनी गलतियों की वजह से 'एंटी इनकमबेंसी' के बावजूद फायदा नहीं उठा पाई और हरियाणा जैसे राज्य में भाजपा को सीधा फायदा मिल गया। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी (आप) को नहीं साध सकी और दोनों पार्टियों के वोट बंटने के कारण भाजपा सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो गई। फिर दिल्ली में कांग्रेस ने आप से दूरी बनाई और भाजपा का 27 साल पुराना सत्ता का वनवास खत्म हो गया, जबकि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के सामने वामदलों से समझौता करने से कांग्रेस जीरो में सिमट गई और भाजपा का वोट शेयर अचानक बढ़ने से उसे कभी घोर दक्षिणपंथ विरोधी राज्य रहे बंगाल में अब तक की सबसे ज्यादा 70 सीटें मिल गई और 2021 के विधानसभा चुनाव में वामदलों के साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई में शून्य पर सिमटना पड़ा। वोट शेयर भी 12.2 फीसदी घटकर 2.93 फीसदी हो गया, जबकि 2016 के चुनाव में उसे 44 सीटें मिली थी। इस हार का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा और कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही हासिल कर सकी। ऐसी ही स्थिति और समीकरणों के कारण यूपी, बिहार, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का जनाधार खिसकता जा रहा है।

ऐसे में कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे और कार्यशैली पर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है, मगर वह तय नहीं कर पा रही कि उसे किस रास्ते पर जाना है। कांग्रेस को यह पता है कि साल 2029 में होने वाले आम चुनाव से पहले वह राज्यों में मजबूत नहीं हुई तो उसे फिर केंद्र की सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है, ऐसे में वह अभी से राज्यों में जनाधार बढ़ाने के लिए हाथ पैर मार रही है।

नजर राज्यों में मजबूती पर

आने वाले दिनों में पहले बिहार और फिर असम और गुजरात में चुनाव होने हैं। इसके बाद उत्तरप्रदेश में चुनाव होंगे। वैसे तो कांग्रेस ने अभी से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में प्रदेश प्रभारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया गया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी साफ नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते पर खड़ा होने की कोशिश करेगी या फिर गठबंधन के चलते फिर कोई सियासी समझौता करना पड़ता है। फैसलों से तो कांग्रेस आक्रामक होने के संकेत दे रही है, लेकिन राज्यों में ग्राउंड लेवल पर इसके दूरगामी परिणाम पार्टी के पक्ष में आने पर फिलहाल तो संदेह ही किया जा सकता है।

बिहार का उदाहरण लें तो अल्लावरू कृष्णा को नया प्रभारी बना दिया, जबकि बिहार में गठबंधन की धुरी माने जाने वाले लालूप्रसाद यादव के नजदीकी माने जाने वाले प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। इसके बाद अल्लावरू ने राहुल के इशारे पर फायर ब्रांड छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा दिया और उनकी 'पलायन रोको, रोजगार दो' यात्रा को हरी झंडी दे दी। इसके लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहकर अखिलेश ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इतना ही नहीं, नाराजगी के बीच ही राहुल के कहने पर कांग्रेस ने अखिलेश को बदलकर उनकी जगह दलित चेहरे के रूप में विधायक व पूर्व मंत्री राजेश कुमार को कमान सौंप दी गई।

सियासी पंडित हालांकि इसे कांग्रेस की बिहार में 'बैक-टू द रूट्स' के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि दलित चेहरा ऐसे वक्त में सामने लाया गया है जब भाजपा, जदयू और राजद जैसे बड़े दलों ने भी प्रदेश पार्टी की कमान दलित को सौंपने से परहेज कर रखा है।

वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह की राय में कांग्रेस का यह फैसला सतही तौर पर तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जरिए वह एक बार फिर अपना जनाधार वापस हासिल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन परिणाम नए प्रदेशाध्यक्ष की न सिर्फ कांग्रेस संगठन, बल्कि अन्य सहयोगी दलों में स्वीकार्यता पर निर्भर करेंगे। वे बताते हैं कि साल 1990 तक बिहार में सवर्ण, दलित और मुस्लिम मतों की बदौलत एक छत्र राज किया, लेकिन धीरे-धीरे ये वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से खिसकता गया। यूं देखा जाए तो कांग्रेस आज बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद की मेहरबानी पर चुनावी राजनीति में खड़ी नजर आती है। अब कांग्रेस को फैसला करना है कि वह अकेले खुद का खोया वजूद हासिल करेगी या लालू और गठबंधन के हाथों में खेलेगी। कारण मौजूदा दौर में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है।

जानकारों का कहना है कि अभी बिहार में चुनाव छह-सात माह बाद होंगे और इस दौरान परिस्थितियां कितनी बदलेगी, सबकुछ उसी पर निर्भर करेगा। फिलहाल कांग्रेस अपने पत्ते खोलने से बच रही है, लेकिन लालू ने पहले ही सीएम फेस सामने कर दिया है। कांग्रेस ने पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। कहा जा रहा है कि इस बार लालू यादव कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस को अपनी जमीन तैयार करनी होगी और लोगों तक पहुंचना होगा। प्रदेशाध्यक्ष की कमान दलित को सौंपने के पीछे यही बड़ा राज है। पार्टी का मानना है कि वह राजेश कुमार के जरिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के कब्जे वाले दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। बिहार में लगभग बीस प्रतिशत दलित हैं, जो परम्परागत रूप से सत्ता के साथ ही रहना पसंद करते हैं। भाजपा और जदयू के पास भी कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। ऐसे में शायद यह बदलाव बदलाव कुछ काम कर जाए।

दिल्ली नहीं, जिलों से चले कांग्रेस

खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस ब्लॉक से जिला संगठनों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली में बुलाई गई 700 जिलाध्यक्षों की बैठक इसी का संकेत है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि इसके पीछे पार्टी की सोच है कि कांग्रेस दिल्ली से नहीं, जिलों से चले। यानी पार्टी जिला कांग्रेस कमेटियों को केंद्रीय भूमिका देने का इरादा रखती है। नीति यह है कि पार्टी में जिला कांग्रेस कमेटियों का महत्व बढ़ेगा और वे उम्मीदवार चुनने और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में मदद करेंगे।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार बेलगावी के 'नव सत्याग्रह बैठक' में एक प्रस्ताव पारित कर साल 2025 संगठन का वर्ष घोषित कर 'संगठन सृजन कार्यक्रम' की घोषणा की गई थी। उसी संदर्भ में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। इस योजना के लिए गुजरात और मध्यप्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में चुना गया है। इसका क्रियान्वयन दो साल बाद चुनाव में जाने वाले गुजरात से शुरू होगा। दोनों राज्यों में संगठनात्मक सुधार के लिए एक खाका तैयार किया जा रहा है, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले अधिवेशन में पेश किया जा सकता है। इसके अनुरूप विधानसभावार पर्यवेक्षक तैनात होंगे, जो ब्लॉक और पंचायत स्तर के प्रमुखों के नाम बताएंगे। साथ ही पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इसी आधार पर पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू कर देगी।

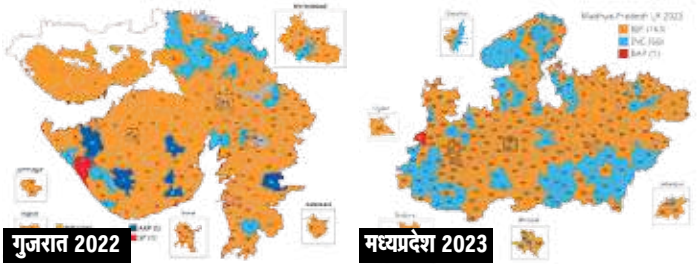

जानकारों के अनुसार मध्यप्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। कांग्रेस गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से केवल 17 और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 26 में से केवल एक सीट जीत सकी है। मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 में से 66 सीटें मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 29 में से सिर्फ एक सीट मिल सकी। दोनों नतीजों के लिए कमजोर संगठन को बड़ी वजह माना गया। इसी वजह से इन दोनों राज्यों को मॉडल स्टेट मानकर काम शुरू किया जा रहा है।

वैसे औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश व छत्तीसगढ़ में भी संगठन को तरजीह देने के कदम उठाए हैं। मिशन-2027 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यूपी में बनाए गए 75 नए जिलाध्यक्षों में 64 फीसदी हिस्सा अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को देकर इन वर्गों में वापस पैठ जमाने का संकेत दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी नए बनाए गए जिलाध्यक्षों में इन वर्गों की पूरी भागीदारी है।

गुटबाजी का कोई पार नहीं

कांग्रेस की लगातार चुनावी पराजयों के पीछे नेताओं की आपसी गुटबाजी और खींचतान को भी अहम कारण माना जाता है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव इसके बड़े उदाहरण के रूप में आज भी इसकी गवाही दे रहे हैं। और तो और, चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने न तो उबरने की नए सिरे से कोई कोशिश की और न ही गुटबाजी व आपसी खींचतान को खत्म करने के ठोस प्रयास सामने आए।

सियासी पंडितों का कहना है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार गई, आम कार्यकर्त्ता बाहर ही नहीं निकल रहा। न ही संगठन स्तर पर कोई प्रभावी गतिविधि नजर आती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से कुछ हलचल जरूर मची थी, लेकिन विधानसभा उप चुनाव के नतीजों के बाद तो बड़े से बड़े नेता बंगलों में कैद होकर रह गए हैं। राज्य में बहुमत के बूते भाजपा का राज जरूर है, लेकिन सदन के अंदर और बाहर उसे विरोध भी झेलना पड़ रहा है। खुद भाजपा के कई नेता, सरकार के कई मंत्री और विधायक भी सरकार से खफा हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास विपक्ष की भूमिका में जान डालने का मौका है, लेकिन वह तो खुद अपने ही बोझ तले दबी जा रही है।

प्रदेश की कांग्रेसी राजनीति के पावर सेंटर रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी सीन से नदारद हैं। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे कुछ नेता ताकतवर दिखाई तो देते है, लेकिन पिक्चर अब भी बड़े नामों से ही चल रही है और बड़े नाम भी अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को हांकते हैं, जिसमें पार्टी कम और व्यक्ति ज्यादा मजबूत होता है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व भी आंखें मूंदकर ही बैठा है, शायद उसे भी 2028 के विधानसभा चुनावों का इन्तजार हो। यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, जहां सत्ता जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी-सीबीआई के जाल से ही बाहर नहीं आ पा रहे और उनके प्रतिद्वन्द्वी टीएस सिंह देव फ्रेम से ही बाहर है।

नब्ज और नेतृत्व पर भी सवाल

इतिहास बताता है कि नेहरू-गांधी परिवार ही कांग्रेस का एक तरह से पर्याय रहा है। कोई भी नेता इस परिवार को चुनौती नहीं दे पाया। ये चीज आज के दौर में भी दोहराई जा रही है। कहने को तो कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन कांग्रेस के फैसलों पर छाप आज भी सोनिया और राहुल गांधी की ही नजर आती है। अब तीसरा पावर सेंटर प्रियंका गांधी भी है। खड़गे का नम्बर इनके बाद आता है। खरगे कुछ करना चाहे तो भी सहमति इन तीनों की जरूरी है। एआईसीसी के महासचिवों के चयन और काम बांटने से लेकर कांग्रेस की नई आने वाली संगठनात्मक रणनीति में भी यह परिलक्षित हो चुका। ऐसे में आम कार्यकर्ता भी गांधी-नेहरू परिवार को ही कांग्रेस मानने को मजबूर है और जनता के सामने मोदी- शाह की जोड़ी ने इस नरेटिव का इतना मजबूत कर दिया है कि वह भी कांग्रेस की किसी गारंटी पर मुश्किल से भरोसा करती है। कांग्रेस को लम्बे समय से कवर कर रही एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कांग्रेस को तो राहुल ने हाइजैक कर रखा है। वे कांग्रेस के घोड़े को कभी बारात का तो कभी रेस का घोड़ा बता देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कार्यकर्ता या आम जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।

गुजरात के पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि राहुल की बात सुनने में तो सही लगती है कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ना पड़ेगा, तभी जनता उन पर भरोसा करेगी, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जनता के कांग्रेस पर भरोसा नहीं करने का एक कारण सत्ता-संगठन में गांधी परिवार की पंसद-नापसंद को मिलने वाली तवज्जो भी है। सही नेताओं को काम नहीं करने देने के कारण ही गुजरात में कांग्रेस तीन दशक से सत्ता में नहीं आ पा रही, बाकी गुजरात के लोग तो अच्छे विकल्प का इंतजार कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला समर्थन इसका उदाहरण है।

> इसके अलावा कांग्रेस चुनाव के दौरान लोगों की नब्ज भी नहीं पकड़ पा रही। आज सोशल मीडिया के दौर में मिनटों में माहौल बनता और बिगड़ता है। बंद कमरे की बातें तक बाहर आ जाती है, लेकिन कांग्रेस नब्ज पकड़ने में हर बार नाकाम हो जाती है। कभी वह अल्पसंख्यक हितैषी बनकर बहुसंख्यक वर्ग का कोपभाजन बन जाती है तो कभी उदार हिन्दुत्व की राह पकड़ कर पारम्परिक वोट बैंक भी गंवा बैठती है। चुनावों के वक्त में कांग्रेस नेताओं के बयान मुंह में आया निवाला छिन जाने का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही प्रयागराज में सम्पन्न महाकुम्भ के मौके पर 'गंगा में डुबकी से क्या गरीबी मिट जाएगी', 'क्या इससे लोगों का पेट भर जाएगा', जैसे खरगे के बयान क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? राम मंदिर के मौके कांग्रेस का बेरुखी क्या उसे फायदा दे सकती है? वैसे इस तरह के बयानों से कांग्रेस ने भले ही किनारा किया हो, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस की चुनावी पराजयों में ये बयान भी एक फैक्टर तो बनते ही हैं।

कांग्रेस का पुनरुत्थान कैसे हो, इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक व लेखक सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि कांग्रेस स्वयं में सुधार की क्षमता पूरी तरह खो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तकलीफ सिर में है और इलाज पेट का किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जीत का श्रेय गांधी परिवार को और हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कांग्रेस की आदत रही है। उसे खुद अपने बारे में आत्मावलोकन करना पड़ेगा, बाकी संगठन और कार्यकर्ताओं को सम्मान की बातें कागजों में ही अच्छी लगती है।

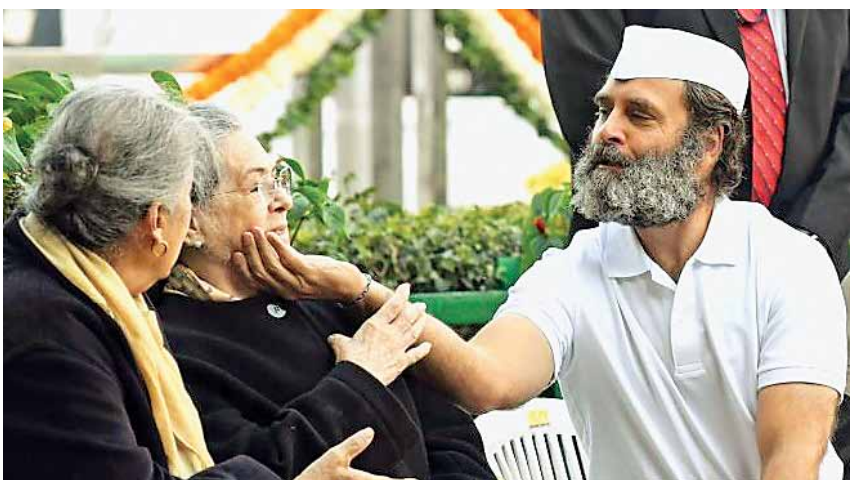

ऐतिहासिक तथ्य भी गवाही नहीं देते सुमन के बयान की

बाबर को हरा चुके थे राणा सांगा

विवेक भटनागर शोध निदेशक
प्रताप गौरव केंद्र, उदयपुर

विवाद सांगा के बाबर की मदद करने के तथ्य पर है। कहा जाता है कि बाबर ने महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी। इसके लिए उसने अपना दूत भी मेवाड़ राज दरबार में भेजा, लेकिन सांगा ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत सरहिंद के हाकिम दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई ने बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी।

मेवाड़ के प्रतापी शासक रहे राणा सांगा (महाराणा संग्राम सिंह प्रथम), जिन्हें अपने अदम्य साहस और लड़ाइयों में एक भुजा, एक आँख, एक टांग गँवाने और शरीर पर अस्सी घाव झेलने की वजह से इतिहास में सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है, इन दिनों फिर चर्चा में है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के भाषण में राणा सांगा को बाबर की मदद करने के कारण 'गद्दार' कहे जाने से देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। इनके मुताबिक राणा सांगा ने बाबर की मदद तो कभी नहीं की, बल्कि उन्होंने फरवरी 1527 ई. में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में मुगल आक्रान्ता बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता था।

17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध मैदान में सिर में तीर लगने से घायल हुए राणा सांगा बसवा (दौसा-राजस्थान) में स्वस्थ होकर फिर युद्ध के मैदान में पहुंचे और बैतवा नदी के तट को जीतते हुए कालपी तक पहुंच गए। जहां 30 जनवरी 1528 को उन्हें जहर देकर मार दिया गया। इतिहास बताता है कि खानवा के धावे के बाद बाबर ने आगे कोई क्षेत्र नहीं हथियाया, लेकिन सांगा ने शक्ति संचय कर पुनः अपने क्षेत्रों को अधिकार में ले लिया।

मौदूदा विवाद सांगा के बाबर की मदद करने के तथ्य पर है। कहा जाता है कि बाबर ने महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी। इसके लिए उसने अपना दूत भी मेवाड़ राज दरबार में भेजा, लेकिन सांगा ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत सरहिंद के हाकिम दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई ने बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी।

हकीकत में बाबर की मदद करने की बात कुछ इतिहासकारों की मनगढ़ंत कहानी है, जिसका कोई प्राथमिक प्रमाण किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन दौलत खां लोदी की ओर से बाबर को लिखे गए पत्र की प्रतियां उपलब्ध हैं।

अफगानी इतिहासकार अहमद यादगार की पुस्तक तारीख-ए-सल्तनत-ए-अफगान में लिखा गया है कि बाबर काबुल में अपने बेटे कामरान के निकाह की तैयारी में मसरूफ था। उस समय दिल्ली में सत्तासीन सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार था। सुल्तान ने अपने चाचा को देहली बुलाया। इस पर दौलत खां खुद नहीं जाकर अपने बेटे दिलावर खान को भेज देता है। इस नाफरमानी से चिढ़कर सुल्तान इब्राहिम लोदी ने चचेरे भाई दिलावर खां को गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया। दिलावर वहां से जान बचा कर भागकर लाहौर पहुंचा। इस पर दौलत खां लोदी को आगे की परेशानी दिखाई देती है। वह जानता था कि सुल्तान उसे नहीं बख्शेगा। ऐसे में इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से उतार कर उस पर कब्जा करना ही एक साधन बचा था, जो उसे और उसके बेटे को बचा सकता था।

दौलत खां लोदी ने तत्काल अपने बेटे दिलावर और आलम खान को बाबर से मिलने काबुल रवाना किया। दिलावर ने काबुल में पहुंच कर चारबाग में बाबर से मुलाकात की। बाबर ने उस से पूछा- तुम ने सुल्तान इब्राहिम का नमक खाया है तो ये गद्दारी क्यों? इस पर दिलावर खां ने जवाब दिया कि लोदीयों के कुनबे ने चालीस साल तक दिल्ली की सत्ता संभाली है लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोदी सभी अमीरों के साथ बदसलूकी करता है। पच्चीस अमीरों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। किसी को फांसी पर लटका कर तो किसी को जला कर मार डाला। अब सभी मीर उसके दुश्मन बन गए हैं और उसकी खुद की जान खतरे में है। उसे अनेक अमीरों ने बाबर से मदद मांगने भेजा है। निकाह में मसरूफ बाबर ने एक रात की मोहलत मांगी और चार बाग में इबादत की, 'ए मौला, मुझे राह दें कि हिन्द पर हमला कर सकूं। अगर हिन्द में होने वाले आम और पान उसे तोहफे में मिलते हैं तो वह मान लेगा कि रब चाहता है कि वो हिन्द पर आक्रमण करें।

अगले दिन दौलत खां के दूतों ने उसे शहद में डूबे अधपके आम भेंट किए। ये देख बाबर उठ खड़ा हुआ और आम की टोकरी देख सजदे में झुक गया। उसने अपने सिपहसालारों को हिन्द पर कूच करने का हुक्म दिया। वहीं बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में यह रिकॉर्ड छिपा कर सांगा की ओर से पत्र लिखने और हिन्द पर आक्रमण करने के न्यौते का जिक्र करता है। इस प्रकार की कहानी सिर्फ बाबरनामा में ही मिलती है और कहीं नहीं। इसलिए बाबर का रिकॉर्ड सत्य नहीं माना जा सकता है। जबकि दौलत खां के दूतों का काबुल जाना और उसका पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है।

वहीं तजकिरत-उल वाकियात में हुमायूं का लेखक जौहर आफताबची और जहांगीर के काल में तारीख-ए-मखजने अफगना का लेखक नियामतुल्लाह दोनों ही दौलत खां लोदी के पत्र लिखने की बात का वर्णन करते हैं। जहांगिर के दरबार में 1609 में काम करने वाले नियामतउल्ला के लेखन में दिल्ली के अफगान सुल्तानों तथा अफगानी कबीलों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। इस ग्रन्थ में सुल्तान बहलोल लोदी से लेकर इब्राहीम लोदी तक के समय का वर्णन मिलता है।

संदर्भ...

1. बाबरनामाः लेनपुन अनुदित।
2. एलियट एंड डाउसन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम पांच में तारीख-ए-सल्तनत-ए-अफगान लेखक अहमद यादगार।
3. तजकिरत-उल-वाकियात लेखक जौहर आफताबची। 4. तारीख-ए-मखजन-ए-अफगान लेखक नियामतउल्ला।

कब्र में ही रहने दें दफ़न

फिल्म 'छावा' से गरमाया औरंगजेब के मकबरे का मुद्दा, सिनेमा को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी

मनीष गोधा ✍ वरिष्ठ पत्रकार

फिल्म छावा को मिली सफलता और प्रशंसा के बीच औरंगजेब की तारीफ ने अब तक दफ़न पड़े औरंगजेब के मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया। हालात तो ये हो गए कि उसके बाद इस मकबरे को हटा कर यहां शौचालय बनाने जैसे बयान आ गए। औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग को लेकर 17 मार्च को नागपुर में एक प्रदर्शन चल रहा था, जो ना जाने कब साम्प्रदायिक हिंसा में बदल गया और देखते ही देखते घरों पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी हो गई।

मुगलों, विशेषकर औरंगजेब और मराठों के बीच का संघर्ष भारत के इतिहास का वो हिस्सा है जिसने हमारे देश में हिन्दू राष्ट्रवाद के विचार को पनपाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यह विचार और इसके परिणाम कितने सही और गलत हैं, इसे लेकर लम्बी बहस की जा सकती है। बल्कि देखा जाए तो यह बहस चल भी रही है, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, उसने यह साबित कर दिया कि औरंगजेब के प्रति नफरत मराठाओं में आज भी कम नहीं हुई है। यह भी साबित हुआ कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हम आगे भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर कुछ मान्यताओं और धारणाओं को हम आज भी छोड़ नहीं पा रहे हैं।

औरंगजेब की बरसी यानी तीन मार्च को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी हाल में प्रदर्शित हुई फिल्म 'छावा' पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए औरंगजेब की तारीफ कर देते हैं और छत्रपति सम्भाजी महाराज तथा औरंगजेब की बीच हुए संघर्ष को धार्मिक नहीं, बल्कि सत्ता और संपत्ति का संघर्ष बताते हुए कहते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं। मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में फिल्म छावा को मिली सफलता और प्रशंसा के बीच औरंगजेब की तारीफ ने अब तक दफ़न पड़े औरंगजेब के मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया। हालात तो ये हो गए कि उसके बाद इस मकबरे को हटा कर यहां शौचालय बनाने जैसे बयान आ गए। औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग को लेकर 17 मार्च को नागपुर में एक प्रदर्शन चल रहा था, जो ना जाने कब साम्प्रदायिक हिंसा में बदल गया और देखते ही देखते घरों पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी हो गई। करीब 33 पुलिसकर्मी और कुछ आम लोग घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया।

दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब का मकबरा नागपुर में है ही नहीं। यह औरंगाबाद से करीब 24 किलोमीटर दूर एक गुमनाम जगह खुल्दाबाद में है। अब आप देखिए कि दिल्ली का सुल्तान औरंगजेब और उसका मकबरा दिल्ली में ना हो कर उसी महाराष्ट्र में जहां शायद उससे सबसे ज्यादा नफरत की जाती रही है और यह नफरत महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित भी करती रही है।

बहरहाल, मौजूदा विवाद पर आते हैं, जो देखा जाए तो आज का विवाद है ही नहीं। यह महाराष्ट्र की राजनीति का पुराना मुद्दा है। औरंगजेब के इस मकबरे को हटाने की मांग शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे भी उठाते रहे हैं और बताते हैं कि इसे लेकर अस्सी के दशक में महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा भी होती रही है। मौजूदा विवाद उस पुराने मुद्दे का विस्तार भर है जो माना जा रहा है कि फिल्म छावा के कारण एक बार फिर चर्चा में आ गया और देश में मुगलिया शासन की याद दिलाने वाले प्रतीकों को बदलने, हटाने आदि को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए लगता नही है कि यह मुद्दा जल्दी शांत होगा। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति या महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो ध्रुवीकरण को बढ़ाने वाले इस या ऐसे मुद्दों से किसी को कोई बड़ा फायदा होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह एक ही दल की स्थिर सरकारें हैं।

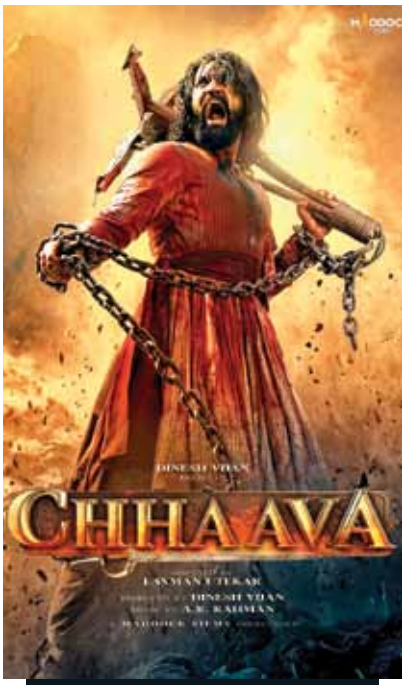

सिनेमा का इतना असर....

इस पूरे मुद्दे का एक और पहलू है जो सिनेमा से जुड़ा है। किसी फिल्म का इस तरह किसी मुद्दे को जिंदा कर देना या कहें कि भावनाओं को उद्वेलित कर देना यह बताता है कि सिनेमा को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ओनियन मेकिंग यानी मत निर्माण के अन्य साधनों की तरह सिनेमा भी एक ओपिनियन मेकर है और पूर्व में सिनेमा यह काम अलग- अलग समय पर करता भी रहा है। लेकिन, चूंकि इस माध्यम की पहुंच और प्रभावशीलता काफी है और आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, उस दौर में छोटी सी चूक की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विषयों के चुनाव में सिनेमा से जुड़े लोग इस जिम्मेदारी को समझेंगे।

औरंगजेब का मकबरा

लेकिन अब आते हैं मूल सवाल पर- क्या सच में औरंगजेब का मकबरा या ऐसे ही अन्य विषय आज के दौर में हमारे लिए कोई मुद्दा होना चाहिए? इस सवाल का जवाब अलग-अलग दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य में हां भी हो सकता है और ना भी। हम दोनों पक्ष आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और चूंकि हर व्यक्ति अपनी अलग सोच रखता है, इसलिए इस सवाल का जवाब भी आप अपनी सोच के हिसाब से तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पहले हां की बात करते हैं

हां, औरंगजेब की कब्र ही नहीं, बल्कि ऐसे वो तमाम मुद्दे आज भी जरूरी हैं जो उस दौर का सही इतिहास हमारे सामने लाते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि इतिहास के नाम पर हमें जो कुछ पढ़ाया जाता रहा है, उस पर एक खास किस्म की सोच हावी रही है और इसीलिए हमारे सामने लाया गया इतिहास पूरी तरह निष्पक्ष या विचारधारामुक्त नहीं कहा जा सकता है। वर्षों तक इतिहास को लेकर दूसरा दृष्टिकोण हमारे सामने आ ही नहीं पाया, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठानों पर उस खास विचारधारा के पोषक बैठे थे।

अब सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत कुछ वो भी सामने आ रहा है जो इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज तो था, लेकिन उसे सामने लाया नहीं गया, लेकिन जो हमें जानना चाहिए था। ऐसे में औरंगजेब की कब्र जैसे मुद्दों के बहाने ही सही, यदि इतिहास को लेकर दबी-छुपी जानकारियां सामने आती हैं और एक नई दृष्टि का निर्माण होता है तो होना चाहिए। अब इसे लेकर कोई यह आरोप लगाए कि इतिहास के पुनर्लेखन का प्रयास किया जा रहा है, इसे अपने हिसाब से तोड़ा- मरोड़ा जा रहा है तो उसे आरोप लगाने के बजाए अपने तथ्य सामने रखने चाहिए। सही और गलत का फैसला अपने आप हो जाएगा।

अब बात ना की

▪ वहीं इसी सवाल को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस मुद्दे या इसी तरह के अन्य मुद्दों को लेकर जिस तरह का माहौल बनता है और भावनाएं उद्वेलित होती है तो यह भी लगता है कि आखिर क्यों ना इतिहास से उतना ही लिया जाए, जितना हमें आज जरूरत है या जो आज हमारे लिए प्रासंगिक है।

▪ हम एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं और ऐसे दौर में औरंगजेब की कट्टरपंथी सोच हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती है? वो अपनी सोच के साथ दुनिया से विदा हो गया और अब शांति से अपनी कब्र में आराम कर रहा है। हम क्यों उसे और उसकी सोच को उस कब्र से निकाल रहे है? वो जहां है उसे वहीं पड़े रहने दीजिए। समय के साथ बहुत कुछ मिट जाता है।

▪ हमारे देश के 90 प्रतिशत लोग नहीं जानते है कि औरंगजेब का मकबरा खुल्दाबाद में है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। यह मकबरा कब समय की धूल का हिस्सा बन जाता हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए क्यों ना समय को अपना काम करने दिया जाए और धूल डालो जी बात पर, कहते हुए आगे बढ़ा जाए।

इतिहास होगी तारीख

प्रवीण धींगरा ✍ वरिष्ठ पत्रकार

सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष भी रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग बन रहा है। इस तिथि को चुनने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि राजस्थान दिवस का उत्सव न केवल एक प्रशासनिक आयोजन बनकर रह जाए, बल्कि यह जन-जन के जीवन में सांस्कृतिक उत्साह और एकता का संदेश लेकर आए। यह बदलाव 75 साल बाद एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है

राजस्थान के इतिहास की एक तारीख 30 मार्च। यह तारीख फिर से इतिहास होने जा रही है। वह इसलिए, क्योंकि राजनीति में प्रयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने राजस्थान के इतिहास को लेकर एक प्रयोग किया है। कलैंडर तारीख की जगह तिथि के दिन राजस्थान दिवस मनाने का। यह फैसला इसी साल लिया और लागू किया गया है, इस साल राजस्थान दिवस की कलैंडर तारीख और तिथि, दोनों एक ही दिन है। अब ऐसा संयोग राजस्थान के 100 साल होने तक महज एक बार आएगा। बाकि, 12 बार यह दिवस मार्च की अलग-अलग तारीखों तो 12 बार ही अप्रेल की अलग-अलग तारीखों में मनाना होगा। इसका असर यह भी कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस सवाल को मिटाया जाएगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। नया सवाल जरूर जुड़ सकता है। राजस्थान दिवस किस तारीख को मनाया जाता था। या, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।

अगले साल से ही बदल जाएगी तारीख

सरकार ने जब यह फैसला किया है, तब कैलेंडर की तारीख और तिथि, दोनों एक ही दिन है। लेकिन अगले साल से तिथि के दिन की तारीख अलग होनी शुरू हो जाएगी। वर्ष 2026 में हम राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाएंगे।

शतायु राजस्थान में 18 साल बाद आएगा 30 मार्च का दिन

24 साल बाद जब राजस्थान 100 साल का होगा, इस दौरान राजस्थान दिवस की कैलेंडर डेट और हिंदी तिथि एक साथ महज एक बार एक ही दिन आएगी। वह भी राजस्थान दिवस मनाने के नए फैसले के ठीक 18 साल बाद, वर्ष 2044 की तारीख 30 मार्च के दिन ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी। संयोग देखिए, इन 24 वर्ष में राजस्थान दिवस 12 साल मार्च माह में तो 12 साल अप्रेल माह में मनाया जाएगा। (तिथि काल दर्शक पंचांग के अनुसार)

सरकार की सोच

राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला की शुरूआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर में राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन से की। उन्होंने इस दौरान राजस्थान दिवस को लेकर सरकार के निर्णय के संदर्भ में कहा कि गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर भारतीय पंचाग की तिथि नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को मनाया जा रहा है। इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष भी रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग बन रहा है। इस तिथि को चुनने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि राजस्थान दिवस का उत्सव न केवल एक प्रशासनिक आयोजन बनकर रह जाए, बल्कि यह जन-जन के जीवन में सांस्कृतिक उत्साह और एकता का संदेश लेकर आए। यह बदलाव 75 साल बाद एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता था, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तय था।

इस फैसले से देखने को मिल सकते हैं कई बदलाव

राज्य सरकार के राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि पर ही मनाने के फैसले से आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, सरकार इसे आमजन का उत्सव बनाने, अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रही है, फिर भी फैसले का असर सांस्कृतिक, प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण जैसे पहलुओं पर दिखाई देगा।

पर्यटन पर असर: राजस्थान दिवस पर जयपुर और अन्य शहरों में पर्यटन विभाग द्वारा बड़े आयोजन होते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तारीख बदलने से पर्यटकों की योजना प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वे निश्चित तारीख के आधार पर यात्रा की तैयारी करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

सांस्कृतिक महत्व में वृद्धि: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष का प्रारंभ है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। इसे राजस्थान दिवस से जोड़ने से राज्य की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और लोगों में अपनी जड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। यह कदम परंपरागत मूल्यों को बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है।

त्योहारों से तालमेल: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अक्सर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन के साथ मेल खाती है, जो पहले से ही एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। इससे उत्सव का माहौल और भव्यता बढ़ सकती है, क्योंकि लोग एक साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकेंगे।

परंपरागत पंचांग का सम्मान: यह बदलाव हिंदू पंचांग को महत्व देने का संकेत देता है, जो समय को सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर मापता है। इससे लोगों में पारंपरिक समय गणना के प्रति रुचि बढ़ सकती है।

तारीख में अनिश्चितता: तिथि चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होती है और यह हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए, 2025 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, लेकिन अगले साल यह 19 मार्च एवं उसके बाद के साल में कोई अन्य तारीख होगी। इससे पहले से निर्धारित 30 मार्च की ऐतिहासिक स्थिरता प्रभावित होगी, और हर साल आयोजन की योजना बनाने में भ्रम या असुविधा हो सकती है।

प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयां: सरकारी और निजी क्षेत्र में छुट्टियां, कार्यक्रम और तैयारियां आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित होती हैं। तिथि के अनुसार बदलाव से हर साल तारीख तय करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। स्कूलों, कार्यालयों और पर्यटन से जुड़े आयोजनों की योजना में जटिलता बढ़ सकती है।

सार्वजनिक स्वीकार्यता: लंबे समय से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा रही है। अचानक बदलाव से कुछ लोग इसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, खासकर वे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आदी हैं या धार्मिक तिथियों से कम जुड़ाव रखते हैं।

बात इतिहास की....

जोधपुर का राजस्थान में विलय

जिस दौर में राजस्थान का गठन हो रहा था, उस दौर की जोधपुर से जुड़ी ऐतिहासिक घटना आज भी याद की जाती है। आजादी के समय देश में 562 रियासतें थी। अंग्रेजी हुकुमत ने इन्हें भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था। उस समय जोधपुर रियासत के महाराजा हनवंत सिंह थे। मोहम्मद अली जिन्ना की नजर जोधपुर पर थी और वे इसे पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहते थे। इस दौरान प्रयागराज के कमिश्नर सीआर वेंकटचार का जोधपुर से नाता जुड़ने जा रहा था। वर्ष 1945 में जोधपुर में अंग्रेज अफसर डोनाल्ड फील्ड प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी दमनकारी नीतियों से लोगों में नाराजगी थी। जयनारायण व्यास ने पंडित नेहरू को पत्र लिखकर डोनाल्ड फील्ड की शिकायत की थी। पत्र में लिखा था कि डोनाल्ड फील्ड जनरल डायर की तरह काम कर रहा है। जयनाराण व्यास की चिट्ठी पर नेहरू, शेख अब्दुल्ला और इंदिरा के साथ अक्टूबर, 1945 में जोधपुर आए थे। तब उन्होंने जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह से भी मुलाकात की थी। नेहरू वेंकटचार से एक बार मिल चुके थे। ऐसे में पंडित नेहरू ने महाराजा को सलाह दी कि डोनाल्ड फील्ड को पीएम की पोस्ट से हटा देना चाहिए। उम्मेद सिंह ने नेहरू से सहमति तो जताई लेकिन पूछा कि डोनाल्ड फील्ड की जगह कौन लेगा। तब पंडित नेहरू ने इलाहाबाद के कमिश्नर सी एस वेंकटाचार का नाम लिया। नेहरू की सिफारिश पर सीएस वेंकटाचार को डोनाल्ड फील्ड की जगह पर जोधपुर का दीवान (प्रधानमंत्री) बनाया गया।

इतिहासकार लिखते हैं कि 5 अगस्त 1947 को जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में जिन्ना ने हनवंत सिंह को कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके दिया था और कहा कि जो भी शर्तें हो लिख लीजिए, वे सब मान लेंगे। बस, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ। यह बात तत्कालीन जोधपुर के दीवान (प्रधानमंत्री) सीएस वेंकटाचार तक पहुंची तो उन्होंने सरदार पटेल को पत्र लिखकर जोधपुर के भारत से अलग होने की आशंका जताई। तब सरदार पटेल ने हनवंत सिंह को दिल्ली बुलाया। पटेल ने माउंटबेटन के साथ मिलकर हनवंत सिंह को समझाया, इसके बाद जोधपुर भारत में शामिल हुआ। इसके बाद वेंकटचार कुछ दिनों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने और वेंकटचार के बाद जोधपुर के ही जयनारायण व्यास ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

कोटा, एक जिद्दी शहर

▪ हालातों से लड़कर गढ़ रहा नई परिभाषा ▪ मॉडल सिटी बनाने में जुटे हैं शहरवासी

राजस्थान टुडे ब्यूरो ✍ कोटा

प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ अब बात करें यहां के आमजन की तो कोटा का हर व्यक्ति इन दिनों अपने स्तर पर कोटा के लिए बेहतर प्रयास में जुटा है। यहां कोटा स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसायटी द्वारा कोटा जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोटा केयर्स अभियान के तहत अलग-अलग हित धारक अपने-अपने क्षेत्रों में नवाचार कर रहे हैं। हॉस्टल संचालकों ने स्टूडेंट्स की शिकायतों और उनकी परेशानियों को देखते हुए अब कॉशन मनी और सिक्योरिटी राशि लेना बंद कर दिया है।

देश-दुनिया में मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी, आईआईटी-जेईई और नीट के परिणामों के साथ स्टूडेंट्स सुसाइड के लिए चर्चा में रहने वाला शहर कोटा एक बार फिर नई कहानी लिखने के लिए जिद लिए हुए है। यह जिद नई परिभाषा गढ़ने की है। अनुभव से सीखने की है और विरासत को और आगे ले जाने की है। चम्बल के पानी की तासीर कहें या यहां के लोगों की मेहनत की पराकाष्ठा, इतिहास में देखें तो कोटा ने जब-जब जिद पाली है कुछ करके दिखाया है।

एक ऐसा शहर जहां कोचिंग होगी, कॅरियर होगा, लेकिन इन सबसे पहले केयर होगी

अब यहां के लोगों ने कोशिश शुरू की है कोटा को मॉडल सिटी बनाने की, जहां कोचिंग और करियर तो होगा, लेकिन इससे पहले होगी केयर। कोटा को अब केयर सिटी बनाने की कोशिश है। यहां न सिर्फ कोचिंग संस्थान और हॉस्टल्स, वरन जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और हर शहरवासी एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। इसके तहत यहां 'कोटा केयर्स और कामयाब कोटा' अभियान चलाया जा रहा है।

कोटा के कलक्टर संभवतः इस देश के पहले ऐसे कलक्टर होंगे जो एक शिक्षक की तर्ज पर कक्षाओं में जा रहे हैं और देशभर के बच्चों से बात कर रहे हैं। वे अब तक 25 हजार से अधिक स्टूडेंट्स से सीधे संवाद कर चुके हैं और खुद के उदाहरण से समझा रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, दिनचर्या, सोच, स्वभाव को कैसे बदलना है। पहले नीट और फिर यूपीएससी क्रेक करने वाले जिला कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी बच्चों को फिजिक्स, कैमेस्ट्री के साथ सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, अटेंशन स्पान, मेंटल हेल्थ, स्लीपिंग लूप सहित कई ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है। क्लास के अलावा उन्होंने 'डिनर विद कलक्टर' अभियान शुरू किया हुआ है, जिसमें हॉस्टल्स में जाकर स्टूडेंट्स के साथ डिनर करते हैं और इस दौरान उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। बच्चों को मोटिवेट करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान देते हैं। जिला कलक्टर डॉ. गोस्वामी ने पिछले दिनों देश के अभिभावकों के नाम एक ओपन लेटर भी लिखा, जिसमें यहां आने वाले स्टूडेंट्स के अभिभावकों को विश्वास दिलाया कि यहां उनके बच्चे सुरक्षित वातावरण में अपने सपने पूरे करने के लिए तैयारी करेंगे।

इसी तरह डॉक्टर बनने के बाद आईपीएस के रूप में भूमिका निभा रहीं कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन भी कोटा में स्टूडेंट्स की मेंटोर के रूप में काम कर रही हैं। कोटा संभवतः ऐसा पहला शहर है, जहां थड़ियों पर मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए बने कानूनों के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए पुलिस द्वारा 'के-सॉस' (कोटा-सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स) एप जारी किया गया। 'दरवाजे पर दस्तक' अभियान के तहत स्टूडेंट्स को पैनिक बटन के बारे में बताया जा रहा है। इस एप के पैनिक बटन दबाते ही पुलिस तुरंत स्टूडेंट्स की मदद के लिए पहुंच रही है। यही नहीं स्टूडेंट्स में सुसाइड व सेल्फ हार्म जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मेटा के साथ टाइ-अप किया गया है, जिससे सोशल मीडिया पर इस तरह के शब्द काम में लेने के साथ ही स्टूडेंट्स की पहचान कर ली जाती है और उसे काउंसलिंग दी जाती है।

इसके साथ ही कोटा के जनप्रतिनिधि भी कोटा में आने वाले स्टूडेंट्स और पेरेन्ट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। पिछले दिनों ही स्थानीय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के अभिभावकों को आह्वान करते हुए कहा कि कोटा में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है और यहां जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। आने वाले समय में कोटा देश में एक मॉडल सिटी के रूप में सामने आएगा, जहां हर सुविधा और हर व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए होगी। उन्होंने बच्चों से बात करते हुए भी कहा है कि हम आपके अभिभावक हैं, जो बच्चे अपने घर से दूर कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वे निश्चिंत होकर पढ़ें। यहां किसी भी तरह की समस्या होगी तो उसे हम देखेंगे।

प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ अब बात करें यहां के आमजन की तो कोटा का हर व्यक्ति इन दिनों अपने स्तर पर कोटा के लिए बेहतर प्रयास में जुटा है। यहां कोटा स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसायटी द्वारा कोटा जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोटा केयर्स अभियान के तहत अलग-अलग हित धारक अपने-अपने क्षेत्रों में नवाचार कर रहे हैं। हॉस्टल संचालकों ने स्टूडेंट्स की शिकायतों और उनकी परेशानियों को देखते हुए अब कॉशन मनी और सिक्योरिटी राशि लेना बंद कर दिया है। अब स्टूडेंट्स आसानी से एक से दूसरे हॉस्टल ज्वाइन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बेहतर सुविधाएं तथा केयरिंग के लिए हॉस्टल में अटेंडेंस, मेडिकल फेसिलिटी और अन्य कई व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। कोटा में करीब 4 हजार हॉस्टल्स हैं और इनमें 25 हजार से अधिक कर्मचारी हैं।

इसी तरह शहर के 10 हजार से अधिक ऑटो चालकों की ऑटो यूनियन्स ने स्टूडेंट्स को सुरक्षित यात्रा करवाने की पहल की है। ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने एक किराया निर्धारित कर लिया है, जिससे अधिक चार्ज अभिभावक व आमजन से नहीं लिया जाएगा। वहीं वेटिंग राशि और नाइट चार्ज को लेकर भी निर्णय लेकर प्रशासन को बता दिए गए हैं। ऑटो यूनियन ने आश्वस्त किया है कि अब पेरेन्ट्स को अधिक किराया वसूलने की शिकायत नहीं रहेगी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) कोटा चैप्टर के पदाधिकारियों ने भी स्टूडेंट्स को ओपीडी, आईपीडी व जांचों पर रियायत का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए अलग-अलग दरें तय कर दी गई है, जिसका जिला कलक्टर ने स्वागत भी किया है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि जिस भी हॉस्टल या कोचिंग में साइकोलॉजी काउंसलिंग की आवश्यकता होगी, आईएमए के एक्सपर्ट्स हमेशा तैयार रहेंगे। इसके तहत कोचिंग संस्थानों में मेडिकल हेल्थ चेकअप कैम्प भी लगाए जाएंगे। साथ ही शहर के अन्य स्टैक हॉल्डर्स भी आगे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की मदद के लिए तत्पर है।

ये सभी प्रयास कोटा की छवि को नए सिरे से गढ़ने के लिए हो रहे हैं। कोटावासियों का कहना है कि कोटा ने अब तक स्टूडेंट्स के कॅरियर संवारे हैं। पिछले 40 वर्षों में करीब 30 लाख स्टूडेंट्स को डॉक्टर व इंजीनियर बनाया, लेकिन अब केयरिंग के क्षेत्र में भी नया आयाम स्थापित करेंगे, जो देश में नजीर बनेगी। इसके बाद देशभर में जिस तरह आज कोटा कोचिंग पैटर्न को माना जाता है, उसी तरह कोटा केयरिंग पैटर्न को भी माना जाएगा और इसको फोलो किया जाएगा।

देश का पहला इमोशनल वेलबीइंग सेंटर

कोटा अनुभवों से सीख रहा है। यहां वर्तमान में 200 से अधिक काउंसलर्स स्टूडेंट हेल्थ पर काम कर रहे हैं। यहां आने वाले स्टूडेंट्स की एडवांस केयर और शिक्षा के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बेहतर काम के लिए भी कोटा अब देश के अन्य शहरों से आगे बढ़ रहा है। या यूं कह लें कि कोटा देश का एकमात्र शहर है जहां स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। यहां सबसे पहले इमोशनल वेल बीइंग सेंटर की स्थापना की गई। यह एक ऐसा इंटीग्रेटेड कैंपस है, जहां सभी तरह के काउंसलर 24 घंटे स्टूडेंट्स की मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहां अलग-अलग विधाओं के काउंसलर स्टूडेंट्स को मानसिक तौर पर मजबूत बना रहे हैं। इसमें एकेडमिक, साइकोलॉजिकल, कॅरियर, क्लीनिक सहित सभी तरह के एक्सपर्ट काउंसलर यहां मौजूद रहते हैं। कोटा द्वारा अपनाए गए इस मॉडल को राजस्थान सरकार ने भी सराहा है और अब राजस्थान सरकार ने भी कोटा में स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंतन शुरू करते हुए प्रदेश के जोधपुर व कोटा में युवा साथी केन्द्र शुरू किए जा रहे हैं।

2 लाख स्टूडेंट्स आते हैं यहां तैयारी करने

25% सीटें जो IIT, NIT व MBBS की हैं वहां कोटा कोचिंग के स्टूडेंट

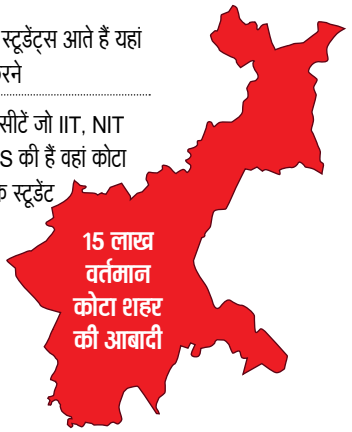

500+ आईआईटीयन-एनआईटीयन व 100 से ज्यादा एमबीबीएस फैकल्टीज

4000 हॉस्टल्स में 1.30 लाख से अधिक की क्षमता।

50000+ छात्राएं।

1500+ मैस

60000+ साइकिल यूजर्स

25000+ स्टूडेंट्स का पीजी में निवास

30 आल इंडिया टॉपर इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में कोटा से

- शहर के 3 इलाकों में फैली हुई है कोचिंग
- देश के हर कोने से यहां स्टूडेंट्स आते हैं, मिनी इंडिया है कोटा

कामयाबी की कहानियां लिखता है कोटा

जिंदगी बदलने के साथ ही कोटा अब कामयाबी की कहानियां लिख रहा है, वो कहानियां जो समाज में बदलावों के लिए प्रेरक साबित हो रही है। गांव-ढाणी के निर्धन परिवार की प्रतिभा को कामयाबी दिलाने की जिद हो या देश को नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहे युवाओं के सपने सच करने का जुनून, कोटा हर कदम पर स्टूडेंट्स के साथ है। यहां की कोचिंग की पढ़ाई पर अभिभावकों को विश्वास तो है ही, अब इस शहर को पर्यटन की दृष्टि से भी नया रूप दे दिया गया है। कोटा कोचिंग ने बीते वर्षों में सैकड़ों ऐसी कहानियां लिखी हैं जिसमें छोटे गांव कस्बों के निर्धन परिवारों की प्रतिभाओं का जीवन बदला। वे सामाजिक बदलाव के उदाहरण बने। उन्हें आस-पास के गांव कस्बे के युवा और समाज के लोगों ने फोलो किया और आज दूर-दराज के क्षेत्रों में कोटा कोचिंग के चलते शिक्षा का उजियारा फैला।

यहां सपने सजते हैं...

कोटा की गलियों में सपने सजते हैं, यहां मेहनत के आंसू भी मुस्कुरा के सिलते हैं। मैं नीट की तैयारी कर रही हूं। अपनी कोटा की लाइफ को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मुझे ऐसा शहर चाहिए था, जहां कम्पीटिशन हो, सेल्फ असेसमेंट बेस्ट हो, जहां मैं जान सकूं कि मेरा कम्पीटिटर कौन है, जान सकूं कि कितनी मेहनत हो रही है। यहां इमोशनल सपोर्ट और एजुकेशन मटेरियल दोनों देश में बेस्ट हैं। यहां वार्डन, टीचर्स, फ्रेंड्स सभी इतने सपोर्टिव हैं कि आपको नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर देते हैं।"

-रितिका राजवंशी, *नीट स्टूडेंट*

कोटा एक अलग शहर है

मैं कोटा बैंक सर्विस के लिए 42 साल पहले आया था। इसके बाद कोटा इतना पसंद आया कि यहीं बस गया। मेरे दोनों बेटे आईआईटीयन हैं और बेटी डॉक्टर है। यह सब कोटा की बदौलत है। हम यहां आईएल मंदिर में सेवा भी करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कोटा दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से कोटा बेहतर है।"

- मनोहर लाल खंडेलवाल, *कोटा*

मेरे बच्चों का जीवन बनाया है कोटा ने

मैं दो साल से कोटा में हूं। पहले मेरी बेटी ने यहां पढ़कर आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया, अभी बेटे ने जेईई-मेन क्लीयर कर लिया है। एडवांस्ड की तैयारी है। मेरे बच्चों का जीवन कोटा ने बनाया है। यहां माहौल का फर्क है। बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। कोटा शहर और यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं।"

- नीलू गौतम, *अभिभावक, बिहार*

'झूठ' कोई दल ऐसा नहीं, जिसने इसका सहारा लिया नहीं

राजीव हर्ष ✍ वरिष्ठ पत्रकार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के प्रस्ताव के संबंध में पंडित जवाहर लाल नेहरू के दावे को गलत बताया जाता है। पंडित नेहरू के अनुसार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता का प्रस्ताव नहीं मिला, जबकि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, 1950 और 1955 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने भारत को स्थायी सदस्यता का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने इसे चीन के पक्ष में ठुकरा दिया।

हमारे देश के राज्य चिन्ह में मुद्रित ध्येय वाक्य 'सत्यमेव जयते' हमारे राजनीतिक दलों के लिए बेमानी है। झूठे वादे, गलत बयान, भ्रमित करने वाले नारे, झूठे आंकड़े, अधूरे सत्य जनसमर्थन जुटाने के प्रमुख उपकरण बन गए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो कोई भी दल और कोई भी नेता ऐसा नहीं है, जिसने सत्ता हासिल करने के लिए या अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए झूठ का सहारा ना लिया हो।

बात करें देश के विभाजन की तो सत्य पर अडिग रहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अपने वादे और बयान पर टिके नहीं रह सके। उन्होंने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मगर तत्कालीन राजनीति में ऐसी करवट बदली कि आजादी से कुछ समय पहले वे देश के विभाजन के लिए सहमत हो गए। देश का विभाजन हुआ और उनका वादा झूठा साबित हुआ। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ आजादी के लिए संघर्ष करेगी, आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाएगा, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस को भंग नहीं किया गया और बाद में कांग्रेस ने सत्ता संभाली।

सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ी तो कहा गया कि उन्होंने स्वेच्छा से पद त्याग किया है, लेकिन हकीकत यह थी कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभि सीतारमैया उम्मीदवार थे। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभि सीतारमैया अध्यक्ष बनें, मगर इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 और पट्टाभि सीतारमैय्या को 1377 वोट मिले। सुभाष चंद्र बोस की इस जीत पर गांधीजी ने कहा 'सीता रमैया की हार मेरी हार है।' इसके कुछ समय बाद बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

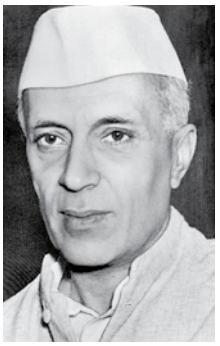

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि वे देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं है। मगर सच्चाई यह है कि माउंट बैटन की देश के विभाजन की योजना को नेहरू ने तुरंत स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के प्रस्ताव के संबंध में पंडित जवाहर लाल नेहरू के दावे को गलत बताया जाता है। पंडित नेहरू के अनुसार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता का प्रस्ताव नहीं मिला, जबकि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, 1950 और 1955 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने भारत को स्थायी सदस्यता का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने इसे चीन के पक्ष में ठुकरा दिया।

सत्यमेव जयते

कश्मीर के मसले पर भी नेहरू ने झूठ बोला। वे कहते रहे कि यह समस्या शीघ्र हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए और इसे अंतरराष्ट्रीय मसला बना दिया। धारा 370 लागू कर कश्मीर को भारत से अलग दर्जा दे दिया। यह समस्या आज तक हल नहीं हो सकी है। पंडित नेहरू ने जनता को विश्वास दिलाया था कि भारत जल्द ही आत्मनिर्भर होगा और औद्योगीकरण में बड़ी छलांग लगाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। तत्कालीन सरकार की समाजवादी नीतियों और लाइसेंस राज ने निजी उद्योगों को बढ़ने नहीं दिया। देश आर्थिक संकट में चला गया। देश में गरीबी और बेरोजगारी और बढ़ गई। देश को कई बार खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा, अमेरिका से गेंहू आयात करना पड़ा।

पंडित नेहरू कहते थे कि 'मेरी नीतियां लोकतंत्र को मजबूत करेंगी', लेकिन सच्चाई यह थी कि वे विरोधी विचार धारा वाले दलों का सहन नहीं कर पाते थे। इसी के चलते उन्होंने 1959 में केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। उस समय ईएमएस नंबूदरीपाद केरल के मुख्यमंत्री थे। वे देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले उनकी सरकार देश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी। इस सरकार ने भूमि और शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए।

चीन के साथ संबंधों को लेकर भी पंडित नेहरू के बयान गलत साबित हुए। वे जनरल करियप्पा और सरदार पटेल की चेतावनियों को दरकिनार कर दावा करते रहे कि कि चीन भारत का दोस्त है, वह हमला नहीं करेगा। उन्होंने 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा दिया, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। भारत- चीन युद्ध से पहले नेहरू कहते थे कि भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है और किसी भी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध में भारतीय सेना को संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। विज्ञान और तकनीक को लेकर किए गए नेहरू के दावे सच साबित नहीं हुए।

देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने, बेरोजगारी मिटाने और आर्थिक विषमता दूर करने के लोक लुभावन वादे किए, लेकिन वे एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी के शासन काल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी और देश खाद्यान्न के संकट से जूझता रहा। इंदिरा सरकार की आर्थिक नीतियों ने भ्रष्टाचार और लाइसेंस राज को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए काम करने का दावा करने वाली इंदिरा गांधी का आपातकाल को लेकर दिया गया बयान सबसे बड़ा झूठ था। उन्होंने कहा कि आपातकाल देश की भलाई के लिए लगाया गया। जबकि सच्चाई यह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी गड़बड़ी के आरोप में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दे दिया था। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी, विरोधियों को जेल में डाल दिया, और जबरन नसबंदी अभियान चलाया।

2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह सभी दलों में समादृत थे। अच्छे अर्थशास्त्री, अपनी विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनके भी कई दावे झूठ और भ्रामक सिद्ध हुए। उनके कार्यकाल में कई घोटाले हुए, लेकिन वे उन्हें नकारते रहे। सबसे बड़ा घोटाला था 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला। मनमोहन सिंह ने दावा किया कि इस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कोई घोटाला नहीं हुआ। सबकुछ नियमानुसार ही हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 1.76 लाख करोड़ के इस घोटाले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने अपनी मनचाही कंपनियों को सस्ती दरों पर लाइसेंस दिए। बाद में सीएजी और और सुप्रीम कोर्ट ने इसे घोटाला बताया और ए राजा द्वारा दिए गए सभी लाइसेंस रद्द कर दिए। इस बात के प्रमाण भी मिले कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सबकुछ जानते बूझते हुए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

2012 के कोयला घोटाले के संबंध में मनमोहन सिंह ने कहा था कि "कोयला खदानों के आवंटन में कोई घोटाला नहीं हुआ, और मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा।" लेकिन हकीकत यह थी कि 1.86 लाख करोड़ के इस घोटाले में कई कंपनियों को कोयला खदानें बिना नीलामी के आवंटित कर दी गईं। मनमोहन सिंह ने इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 214 कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया, जिससे सरकार की भारी बदनामी हुई।

सन 2010 हुए कॉमन वेल्थ खेलों के आयोजन में 70 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन मनमोहन सिंह का कहना था कि इस आयोजन में पूरी पारदर्शिता बरती गई, कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन इस मामले में बाद में सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार किया गया। स्वयं मनमोहन सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि वे घोटालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2G, कोल, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी, और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले हुए, पर सरकार ने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। मनमोहन सिंह कहते थे, "मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता।" लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने अनेक मामलों में सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान के इशारों पर फैसले लिए।

इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में देश की जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो विदेशों में जमा धन वापस लाएंगे और यह वादा केवल चुनावी जुमला निकला। देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा भी खोखला ही निकला। इसी तरह 8 नवंबर को नोट बंदी की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजर्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 99 फीसदी पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन गलत है कि पिछले 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि कांग्रेस के शासन काल में देश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई। इसरो, डीआरडीओ, एम्स, आईआईटी जैसे संस्थान खुले। देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। हरित क्रांति के जरिये देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा, जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई। सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में देश ने अपनी अलग पहचान कायम की। मोदी ने कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ, इसके उलट कृषि कानूनों से किसानों में असंतोष फैला और किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया।

नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन कोई न कोई गलत बयानी करते रहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि राफेल सौदे में 30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। वे इस मुद्दे को लेकर बार- बार कहते रहे चौकीदार चोर है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए। बाद में सीएजी और सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे को क्लीन चिट दी और कहा इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने संप्रग सरकार की मनरेगा योजना को खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने मनरेगा को बंद नहीं किया, बल्कि इसका बजट बढ़ाया और 2020-21 में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा फंड मनरेगा में दिया गया।

राहुल गांधी का यह आरोप भी झूठ साबित हुआ कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। सच्चाई यह है कि भारत चीन सीमा पर लम्बे समय तक तनाव रहा, लेकिन चीन भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी का विरोध करने के सिलसिले में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि नोटबंदी का असर कुछ समय के लिए जरूर पड़ा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई। नोट बंदी से यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिला। जीडीपी में कुछ गिरावट आई, लेकिन यह स्थायी नुकसान नहीं था। राहुल गांधी जेब में एक लाल किताब लेकर यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है। दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहती है। राहुल गांधी का यह आरोप जनता को भ्रमित करने के लिए है। वे इस संबंध में आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर सके।

आम आदमी पार्टी

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से उपजी आम आदमी पार्टी ने थोड़े से समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल बहुत कम समय में देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों में शुमार हो गए। केजरीवाल के झूठे वादों और दावों की फेहरिस्त लम्बी है। वे अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र सरकार या अन्य किसी पर फोड़ते रहते हैं। गलत बयानी और गलत आरोप लगाने के चक्कर में वे कई बार माफी मांग चुके हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बिना किसी सबूत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यमुना के जल में जहर मिलाने का आरोप लगा दिया। चूंकि यह आरोप विधानसभा चुनाव के वक्त लगाया गया था, इस वजह से निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल से जहर मिलाने के आरोप के संबंध में सबूत मांगे तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए।

आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के समय कहा था कि आप कभी भी कांग्रेस या बीजेपी से समर्थन नहीं लेगी और न ही किसी के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन सच यह है कि 2013 के दिल्ली चुनाव में आप ने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई। केजरीवाल ने बड़े जोर शोर के साथ कहा था, 'मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लाल बत्ती, सिक्योरिटी और बड़े बंगले नहीं लूंगा।' लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हों जेड प्लस सिक्योरिटी ली, वे बड़े बंगले में शिफ्ट हुए, और बड़े बंगले के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी वीआईपी कल्चर अपनाया।

तृणमूल कांग्रेस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। उनेक कई गलत बयान और झूठे वादे तो सामने आए ही हैं, सच को छिपाने के प्रयास भी सामने आए हैं। ममता बनर्जी कहती है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। लेकिन सच यह है कि उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर घोटाले के आरोप लगे हैं। ममता सरकार के कार्यकाल में हुए शारदा चिटफंड घोटाले में लाखों लोगों के पैसे डूब गए। 2016 में हुए नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कई टीएमसी नेताओं को रिश्वत लेते देखा गया। कभी ममता सरकार में अहम स्थान रखने वाले पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जेल में हैं। उनकी सरकार के एक अन्य मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। उनकी पार्टी के अनेक नेता आरोपों से घिरे हैं।

घुसपैठ पश्चिम बंगाल की ज्वलंत समस्या है, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में कोई अवैध घुसपैठ नहीं है, और यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है। अवैध घुसपैठ के चलते पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी है। पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा से ग्रस्त राज्य है। वैसे तो हिंसक घटनाओं का दौर वर्षपर्यंत चलता है, मगर चुनाव के दौरान राजनीकि हिंसा चरम पर होती है। ममता बनर्जी सदैव यही कहती है कि उनके कार्यकर्ता हिंसक वारदातों में शामिल नहीं होते। सच्चाई यह है कि 2018 के पंचायत चुनावों में भारी हिंसा हुई, और विपक्ष के उम्मीदवारों को नामांकन तक नहीं भरने दिया गया। ममता कहती है कि राज्य में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल है, मगर सच्चाई यह है कि प्रदेश में उद्योगों की दशा खराब है। कई बड़े उद्योगपति राज्य से बाहर चले गए। नए निवेशक आ नहीं रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के प्रमुख राजनेताओं में गिना जाता है। वे झूठे वादे करने, अपने वादों और बयानों से पलटने, अपनी सुविधा से पाले बदलने वाले नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। नीतीश ने कभी कहा था, 'मैं मिट्टी में मिल जागा मगर भाजपा में नहीं जाऊंगा।' इतना बड़ा दावा करने वाले नीतीश आज भाजपा के साथ मिल कर सरकार चला रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब और कहीं नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार ने 2022 में भाजपा से नाता तोड़ कर इंडी गठबंधन बनाया और फिर 2024 में पुनः भाजपा के साथ आ गए। नीतीश कुमार के कई दावे गलत साबित हुए है। वे बिहार में अपराधों पर काबू पाने का दावा करते हैं, मगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े अलग कहानी कहते हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार में अपराध बढ़े है। न जंगल राज और माफिया राज खत्म हुआ न हत्या और बलात्कार के मामले कम हुए। नीतीश बेरोजगारी कम होने की बात करते हैं, मगर बिहार के युवा रोज़गार की तलाश में देश के अन्य राज्यों में पलायन करने पर मजबूर है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंदी लागू की। वे कहते हैं कि इससे अपराध में कमी आई, लेकिन हुआ यह कि बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी होने लगी। शराब बंदी कानून के तहत हजारों लोग गिरफ्तार हो गए। शराब की तस्करी बंद नहीं हुई। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में उद्योगों की कमी नहीं है, मगर सच्चाई यह है कि बिहार में बड़े उद्योग नहीं है। बड़े उद्योगपति आज बिहार में निवेश करने से कतराते हैं।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव केवल बिहार ही नहीं, देश के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनके झूठे वादों, झूठे दावों की सूची लंबी है। वे जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं और सच यह है कि उनकी राजनीति जातीय समीकरणों पर ही टिकी हुई है। चारा घोटाले में दोषी पाए जाने पर जेल की हवा खा चुके हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनके और उनके परिवार के खिलाफ जांच चल रही है। वे दावा करते हैं कि उनके शासन काल में बिहार में विकास हुआ गरीबों के हालात सुधरे। सच्चाई यह है कि 1990 से 2005 तक अधिकांश समय लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासन रहा। इस दौर को जंगल राज कहा गया। बिहार का बुनियादी ढांचा चरमरा गया था।

झूठ बोल कर जनता को भ्रमित करने वालों एक प्रमुख नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुम्बई में 26 नवम्बर 2008 को हुए आतंकी हमले में हिंदू संगठनों का हाथ था। सच्चाई यह है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। पकड़े गए हमलावर अजमल कसाब और अन्य आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक निकले।

झूठ बोलने के मामले में वामपंथी दल किसी से पीछे नहीं हैं। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले वामपंथी सत्ता में आते ही दूसरे राजनीतिक दलों का दमन करने लगते हैं। विपक्ष की आवाज को खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। दावा करते हैं कि वे अहिंसा में विश्वास करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नक्सलवाद वामपंथी विचारधारा से निकला। वाममोर्चा के शासन में पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा से ग्रस्त रहा। वाम मोर्चा शासित केरल भी राजनीतिक हिंसा से त्रस्त है। वामदल मजदूरों के कल्याण की बात करते हैं मगर सच्चाई यह है कि जब पश्चिम बंगाल में वाममोर्च का शासन था मजदूर बहुत बुरी दशा में थे।

जब तक जनता जागरुक नहीं होगी, नेताओं के झूठ, गलत बयान, अधूरे सत्य पर सवाल नहीं करेगी, राजनीति में झूठ का बोलबाला यूं ही चलता रहेगा।

गरिमा और जवाबदे

विवेक श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान विधानसभा का हालिया बजट सत्र कई ऐतिहासिक और अप्रत्याशित घटनाओं का गवाह बना। आमतौर पर नीति-निर्धारण और प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के लिए आरक्षित यह पवित्र सदन इस बार व्यक्तिगत कटाक्ष, अमर्यादित टिप्पणियों और राजनीतिक नाटकों का अखाड़ा बनता दिखा। लोकतंत्र के इस मंदिर में जिस गरिमा और गंभीरता की अपेक्षा की जाती है, वह बार-बार तार-तार होती नजर आई।

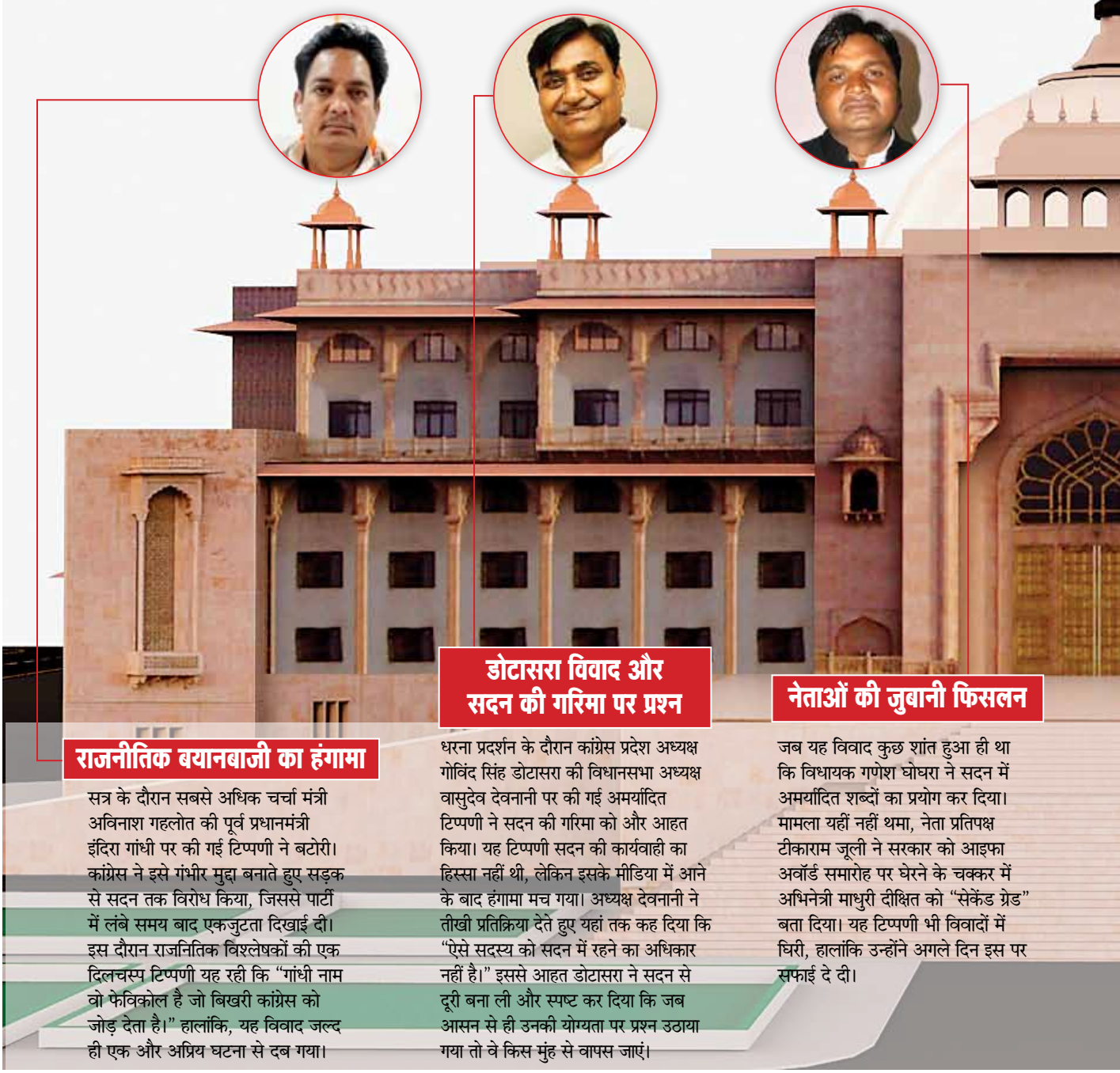

राजनीतिक बयानबाजी का हंगामा

सत्र के दौरान सबसे अधिक चर्चा मंत्री अविनाश गहलोत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी ने बटोरी। कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बनाते हुए सड़क से सदन तक विरोध किया, जिससे पार्टी में लंबे समय बाद एकजुटता दिखाई दी। इस दौरान राजनितिक विश्लेषकों की एक दिलचस्प टिप्पणी यह रही कि "गांधी नाम वो फेविकोल है जो बिखरी कांग्रेस को जोड़ देता है।" हालांकि, यह विवाद जल्द ही एक और अप्रिय घटना से दब गया।

डोटासरा विवाद और सदन की गरिमा पर प्रश्न

धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी ने सदन की गरिमा को और आहत किया। यह टिप्पणी सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इसके मीडिया में आने के बाद हंगामा मच गया। अध्यक्ष देवनानी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया कि "ऐसे सदस्य को सदन में रहने का अधिकार नहीं है।" इससे आहत डोटासरा ने सदन से दूरी बना ली और स्पष्ट कर दिया कि जब आसन से ही उनकी योग्यता पर प्रश्न उठाया गया तो वे किस मुंह से वापस जाएं।

नेताओं की जुबानी फिसलन

जब यह विवाद कुछ शांत हुआ ही था कि विधायक गणेश घोघरा ने सदन में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया। मामला यहीं नहीं थमा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को आइफा अवॉर्ड समारोह पर घेरने के चक्कर में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को "सेकेंड ग्रेड" बता दिया। यह टिप्पणी भी विवादों में घिरी, हालांकि उन्होंने अगले दिन इस पर सफाई दे दी।

...ही पर उठते सवाल

सत्र का निष्कर्षः क्या सीख मिली?... राजस्थान विधानसभा का यह सत्र उन मुद्दों से ज्यादा सुर्खियों में रहा, जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले थे। जिस सदन से जनता को उम्मीदें हैं, वहां व्यक्तिगत कटाक्ष, गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी और सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच निजी टकराव अधिक देखने को मिला। सत्तारूढ़ विधायकों की मंत्रियों से नाराजगी, नौकरशाही की निष्क्रियता और विपक्ष की राजनीति ने यह साबित किया कि लोकतंत्र की सबसे अहम संस्था की मर्यादा को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना होगा।

जनता अपने प्रतिनिधियों को सदन में इसलिए नहीं भेजती कि वे एक-दूसरे पर कटाक्ष करें या गैर-जिम्मेदार बयान दें, बल्कि इसलिए कि वे उनकी समस्याओं को हल करने के लिए गंभीरता से चर्चा करें। यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में जनप्रतिनिधि सदन की गरिमा को सर्वोपरि रखेंगे और इस सत्र में जो हुआ, उसे दोहराने से बचेंगे।

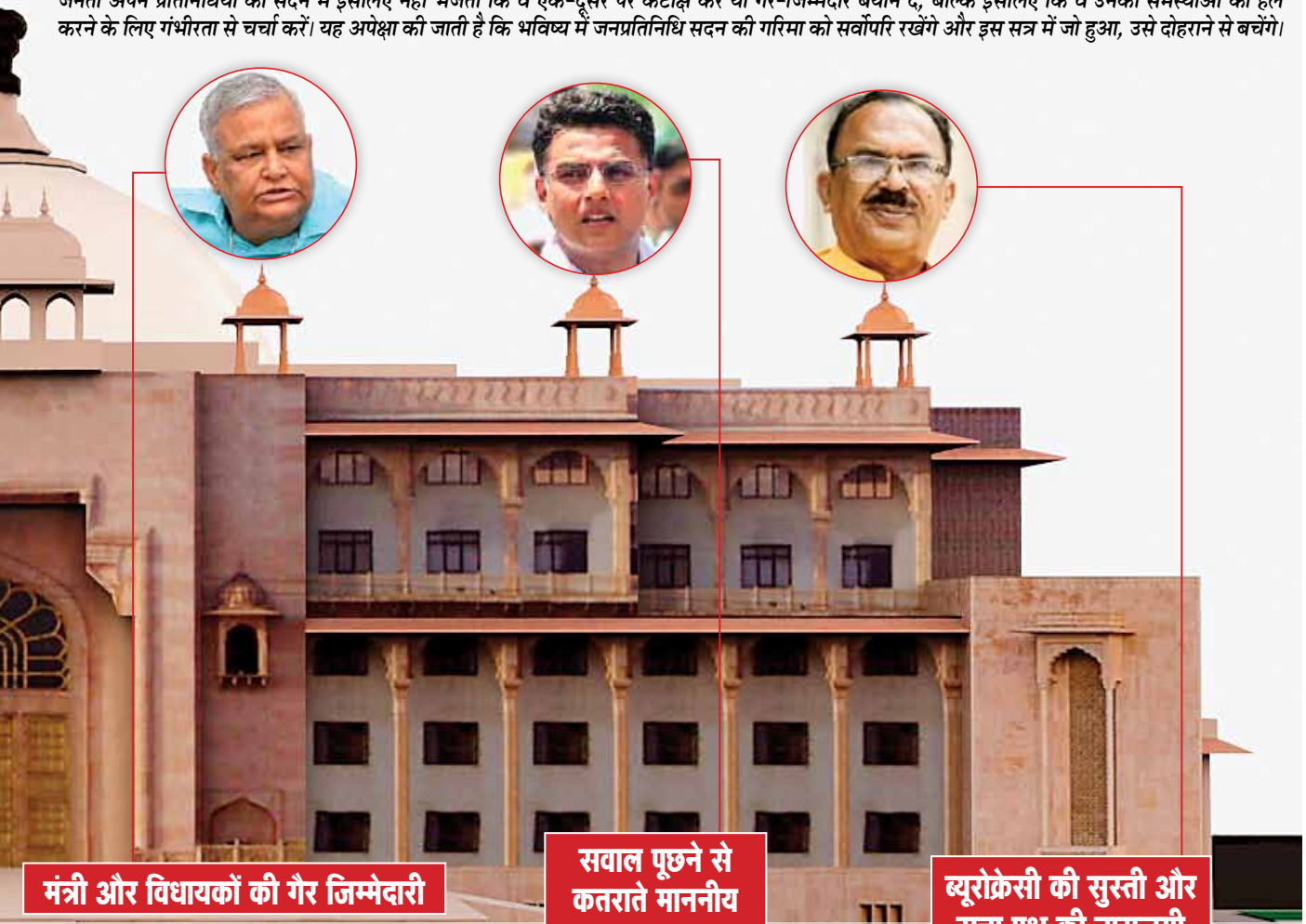

मंत्री और विधायकों की गैर जिम्मेदारी

मंत्रियों की भूमिका भी इस सत्र में सवालों के घेरे में रही। किरोड़ी लाल मीणा ने सदन में स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहने की अनुमति ली, लेकिन वे प्रदेशभर में सक्रिय नजर आए। उनकी भूमिका सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झूलती दिखी, जिससे सरकार की अंदरूनी रणनीति पर भी सवाल खड़े हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने सदन में उपस्थित न होकर अपनी पुरानी परंपरा को बनाए रखा। दोनों नेता तभी विधानसभा आते हैं जब वे सदन के नेता होते हैं। इसी कड़ी में अशोक चांदना भी नजर आए, जो इस सत्र से पूरी तरह नदारद रहे। यह दावा किया जा रहा है कि वे अपनी माइंस से जुड़े प्रकरणों में व्यस्त हैं, लेकिन हिंडौली की जनता ने उन्हें जिस जिम्मेदारी के लिए चुना, वह सदन में दिखी ही नहीं।

सवाल पूछने से कतराते माननीय

विधानसभा का मूल उद्देश्य है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन यह उद्देश्य कितना पूरा हुआ, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत सात विधायकों ने एक भी सवाल नहीं पूछा। हालांकि, 167 विधायकों ने सवाल उठाए और कुल 9800 प्रश्न विधानसभा में दर्ज हुए, लेकिन सवाल यह है कि जो बड़े नेता खुद को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, वे सदन में अपनी भूमिका से क्यों बचते रहे?

ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती और सत्ता पक्ष की नाराजगी

इस बार का सत्र न केवल राजनीतिक हंगामे से भरा रहा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता की कमी देखी गई। मंत्रियों और विधायकों की रुचि कम दिखी तो अफसरशाही ने भी इसे हल्के में लिया। मंत्रियों के जवाबों में कई बार स्पष्टता और तैयारी की कमी नजर आई, जिससे खुद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नाराज हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विधायक दल की बैठक में सख्त लहजे में नाराजगी जताई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर इसका असर सीमित रहा।

बयानों के बवंडर में संयम

राजनीति में कुछ लोग विचारधारा की मशाल लेकर चलते हैं, तो कुछ बयानबाजी की तलवार। संयम लोढ़ा दूसरी श्रेणी में आते हैं। उनकी जुबान जब चलती है, तो विरोधियों के पास जवाब से पहले चोट का अहसास होता है। सिरोही की राजनीति में उनका कद किसी पुराने किले की तरह रहा है— कभी सत्ता के प्रहरी, तो कभी बगावत के प्रतीक। दिलचस्प यह है कि वे कभी भाजपा के खेमे में नहीं रहे, बल्कि हमेशा उसके खिलाफ मोर्चा संभालते रहे। लोढ़ा की राजनीति को परिभाषित करना कठिन है। वे कभी कांग्रेस के साए में दिखते हैं, तो कभी निर्दलीय योद्धा की तरह सत्ता के दरबार में नजर आते हैं। 2018 में निर्दलीय विधायक बनकर वे अशोक गहलोत के सलाहकार बने और सत्ता के गलियारों में छाए रहे। लेकिन राजनीति में निष्ठा से ज्यादा नतीजे मायने रखते हैं, और 2023 के चुनाव में जनता ने उनका सियासी सिंहासन हिला दिया। संयम के बयान तीखे रहे हैं। वे जब जुबान खोलते हैं, तो सामने वाला संभल ही नहीं पाता। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था— "बछड़ा अब सांड बन चुका है," और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नियुक्ति पर तंज कसा— "यह राखी सावंत को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड देने जैसा है।" खेतलाजी मंदिर में 'मोदी-मोदी' के नारों पर तिलमिलाकर खुद को "सिरोही का मोदी" बताया और गुस्से में भीड़ को "डफोलो" (मूर्ख) तक कह बैठे। लोढ़ा की राजनीति तेज धार वाली तलवार की तरह है— सीधी, पैनी और कभी-कभी बेलगाम। अब देखना यह है कि उनकी यह तलवार आगे भी धार बनाए रखेगी या समय के साथ म्यान में चली जाएगी।

टीका-टिप्पणी में जूली

राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी की सरिता कभी मंद नहीं पड़ती, लेकिन जब नेता विपक्ष टीकाराम जूली बोले, तो जैसे शब्दों की 'टीका' से टिप्पणी का नया संस्कार हो गया। अब तक विधानसभा में बजट, विकास, और नीतियों पर चर्चा होती थी, लेकिन इस बार माधुरी दीक्षित के करियर ग्राफ पर विचार-विमर्श हुआ! जूली साहब ने जोश में आकर 'सेकंड ग्रेड' की परिभाषा दे डाली, मानो विधानसभा नहीं, कोई फिल्म समीक्षक का मंच हो। शाहरुख को 'फर्स्ट ग्रेड' बताकर शायद सोचा होगा कि बॉलीवुड उनके बयान पर मोहर लगा देगा। लेकिन जनाब! माधुरी दीक्षित आज भी लाखों दिलों की धड़कन हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर यही तर्क राजनीति पर लगाया जाए? 'फर्स्ट ग्रेड' और 'सेकंड ग्रेड' का फॉर्मूला राजनीतिक हस्तियों पर फिट किया जाए, तो कई चेहरे पर्दे के पीछे चले जाएंगे। आखिर, राजनीति भी तो एक बड़ा थिएटर ही है— कोई हिट, कोई फ्लॉप, और कुछ रीमेक में भी फिट हो जाते हैं। जूली जी का यह बयान साबित करता है कि हमारी राजनीति में मसाला फिल्मों का तड़का अब भी ज़िंदा है। राजनीति और सिनेमा में फर्क सिर्फ इतना ही रह गया है कि एक में पर्दे पर हीरोइन बदलती है, और दूसरे में चुनाव के साथ चेहरे। लेकिन दर्शक हमेशा वही रहते हैं— कभी ताली बजाते, कभी सिर पकड़ते!

जोधपुर में आसाराम की वापसी

जोधपुर की गलियों में एक पुरानी परछाईं लौट आई है। आसाराम की वापसी किसी धुंधले चित्र के फिर उभरने जैसी है— कभी प्रवचनों से शहर को गुंजाने वाला यह नाम अब अदालतों की बहस और फैसलों में बंध चुका है। कभी अनुयायियों की भीड़ से घिरी जोधपुर की सड़कें अब बस कानून के पहरेदारों और जिज्ञासु निगाहों की गवाह बन रही हैं। शहर की हवा में श्रद्धा की जगह कानाफूसी और तंज के सुर घुले हैं। आसाराम की मौजूदगी एक बार फिर बहसों को गर्म कर रही है— क्या समय सच में आगे बढ़ गया है, या कुछ छायाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे समय के साथ भी धुंधली नहीं होतीं? जो भी हो, जोधपुर एक बार फिर एक कहानी को दोबारा जी रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार श्रद्धा के स्थान पर प्रश्न अधिक हैं।

चिकित्सा विश्वविद्यालय में 'येवले' प्रभाव

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) में नए कुलपति की नियुक्ति किसी मेडिकल केस स्टडी से कम दिलचस्प नहीं रही। एक दिन पहले तक कुलपति पद का भविष्य धुंध में था, लेकिन फिर अचानक, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हस्ताक्षर से एक नाम बाहर आया— प्रो. प्रमोद येवले! बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अप्रत्याशित जांच रिपोर्ट से डॉक्टर खुद चौंक जाएं। चिकित्सा नीति के 'ऑपरेशन थिएटर' में जहां कई नामों की 'सर्जरी' चल रही थी, वहां येवले साहब की एंट्री बिना किसी पूर्वाभास के हुई— जैसे बिना लक्षणों वाला कोई मेडिकल सरप्राइज़! अब सवाल उठता है कि क्या येवले साहब इस विश्वविद्यालय को नई 'डोज़' देंगे या फिर वही पुरानी नीतियों की 'प्रिस्क्रिप्शन' जारी रहेगी? चिकित्सा शिक्षा के मर्ज़ के लिए कौन-सी 'थेरेपी' काम करेगी? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि येवले साहब शिक्षा के इस 'आईसीयू' में नई जान फूंकेंगे या फिर नीतियों के 'वेंटिलेटर' पर पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी।

▪ **बलवंत राज मेहता**

डॉ. लुइजि पिओ तैस्सितोरी

इटली का बेटा, राजस्थान की माटी का अपना

बलवंत राज मेहता
✍ वरिष्ठ पत्रकार

दूर इटली की किसी बर्फीली सुबह में जन्मा एक बालक, जिसे तब शायद यह भी नहीं पता था कि उसकी आत्मा किसी रेगिस्तानी धरा में बसने वाली है। 13 दिसंबर 1887 को इटली के उडीन में जन्मे लुइजि पिओ तैस्सितोरी भाषाओं के दीवाने थे। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अध्ययन में रमते-रमते जब उन्होंने राजस्थानी भाषा और उसके अनमोल साहित्य को जाना, तो मानो उनकी आत्मा इस भाषा में बस गई। वे इसे केवल पढ़ना नहीं चाहते थे, वे इसे जीना चाहते थे।

राजस्थान की ओर खिंचाव : आत्मा का पुनर्जन्म

वर्ष 1914 में, तैस्सितोरी बीकानेर पहुंचे। एक विदेशी, जो उस भाषा के प्रेम में खिंचा आया था, जिसे तब भारत में भी उचित मान्यता नहीं मिली थी। बीकानेर की हवाओं में जैसे कोई पुरानी पहचान थी, यहां की धूल में शायद कोई पुराना रिश्ता। उन्होंने अपनी पूरी साधना इसी भूमि के लिए समर्पित कर दी।

▪ वे पुस्तकालयों में दिन-रात पांडुलिपियां टटोलते, डिंगल के कठिन छंदों को समझने की कोशिश करते। चारण कवियों की वीरगाथाएं, भक्ति काव्य, और लोकगीत— सबकुछ जैसे उनकी आत्मा का हिस्सा बन गए। वे आम लोगों के बीच घुल-मिल गए। राजस्थान की बोली और संस्कारों को आत्मसात कर लिया।

तैस्सितोरी के अमर शोध और उनकी अनमोल कृतियां... तैस्सितोरी ने राजस्थानी भाषा, साहित्य और इतिहास पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए अनमोल धरोहर हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं:

1. "Notes on the Prakrit of the Jain Texts" – जैन ग्रंथों में प्रयुक्त प्राकृत भाषा पर गहन अध्ययन।
2. "Rajasthani Phonetic and Grammatical Sketch" – राजस्थानी भाषा की ध्वनि और व्याकरणिक संरचना पर विस्तृत शोध।
3. "Bikaner Inscriptions" – बीकानेर के अभिलेखों का विश्लेषण, जिससे राजस्थान के प्राचीन इतिहास की कई नई परतें खुलीं।
4. "Medieval Jainism with Special Reference to Rajasthan" – मध्यकालीन जैन धर्म पर विस्तृत अध्ययन, जिसमें राजस्थान के जैन ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया।

तैस्सितोरी ने बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र के शिलालेखों और सिक्कों का गहन अध्ययन किया, जिससे राजस्थान के इतिहास की कई नई परतें खुलीं।

भारत सरकार के लिए भी अनमोल योगदान

वर्ष 1916 में, उन्हें भारत सरकार द्वारा "आरियंटल लिस्ट" की सहायता के लिए नियुक्त किया गया। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से भी जुड़े और बीकानेर में कई प्राचीन अभिलेखों, सिक्कों और शिलालेखों का गहन अध्ययन किया। उनकी खोजों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की पूर्व धारणाओं को बदलने में अहम भूमिका निभाई।

उम्र 33... राजस्थान की माटी में विलीन हो गया बेटा

नियति को कुछ और ही मंजूर था। 22 नवंबर 1919 को मात्र 33 वर्ष की आयु में, बीकानेर की इसी भूमि पर उन्होंने अंतिम सांस ली। एक ऐसा इंसान, जिसने राजस्थानी भाषा और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, राजस्थान की इसी रेत में हमेशा के लिए समा गया। उनका अंतिम संस्कार यहीं किया गया। इटली के इस ऊर्जावान युवा की राख, राजस्थान की रेत में मिल गई। शायद कोई चारण कवि उनकी आत्मा को पढ़ रहा हो, कोई पुरानी हवेली में उनकी खोजी गई पांडुलिपियां सांस ले रही हों, कोई लोकगीत आज भी उनकी याद में गाया जाता हो।

बीकानेर में स्मारक, लेकिन राजस्थान उन्हें भूलता जा रहा है... उनके सम्मान में बीकानेर में एक स्मारक स्थापित किया गया, जो आज भी इस महान आत्मा की गवाही देता है। पर कितने लोग वहां जाते हैं? कितने लोगों को पता है कि यह राजस्थान का अपना एक बेटा था, जिसने उसकी भाषा को दुनियाभर में सम्मान दिलाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया?

राजस्थान का अनजाना नायक

राजस्थानी भाषा, जिसके लिए तैस्सितोरी ने खुद को झोंक दिया, उसे आज भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी को उसकी पहचान दिलाने वाला व्यक्ति खुद राजस्थान की स्मृतियों से धुंधला होता जा रहा है। अगर तैस्सितोरी को कुछ चाहिए था, तो बस इतना कि उनकी प्रिय भाषा जिंदा रहे, उसका सम्मान हो। पर शायद, हम उन्हें भी भूल चुके हैं और उनकी उस भाषा को भी, जिसे उन्होंने अपना हृदय दे दिया था। **बीकानेर की हवाएं जब थार के रेत पर बहती हैं, तो शायद एक आवाज़ कानों में पड़ती है-**

"राजस्थान! क्या तुम मुझे अब भी याद करते हो?"

फोटो साभार – अजीज भुट्टा, बीकानेर

बोल हरि बोल

हरीश मलिक ✍ वरिष्ठ व्यंग्यकार

बिना चिंतन के भी कई लिक्खाड़ व्यंग्य पेल देते हैं। अपन भी आज बिना चिंतन के बैठे हैं। अपनी मर्जी से नहीं, जब लिखने कहा गया तो ऐसे ही मूर्खता करने बैठ गए! कहा गया कि आजकल जो चल रहा है, उस पर एक नजर मारिए और अपनी तीरे नजर से लिख डालिए। जिसको समझ आया वो व्यंग्य मान लेगा, वरना मूर्खता में तो आपका फोटू सुरिंदर शर्मा से मीलों आगे ही है।

अप्रैल महीने की शुरुआत मूर्खता दिवस से होती है। मूर्खानंद की बातों पर आंखें गोल और लब हंसने के लिए खुल जाते हैं। ऐसे ही व्यंग्य का कटाक्ष भी चेहरे पर क्लोज-अप मुस्कान ले आता है। तो क्या मूर्खानंद और व्यंग्य में करीबी रिश्ता है? यह गंभीर चिंतन का विषय हो सकता है। वैसे मूर्खता के लिए ज्यादा चिंतन की दरकार नहीं है। बिना चिंतन के भी कई लिक्खाड़ व्यंग्य पेल देते हैं। अपन भी आज बिना चिंतन के बैठे हैं। अपनी मर्जी से नहीं, जब लिखने कहा गया तो ऐसे ही मूर्खता करने बैठ गए! कहा गया कि आजकल जो चल रहा है, उस पर एक नजर मारिए और अपनी तीरे नजर से लिख डालिए। जिसको समझ आया वो व्यंग्य मान लेगा, वरना मूर्खता में तो आपका फोटू सुरिंदर शर्मा से मीलों आगे ही है। आसपास नजर डाली तो पहला किस्सा कई रंग वाली जेब (औरंगजेब) का नजर आया!

औरंगजेब की कब्र

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' के बाद विकी कौशल के साथ-साथ औरंगजेब भी छाया हुआ है। औरंगजेब का किरदार निभाने वाले बेचारे अक्षय खन्ना बेहद दुःखी हैं। इतने बरस बाद मुश्किल से किसी फिल्म में अच्छा अभिनय हो पाया। लेकिन लोग उनके उम्दा अभिनय को भूलकर असली औरंगजेब के पीछे ही पड़ गए। उनकी एक्टिंग की बजाए औरंगजेब की क्रूरता की गली- गली में चर्चा है। उसकी अगली-पिछली पीढ़ियों के इतिहास खंगाले जा रहे हैं। यहां तक कि सदियों से चैन की नींद ले रहे औरंगजेब को खुल्ताबाद में अब अपनी कब्र की चिंता सताने लगी है। ना जाने कब मिट्टी का ढेर, मिट्टी हो जाए। लेकिन सबक लेने वाली बात ये है- जॉनी तुम्हारे पाप मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे।

सरजी की बज गई बीन

दूध का जला तो छाछ फूंक-फूंककर पीता है, लेकिन सरजी की तो छाछ भी जली हुई निकली है। मुफ्त का चंदन घिसते- घिसते बैसाखनंदन बन गए! बुजुर्गों ने क्या खूब कहा है कि बंदे को औकात से बढ़कर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सरजी ने तो पूरे जन्म की गारंटी ले ली थी। इस जन्म में तो कोई उनको हरा नहीं सकता, लेकिन जनता- जनार्दन को 'पैर की जूती' नहीं समझने का। वह सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है तो तशरीफ के नीचे से यकायक कुर्सी भी छीन लेती है। दरअसल, कुर्सी की भी अपनी मूर्खताएं होती हैं। उस पर कई वज्र मूर्ख भी बैठ जाते हैं। बैठने से पहले दावों, वादों और बातों से ठीक-ठाक लगते हैं। पर उनकी मूर्खता कुर्सी पर बैठने के बाद प्रकट हो ही जाती है। कुर्सी रूठी तो अब ना तीन में तेरह में हैं सरजी। बंदा दिल पे ले सकता है, इसलिए धोबी वाला मुहावरा नहीं लिखा।

कैश में लग गई आग

योर ऑनर! आजकल तो आप भी खूब सुर्खियों में हैं। कहीं कैश की आग में जल रहे हैं, तो कहीं रेप की कोशिश और प्रयास को नए सिरे से परिभाषित करने में लगे हैं। कैश का मसला तो वाकई कुछ ज्यादा हो गया। लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं, लेकिन यहां तो फायर का फतंगड़ बन गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट से संसद तक का मुद्दा बन गया है जी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अदालत की इज्जत 'बढ़ाते' मीम्स और सवाल बिखरे हैं। और लोग- बाग हैं कि कैश की आग में बाग- बाग हुए जा रहे हैं। आज पकड़ में आए हो चचा। दूसरों का फैसला करते- करते बहुत डकार लिया, अब जनता की डकार लेने की बारी है। अपन ज्यादा नहीं लिखेंगे। मामला कभी भी अवमानना का बन सकता है, इसलिए थोड़े लिखे को ज्यादा समझना।

ऐसा रोना भी क्या रोना

अप्रैल के पूरे महीने आईपीएल का सीजन एक बार फिर शबाब पर रहने वाला है। कैप्ड और अन-कैप्ड दोनों तरह के खिलाड़ी रन और पैसा खूब कूटने में लगे हैं। पर ई का हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा रोए जा रहे हैं। इतना तो भाई तब भी नहीं रोया था, जब पाकिस्तान से मैच में सपाट क्लीन बोल्ड हो गया! पैसे-कार के लिए करोड़पति रोहित को रोता देखकर रोना आ रहा है। शमा मोहम्मद फिर ट्वीट मारेंगी कि ड्रीम-11 के विज्ञापन में रोते हुए रोहित 'मोटे' भी लग रहे हैं। भइया मोटा-पतला होना तो आपकी अपनी च्वाइस है। लेकिन थोड़े से पैसे के लिए ऐसे विज्ञापन क्यों करते हो, जिससे युवा उत्साहित होकर अपना बैंक बैलेंस भी गंवा बैठें।

स्ट्रेटेजिक टाइम आउट! और गेम चेंज

अजय अस्थाना ✍ वरिष्ठ पत्रकार

जून 2015 में दो बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड में शामिल होने के कारण दो सीजन के लिए निलंबित कर दिया गया था। दो सीजन के लिए दोनों टीमों की जगह पुणे और राजकोट की फ्रेंचाइजी ने ले ली। आईपीएल में फिक्सिंग करने के लिए 2013 में राजस्थान रॉयल्स के अजित चंदिला और अंकित चव्हाण को बैन भी किया था।

देश में इन दिनों आईपीएल का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। शाम होते ही लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं और चौकों-छक्कों का मजा लेते हैं। मैच के दौरान स्ट्रेटिजिक टाइम आउट होता है और जब टीमें वापस मैदान पर उतरती हैं तो गेम पलट जाता है। ऐसा अनेक बार होता है। यहीं से शुरू होता सट्टे का खेल।

करीब 6 हजार साल पहले जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था। लोग पक्के घर और सीवरेज सिस्टम बना रहे थे, लगभग उसी दौरान इजिप्ट के लोगों ने खेलों पर सट्टा खेलना शुरू कर दिया था। 800 साल पहले जब एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत हुई, उस दौरान भी खेलों पर सट्टा लगाना काफी आम था। क्रिकेट की बात करें तो आज से 360 साल पहले 1664 में इंग्लैंड की संसद ने सट्टा खेलने के खिलाफ़ कानून बना दिया था। हालांकि, तब से अब तक दुनिया के कई देशों में सैकड़ों कानून बने। इसके बावजूद खेलों पर सट्टेबाजी बदस्तूर जारी है। भारत में ऑफलाइन बेटिंग पूरी तरह से बैन है, लेकिन ऑनलाइन बेटिंग को अब तक रेगुलाइज नहीं किया गया है। इस कारण कई विदेशी कम्पनियां कानून की कमी का फायदा उठाकर इंटरनेट पर भारतीयों के लिए भी स्पोर्ट्स बेटिंग के ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। फैंटेसी गेम बेटिंग के दायरे में नहीं आते। इस मामले पर 2020 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि फैंटेसी ऐप यूजर की स्किल और जजमेंट का खेल है। इसमें खिलाड़ियों के आंकड़े और ग्राउंड की कंडीशन के आधार पर पैसा लगाया जाता है। इसीलिए इसे बेटिंग में नहीं गिना जा सकता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारत में फैंटेसी गेमिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ा। इस कारण ड्रीम-11 की तरह माय-11 सर्कल, मायटीम-11, बल्लेबाजी जैसी कई ऐप्स ने स्पोर्ट्स फैंटेसी के मार्केट में कदम रख दिया। सभी ऐप्स तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। ये करोड़ों तक जीतने का लुभावना ऑफर देकर लोगों को इसमें पैसे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इनका प्रमोशन करते हैं आईपीएल के स्टार क्रिकेटर्स।

क्या है बेटिंग और फिक्सिंग

बेटिंग और फिक्सिंग दोनों अलग-अलग चीजें हैं। स्पोर्ट्स बेटिंग में किसी मैच के रिजल्ट या खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर मैच के दौरान या पहले पैसा लगाया जाता है। इसमें यूजर को नतीजे का पता नहीं रहता। इसी चीज से बचने के लिए कुछ बड़े सट्टेबाज खिलाड़ियों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें मैच में अपने हिसाब से परफॉर्म करने के लिए पैसे देते हैं। खिलाड़ी अगर सट्टेबाज का साथ देने के लिए पैसे लेकर अपनी परफॉर्मेंस में बदलाव करता है तो उसे फिक्सिंग के दायरे में गिनते हैं। फिक्सिंग पूरी दुनिया में गैरकानूनी है। आईपीएल की बात करें तो जून 2015 में दो बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड में शामिल होने के कारण दो सीजन के लिए निलंबित कर दिया गया था। दो सीजन के लिए दोनों टीमों की जगह पुणे और राजकोट की फ्रेंचाइजी ने ले ली। आईपीएल में फिक्सिंग करने के लिए 2013 में राजस्थान रॉयल्स के अजित चंदिला और अंकित चव्हाण को बैन भी किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और सलमान बट्ट बैन झेल चुके हैं।

ऐसे लगता है आईपीएल में सट्टा

आईपीएल मैच शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ इन मैचों पर लगने वाला करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा परवान चढ़ चुका है। कई बुकियों ने बाहर के एजेंट्स को हायर कर रखा है और पुलिस की नजरों से बचने के लिए बाहरी लोगों से शहर में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित करवा रहे हैं। बुकी वेबसाइट और एप के जरिए हर बाल पर हार-जीत के दांव लगवा रहे हैं। ऑनलाइन खेल के फेर में सटोरियों को दबोचना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए शातिर बुकीज ने सट्टा खिलाने का तरीका बदल लिया है। पूरा खेल हाइटेक होकर ऑनलाइन हो गया है। वेबसाइट, एप और मोबाइल पर चल रहे ऑनलाइन सट्टा बुकी कारों में बैठकर और घूम-घूम कर खिला रहे हैं। सटोरियों ने हाईटेक जमाने में खुद को भी हाईटेक कर लिया है। अब फोन पर कॉल या मैसेज के बजाय ज्यादातर बुकिंग वाट्सएप या अन्य इंटरनेट मीडिया साइट्स से ले रहे हैं। सट्टा खिलाने के लिए हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सीधे-सीधे बुकिंग हो जाती है। दांव जीतने पर पेमेंट की जानकारी भी इसी तरह से दी जा रही है। सटोरिए के प्लेटफॉर्म पर चलने वाले आइपीएल मैच का स्कोर अन्य लाइव स्कोर दिखाने वाले माध्यमों से ज्यादा तेज है। संभावना है कि बुकी के एजेंट क्रिकेट मैदान में मौजूद रहते हैं वहीं से हर गेंद का स्कोर उसी समय अपडेट करते हैं। इसके कारण टीवी चैनल के मुकाबले मैच का लाइव स्कोर 2-3 गेंद पहले ही आ जाता है। इसमें सट्टा भाव भी रहता है। जो हर बॉल पर अपडेट होता है। इसे देखकर खिलाड़ी बुकी को अपना दांव नोट कराते रहते हैं। लाइव अपडेट पहले होने का फायदा उठाकर सटोरिए हर बॉल के दांव बुक करके लाखों रुपए कमाते हैं।

क्या है स्पोर्ट्स बेटिंग

स्पोर्ट्स बेटिंग क्रिकेट मैच के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। बेटिंग रेट भारत के जीतने पर $7000 रुपए है और पाकिस्तान के जीतने पर $3000 रुपए है। यानी भारत के जीतने पर अगर आपने 1000 रुपए लगाए और टीम जीत गई तो आपको 7000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के जीतने पर आपने 1000 रुपए लगाए और टीम जीत गई तो आपको 3000 रुपए मिलेंगे।

अमेरिका में लाखों करोड़ों की स्पोर्ट्स बेटिंग

2018 में अमेरिका में लीगल हुई स्पोर्ट्स बेटिंग। कई देशों की तरह अमेरिका में भी स्पोर्ट्स बेटिंग कई वर्षों तक रेगुलेटेड नहीं थी। 1992 में फेडरल कानून के तहत अमेरिका के सभी राज्यों में स्पोर्ट्स बेटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि, 2018 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटा दी। तर्क यह था कि बैन के बावजूद जब पैसों का यह खेल चल ही रहा है तो इसे क्यों न मान्यता दे दी जाए। इस समय अमेरिका के 50 में से 38 राज्यों में स्पोर्ट्स बेटिंग को कानूनी मान्यता मिली हुई है। अमेरिकी लोगों ने 2023 में 10 लाख करोड़ की स्पोर्ट्स बेटिंग की। 2018 में सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिलने के बाद अमेरिका में स्पोर्ट्स बेटिंग जंगल में आग की तरह फैली। अमेरिकी गेमिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2023 में अमेरिका में लोगों ने 119.84 बिलियन डॉलर, यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स बेटिंग की। यह रकम 2022 की तुलना में 27.5 प्रतिशत ज्यादा है। लोगों की बेटिंग में बढ़ती रुचि से अमेरिकी बेटिंग कंपनियों का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2023 में अमेरिकी स्ट्रेबाजी कंपनियों ने 10.92 बिलियन डॉलर, यानी करीब 90 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया।

इस बार सनराइजर्स हैदराबाद प्रबल दावेदार!

इस बार किसके सिर सजेगा आईपीएल का खिताब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश के सबसे बड़े फलोदी के सट्टा बाजार ने सनराइजर्स हैदराबाद को खिताब का सबसे प्रबल दावेदार माना है। सट्टा बाजार में सनराइजर्स हैदराबाद के भाव सबसे कम हैं। फलोदी सट्टा बाजार देश में चुनाव और क्रिकेट की भविष्यवाणियों के लिए मशहूर है। पहले भी इसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में सही अनुमान लगाकर सबको चौंका दिया था। मतगणना से एक दिन पहले बाजार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और ऐसा ही हुआ। अब आईपीएल-2025 की बारी है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। फलोदी सट्टा बाजार में उनकी टीम सबसे नीचे है। इसका मतलब है कि बाजार को रॉयल्स के जीतने की उम्मीद कम लग रही है।

सट्टा बाजार में किस टीम का कितना भाव?

फलोदी सट्टा बाजार के भावों की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद पहले नंबर पर है। इसके बाद मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है। इन दोनों के भाव बराबर हैं। फिर रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का नंबर आता है। सबसे आखिर में राजस्थान रॉयल्स है।

राजनीति का अपराधीकरण
कौन लगाए रोक?

राधा रमण ✍ वरिष्ठ पत्रकार

राजनीति जिसकी लाठी, उसकी भैंस सरीखी हो गई। राजनीति में अपराधियों के पदार्पण की मूल वजह भी यही है। वरना आजादी के बाद की राजनीति इतनी खराब नहीं थी। सियासत के क्षेत्र में अच्छे लोग सक्रिय थे जो समाज का भला-बुरा सोचते थे।

वैसे तो देश की राजनीति में 1957 के चुनाव में ही बूथ कैप्चरिंग की पहली वारदात बिहार के मुंगेर जिले (अब बेगुसराय जिला) के मटिहानी विधानसभा चुनाव में हो गई थी। उस समय दबंगों ने जबरदस्ती बूथ पर कब्जा कर अपने पक्ष में लोगों के वोट डलवा लिए थे। हालांकि उस काले अध्याय की चर्चा आज तक होती है, लेकिन बाद के दिनों में बूथ कैप्चरिंग की वारदातें लगातार बढ़ती गईं। राजनीति जिसकी लाठी, उसकी भैंस सरीखी हो गई। राजनीति में अपराधियों के पदार्पण की मूल वजह भी यही है। वरना आजादी के बाद की राजनीति इतनी खराब नहीं थी। सियासत के क्षेत्र में अच्छे लोग सक्रिय थे जो समाज का भला-बुरा सोचते थे। किसान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे कि बेटी की शादी अगर गलत घर में हो जाए तो परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन वोट अगर गलत व्यक्ति को मिल जाता है तो समाज खराब हो जाता है।

क्या आज की राजनीति को आप अच्छी और आज के समाज को आप अच्छा समाज कहना चाहेंगे? पिछले करीब चार दशक से राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सभी दलों के नेता हो-हल्ला मचाते रहे हैं। संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी ये मसला सिर चढ़कर बोलता रहा है। लेकिन सही बात तो यह है कि नेता खुद भी नहीं चाहते कि राजनीति साफ-सुथरी हो।

राजनीति को समाज सेवा का दर्जा दिया गया है, लेकिन आजादी के बाद से हमारे समाज सेवकों की सम्पत्ति में अकूत वृद्धि हुई है। अगर, मेरी बात पर भरोसा न हो तो सरकार किसी न्यायिक आयोग से सभी नेताओं की जो किसी सदन के सदस्य रहे हों, उनकी सम्पत्ति की जांच क्यों नहीं करा लेती। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार विधायक या सांसद क्या बन गए, नेताओं की सम्पत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ जाती है। मंत्रियों का तो कहना ही क्या! हद तो यह है कि समाज सेवा के नाम पर उन्हें टैक्स में छूट भी मिलती है। और तो और, सांसद- विधायक जब चाहते हैं अपनी तनख्वाह में मनमानी वृद्धि कर लेते हैं। आज तक इस मामले में किसी सदन में कभी विरोध की बात देखी-सुनी नहीं गई।

सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आजीवन प्रतिबंध लगाना उपयुक्त होगा या नहीं, यह पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दंड के क्रियान्वयन को एक उपयुक्त समय तक सीमित कर, रोकथाम सुनिश्चित की गई है और अनावश्यक कठोर कार्रवाई से बचा गया है। सरकार ने कहा कि यह क़ानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार निर्धारित होते हैं।

गजब तो यह कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद् चारों सदनों का सदस्य रहा हो तो किसी सदन की सदस्यता नहीं रहने पर वह चारों सदनों की एक साथ पेंशन का हकदार हो जाता है। जबकि निजी सेक्टर में काम करने वाले और जीवन खपाने वाले लोग बुढ़ापे में पाई-पाई को मोहताज हो जाते हैं।

आज भी लालू प्रसाद और आनन्द मोहन जैसे न जाने कितने लोग सजायाफ्ता होने के बावजूद प्रतिमाह लाखों रुपए पेंशन के ले रहे हैं। मुझे कहने दीजिए कि इस मामले में राजनीतिक दलों में गजब की एकता है – 'हमाम में सभी नंगे हैं' की उक्ति चरितार्थ होती है।

हाल ही में सजायाफ्ता सांसदों – विधायकों समेत अन्य नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने संबंधी जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया हलफनामा गौर करने लायक है। याचिका भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इस पर सरकार का कहना है कि 'याचिका में जो अनुरोध किया गया है वह संविधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से क़ानून बनाने का आदेश देने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा संबंधी उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से पूरी तरह परे है। इस तरह की योग्यता तय करना केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।'

इतिहास गवाह है कि जनता जिस तेजी से किसी को सिर पर बैठाती है, जायज वजह मिलने पर उससे दूनी गति से सत्ता से च्युत भी कर देती है। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, न कि हठधर्मिता से। हमारे नेताओं को यह बात समझनी ही होगी।

सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आजीवन प्रतिबंध लगाना उपयुक्त होगा या नहीं, यह पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दंड के क्रियान्वयन को एक उपयुक्त समय तक सीमित कर, रोकथाम सुनिश्चित की गई है और अनावश्यक कठोर कार्रवाई से बचा गया है। सरकार ने कहा कि यह क़ानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार निर्धारित होते हैं। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि 'अदालत ने निरंतर यह कहा है कि एक विकल्प या दूसरे पर विधायी विकल्प की प्रभावकारिता को लेकर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता।' जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोषसिद्धि की तारिख से छह साल या कारावास के मामले में रिहाई की तारीख से छह साल तक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग के पास ताकत है कि वह किसी मामले में इस अवधि को कम या पूरी तरह हटा सकता है। धारा 8 कहती है कि किसी विधायक या सांसद को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह सजा पूरी करने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी तरह धारा 9 में प्रावधान है कि भ्रष्टाचार अथवा देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को 5 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में चुनाव आयोग से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी है, जिन पर से आयोग ने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया था या हटा दिया था। साथ ही याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि वह चुनाव आयोग से जानकारी मिलने के दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में ही यह याचिका दाखिल की थी, लेकिन सरकार की हीलाहवाली और टालमटोल रवैये के कारण मामला अभी तक परिणति तक नहीं पहुंच पाया है।

सवाल उठता है कि जो सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के उस फैसले को अध्यादेश के जरिये पलट देने की सामर्थ्य रखती हो, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहभागिता को अपरिहार्य माना गया था। उस सरकार को सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या सरकार ऐसा नहीं चाहती कि राजनीति से अपराधियों का सफाया हो अथवा सरकार में बैठे लोग कहीं अपने भविष्य को लेकर आशंकित तो नहीं हैं।

नेताओं को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता यह सब देख रही है। इतिहास गवाह है कि जनता जिस तेजी से किसी को सिर पर बैठाती है, जायज वजह मिलने पर उससे दूनी गति से सत्ता से च्युत भी कर देती है। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, न कि हठधर्मिता से। हमारे नेताओं को यह बात समझनी ही होगी।

टैरिफ की नई चुनौतियां

राकेश गांधी ✍ वरिष्ठ पत्रकार

ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ नीतियों के चलते भारत वैश्विक व्यापारिक चर्चाओं के केंद्र में है। वहीं मोदी प्रशासन की प्रतिक्रिया पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। अब तक तो भारत ने लचीला रुख अपनाया है, लेकिन यदि उसे अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखते हुए स्वदेशी उत्पादों के महत्व को बनाए रखना है तो कुछ सख्त कदम उठाने होंगे।

विशाल उपभोक्ता बाजार और मध्यमवर्गीय जनता की ब्रांडेड उत्पादों की बढ़ती मांग भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बना रही है। अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख विकसित देश भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। भारत भी औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, पर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने में अभी समय लगेगा। हाल ही में ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ नीतियों के चलते भारत वैश्विक व्यापारिक चर्चाओं के केंद्र में है। वहीं मोदी प्रशासन की प्रतिक्रिया पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। अब तक तो भारत ने लचीला रुख अपनाया है, लेकिन यदि उसे अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखते हुए स्वदेशी उत्पादों के महत्व को बनाए रखना है तो कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका व चीन चाहते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा रहे। ऐसे में यदि भारत अपनी निर्माण क्षमता में गुणात्मक सुधार व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है तो ये देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। ताजा टैरिफ प्रकरण में ये जानना जरूरी है कि भारत जहां अमेरिकी वस्तुओं पर 9.5 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, वहीं भारतीय आयात पर अमेरिकी शुल्क केवल 3 प्रतिशत ही है। ट्रम्प रैसिप्रोकल नीति (जैसे को तैसा) के जरिए सभी देशों से इसी असंतुलन को खत्म करना चाहते हैं।

विकसित देशों की भारत में रुचि

भारत की बड़ी आबादी, बढ़ती क्रय शक्ति और उपभोक्ता बाजार के चलते अमेरिका और चीन की बड़ी कंपनियां यहां निवेश बढ़ा रही हैं। टेस्ला, एप्पल, विमानन कंपनी बोइंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भारतीय बाजार को नहीं खोना चाहतीं। ये कंपनियां भारत में निर्माण हब बनाने की जुगत में हैं। चीन की शाओमी, विवो, ओप्पो जैसी कंपनियों ने भी यहां मजबूत उपस्थिति बनाई है। साथ ही, भारत आईटी सेवाओं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और फार्मा सेक्टर में एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। सस्ती भारतीय दवाओं व वैक्सिन के लिए अमेरिका की भारत पर काफी निर्भरता है। चीन की भी दवाओं के कच्चे माल (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडीग्रेण्ट्स), कपास, लोहा, स्टील, टैक्सटाइल्स, आटोमोबाइल्स व कैमिकल्स आदि के लिए भारत पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

अमेरिका ने टैरिफ वार क्यों छेड़ा?

अमेरिका चीन, यूरोप और अन्य देशों के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। ट्रम्प अपने पहले कार्यकाल में इस समस्या को पहचान चुके थे। ये ही कारण रहा कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्होंने इस असंतुलन को ठीक करने के लिए टैरिफ शुल्क बढ़ाए। अमेरिका की बेहतरी के लिए ट्रम्प वहां की घरेलू औद्योगिक इकाइयों को नुकसान से उबारने व उन्हें सुरक्षा देने के लिहाज से भी सक्रिय हैं। ट्रम्प ने जैसे ही टैरिफ बढ़ाए, चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। ट्रम्प प्रशासन ने इसे 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत प्रचारित किया। ये अलग बात है कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ने गत माह भारत दौरे के दौरान कहा कि 'अमेरिका फर्स्ट' नीति भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'इंडिया फर्स्ट' प्रतिबद्धता के समान है।

भारत को क्या लाभ?

अमेरिका की टैरिफ नीति मुख्य रूप से चीन को लक्षित कर रही है, लेकिन इसका फायदा भारत को भी हो सकता है। अमेरिका ने चीन से आयात घटाकर भारत से स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी उत्पाद और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसी वस्तुओं का आयात बढ़ा दिया है। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के मामले में भी भारत को नए अवसर मिल रहे हैं। अमेरिका- चीन के व्यापारिक तनाव के बीच कई कंपनियां चीन छोड़कर भारत में निर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। इस तनाव का फायदा उठाते हुए भारत ने भी दुनिया के समक्ष देश को वैकल्पिक निर्माण हब के तौर पर प्रस्तुत किया है, जिस पर एप्पल, सेमसंग जैसी कम्पनियों ने भारत में अपना निवेश भी बढ़ाया है।

संभावित नुकसान... हालांकि यह बदलाव भारत के लिए फायदेमंद है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वैश्विक व्यापार अस्थिरता के कारण भारतीय निर्यातकों की चिंताएं बढ़ी हैं। चीन, अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत में सस्ते उत्पादों की बाढ़ ला सकता है, जिससे घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

भारत को क्या करना चाहिए?

भारत को अपनी निर्माण क्षमता में गुणवत्ता पूर्ण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा। साथ ही सेमीकंडक्टर्स, रक्षा उपकरण, पेट्रोलियम उत्पाद, डिजिटल डेटा स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। यूरोप, जापान और रूस के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना भी एक रणनीतिक कदम होगा। गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाने से भी भारत को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। वैसे व्यापार में संतुलन के लिए रैसिप्रोकल नीति मायने रखती है, लेकिन जब देश की आर्थिक मजबूती की बात होती है तो सभी देशों के नायकों को ट्रम्प की तरह सोचना ही होता है। भारतीय शासकों को भी स्मार्ट रणनीति पर काम करना चाहिए और मौके का फायदा उठाकर स्वदेशी उत्पादों को महत्व बढ़ाना चाहिए।

देशवासियों की भूमिका... भारतीय उपभोक्ताओं को स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि मध्यम वर्ग भारतीय ब्रांड्स को अपनाए, तो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। टाटा, महिंद्रा, बजाज, डाबर, पतंजलि, एचसीएल, रिलायंस, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों की वृद्धि से देश का व्यापार घाटा कम होगा और डॉलर पर निर्भरता घटेगी। आज भारत चिकित्सा, तकनीक, ऑटोमोबाइल, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप, सोलर पैनल और बैटरी टेक्नोलॉजी में भी मजबूत स्थिति में आ रहा है। यदि भारत अपनी रणनीति को स्मार्ट तरीके से लागू करे, तो यह वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य

भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो वर्ष 2022-23 के 78.40 अरब डॉलर की तुलना में थोड़ा कम रहा। हालांकि, इस वर्ष अकेले जनवरी में निर्यात 39% बढ़कर 8.44 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मजबूत संबंधों की बदौलत भारत व अमेरिका ने 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य तय किया है।

नीतियां व प्रतिबंध रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा

'टैरिफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल को चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, ये एक सच्चाई हैं। देश इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पिछले दस सालों को देखें तो पाएंगे कि देशों ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल हथियार की तरह किया है। इसमें आर्थिक गतिविधियां, वित्तीय लेन-देन, ऊर्जा सप्लाई या टेक्नोलॉजी सब शामिल हैं। यही आज की दुनिया की सच्चाई है। दुनिया एक नए आर्थिक समीकरण की ओर बढ़ रही है, जहां नीतियां और प्रतिबंध एक नए दौर की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन गए हैं।'

-एस. जयशंकर, *विदेश मंत्री*

भारत पर असर न के बराबर

अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर असर न के बराबर होगा। इसका कारण है कि भारत निर्यात में विविधताएं ला रहा है, साथ ही वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) पर भी जोर दे रहा है। निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश के साथ ही यूरोप से मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए रास्ते पर भी काम कर रहा है। नए सप्लाई चेन एल्गोरिदम को भी नए सिरे से तैयार कर रहा है। ऐसे में टैरिफ को लेकर अमेरिका के फैसले का भारत पर असर पड़ने की आशंका न के बराबर है। हालांकि भारत के निर्यात में 3 से 3.5 प्रतिशत तक की गिरावट की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही स्तरों पर सुधार जरूरी है।

-एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट

क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर डॉलर चाहिए?

ट्रम्प का डर्टी प्लान!

मनोज वर्मा ✍ वरिष्ठ पत्रकार

क्या अमेरिका खुद ही डॉलर की मजबूती से परेशान है? अमेरिकी व्यवस्था को कमजोर डॉलर पंसद है? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ बड़े अर्थशास्त्री पहले ही आशंका जता चुके हैं कि ऐसा संभव है कि आने वाले समय में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अमेरिका खुद डॉलर को गिराएगा। दुनिया भर में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई है कि अमेरिका चाहता है कि उसके डॉलर का डिवेल्यूएशन हो।

मार्च के तीसरे सप्ताह में खबर आई कि रुपए ने डॉलर के विरुद्ध बड़ी छलांग लगाई हैं। इस साल रुपए ने डॉलर के मुकाबले उच्चतम स्तर हासिल कर लिया। एक मार्च को डॉलर का मूल्य 87.47 था, जो 21 मार्च को 85.97 हो गया। अब सवाल इस बात का है कि ट्रम्प के टैरिफ टेरर, सोने में तेजी के बीच ऐसा क्या हो गया कि डॉलर कमजोर हो गया। जबकि दूर- दूर तक डॉलर के कमजोर होने के कोई संकेत नहीं थे। क्या अमेरिका खुद ही डॉलर की मजबूती से परेशान है? अमेरिकी व्यवस्था को कमजोर डॉलर पंसद है? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ बड़े अर्थशास्त्री पहले ही आशंका जता चुके हैं कि ऐसा संभव है कि आने वाले समय में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अमेरिका खुद डॉलर को गिराएगा। दुनिया भर में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई है कि अमेरिका चाहता है कि उसके डॉलर का डिवेल्यूएशन हो। डॉलर के इस खेल में कई पेच हैं। एक तरफ अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उत्पाद आधारित नौकरियां पैदा करने का बोझ ट्रम्प पर है, दूसरी ओर वे ये भी नहीं चाहते हैं कि ब्रिक्स देश डॉलर के अलावा अन्य भुगतान के विकल्प पर सोचें। इसको लेकर धमाकने से भी ट्रंप नहीं चूके। कुल मिलाकर अमेरिका की अनिश्चितता सभी के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं।

दरअसल जब महंगाई के साथ ब्याज दर को कम नहीं किया जा सकता, उस समय डॉलर को गिराने का तरीक़ा सिर्फ़ टैरिफ़ बचता है। इस खेल को देखेंगे तो साफ़ दिखेगा कि किस तरह से टैरिफ़ एक रूप से इंफ़्लेशनरी है और दूसरी और से डिफ़्लेशनरी। ट्रम्प शेयर मार्केट को जब तक नहीं गिराते, तब तक ट्रेज़री बॉण्ड की रेट कम नहीं हो सकती। दस साल के बॉण्ड की रेट को कम करना ही एक मात्र मक़सद है। इससे ही सरकार को सस्ता डेब्ट मिलेगा और उस से डेब्ट स्पायरलिंग से बचा जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट 4 प्रतिशत से कम आएगी तो शेयर मार्केट निचले स्तर पर होगा, सोना आसमान छुएगा। इस तरह की गणित से ही ट्रम्प फिर डॉलर को उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे। इस खेल के पीछे अमेरिकी इंडस्ट्रीयल मिलिट्री कम्पलेक्स है, जिसके कहे अनुसार ट्रम्प चल रहे हैं। हो सकता है कि कम अवधि के इस खेल से भारत को फायदा हो और हम इसे अपनी नीति की जीत मान लें, लेकिन यह अस्थाई विकल्प ज्यादा लाभ नहीं लेने देगा।

अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी एक रिपोर्ट कहती है कि मजबूत अमेरिकी डॉलर न केवल अमेरिका की वित्तीय ताकत का प्रतीक रहा है, बल्कि मुद्रास्फीति को कम रखने में भी मदद करता है। इससे वहां विदेशी निवेश प्रोत्साहित होता है। लेकिन टैरिफ बदलाव के साथ ट्रम्प के सलाहकार उनकी संरक्षणवादी व्यापार नीति की सहायता के लिए डॉलर को कमजोर करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि मजबूत डॉलर अमेरिकी उत्पादों को विदेशों में अधिक महंगा बनाता है। अन्य देशों के उत्पादों के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। ट्रम्प टैरिफ टेरर से अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार में सस्ता होना भी जरूरी है। इसमें कमजोर डॉलर की नीतियां अमेरिकी उत्पादों की सहायता कर सकती हैं। लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि अमेरिका को वस्तु व्यापार में घाटा होता है, लेकिन सर्विसेज में वह शुद्ध लाभ कमा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रम्प के नारे अमेरिका को फिर महान बनाना है, के अनुरूप देश में नौकरियों के सृजन में उत्पाद व्यवस्था को मजबूत बनाकर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ट्रम्प ने अपने आर्थिक सलाहकार के रूप में स्टीफन मिरन को नामित किया हैं। जो अपने शोध में ऐसे तथ्यों को परिभाषित कर चुके हैं, जो दर्शाते हैं कि अमेरिका के लिए डॉलर की मजबूती भी बोझ हैं। बहरहाल भारतीय अर्थशास्त्री भी इस पर निगाएं जमाए बैठे हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुरामन एक आलेख में लिख चुके हैं कि डॉलर की स्वीकार्यता घटती है तो यह उनके लिए बोझ बन जाएगा, लेकिन कोई अमेरिकी ऐसा नहीं चाहेगा।

इसलिए जन्म ले रही है आशंकाएं... अमेरिका में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में भी व्यापारिक घाटे से अमेरिका जूझ रहा था। उस दौर में 1980 में डॉलर बहुत मजबूत था। व्यापार घाटे को ठीक करने के लिए रीगन ने प्लाजा समझौते के माध्यम से डॉलर के डिवेल्यूशन पर काम किया। उस दौर में डॉलर में 40 फीसदी तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। यह समझौता सितंबर 1985 में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और पश्चिम जर्मनी के बीच हुआ था। जिसमें पांच साल में डॉलर के 50 फीसदी बढ़ने पर अन्य करेंसी की वेल्यू मैनेज करने पर सहमति हुई थी। इससे डॉलर के मूल्य गिर गए थे। अमेरिका के एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि तब और अब की परिस्थितियां एक सी नहीं है। ऐसे विकल्प अर्थवयवस्था को डांवाडोल कर सकते हैं।

शब्द भाव का खोल है

कविता निःशब्दता की यात्रा

दिनेश सिंदल ✍ कवि, लेखक

शब्दों में आपकी नीयत दिखती है। आप किसके पक्ष में हैं, किसके विपक्ष में हैं, किसके साथ, हैं, किसके विरोध में हैं, यह स्पष्ट दिखाई देता है। भाव के अंदर आपकी नीयत स्पष्ट नहीं दिखती। कविता के लिए आपको स्वयं के व्यक्तित्व का विसर्जन करना पड़ता है।

मेरे लिए विचार कविता जैसा कोई शब्द नहीं है। मेरा मानना है कि जहां विचार है, वहां कविता बहुत दूर है, क्योंकि विचार बुद्धि की चीज है। विचार को तर्क से काटा जा सकता है। 'तर्क से वह हारा हुआ अनुभव करेगा, बदला हुआ नहीं। रूपांतरण भाव की छलांग है।'

शब्द भाव का खोल है। भाव आत्मा है, शब्द शरीर। शब्द हृदय तक नहीं पहुंचता। वह मस्तिष्क तक ही रहता है। हृदय तक भाव पहुंचता है।

शब्द की अलग- अलग भंगिमाएं है। उसका अलग- अलग आकार है। अलग- अलग रूप है। जब तक हम शब्द के साथ हैं, तब तक हम अलग- अलग है। भाव का कोई रूप नहीं, भाव का कोई आकार नहीं।

शब्द के साथ विचार है। विचार किसी से संबंधित होता है। किसी के प्रति पक्षपाती होता है। विचार किसी के प्रति चिंता, प्रेम, आकर्षण, लगाव, दुराव, नफरत का संबंध रखता है। वह चाहे कोई मनुष्य हो, समाज हो, देश हो, जाति- धर्म हो या भाषा। किंतु भाव किसी से संबंधित नहीं होता। वह हमारा स्वभाव है, जो हमारे भीतर से बहता है। जिस तरह फूल खुशबू और चंद्रमा चांदनी बिखेरता है, नदी प्यास बुझती है। ये फूल, चंद्रमा, नदी का अपना स्वभाव है।

चूंकि शब्द हमारे बाह्य संस्कारों से निकलते हैं। अतः वे अलग-अलग होते हैं। इसलिए जब तक हम शब्द के साथ होते हैं तब तक हम अलग-अलग होते हैं। हम हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, जैन होते हैं, सिख होते हैं, पारसी होते हैं। हम वैचारिक स्तर पर जनवादी, प्रगतिवादी, कलावादी, राष्ट्रवादी आदि खेमों में बंटे होते हैं। लेकिन जब हम भाव के स्तर पर आते हैं तो हमारे सभी खोल उतर जाते हैं। हम में कोई भेद नहीं रहता।

जिस तरह शरीर आत्मा का खोल है। शरीर अलग-अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है। आत्मा के स्तर पर आकर हम में कोई भेद नहीं रह जाता। सब एक और एक सब हो जाता हैं।

जो आत्मा को नहीं मानते वो यूं समझ सकते हैं कि जिस तरह दीपक अलग- अलग हो सकते हैं। कोई मिट्टी का, कोई सोने- चांदी का, कोई पीतल का, कोई लोहे का, किंतु उसके भीतर जलने वाली ज्योति एक होती है। दीपक अलग- अलग है, किंतु ज्योति एक है।

रात भर आंधियारे से लड़ता रहा दहलीज पर
कौन आकर रख गया है इक दिया दहलीज पर
हम गए भीतर तो कोई और ही बैठा मिला
नाम कोई और ही लिखखा मिला दहलीज पर

कविता या कहूं कि हमारी कलाएं हमें इसी ज्योति का रास्ता दिखाती है। इसी ज्योति की तरफ ले जाती हैं।

कविता शब्द में नहीं है। कविता शब्द के पार है। शब्द तो रास्ता है कविता तक पहुंचने का। शब्द साधन है। इसी तरह भाषा साधन है, उपमान- उपमेय साधन है। कविता साध्य है।

जैसे कोई हमें अंगुली के इशारे से चांद दिखाए और कहे- ' वो देखो चांद'। यहां अंगुली चांद नहीं है। चांद कही दूर है। अंगुली सिर्फ चांद की तरफ किया गया इशारा है। कविता में शब्द का काम उस अंगुली जितना ही है। कविता चांद है, किंतु कुछ लोग इस अंगुली को ही चांद समझ लेते हैं और इसे ही सजाने संवारने लग जाते हैं।

कविता शब्दों मे नहीं होती, शब्दों के परे होती है। जिस तरह पत्थर मूर्ति नहीं है। पत्थर में से मूर्ति उकेरना पड़ता है। शब्द कविता के लिए उतने ही जरूरी है, जितना मूर्ति के लिए पत्थर। कविता निःशब्दता में है। जहां शब्द चुप हो जाते हैं, कविता वहां से आरंभ होती है। लेकिन इस निःशब्दता को शब्द से ही पाना पड़ता है। इस निःशब्दता की यात्रा शब्द के रास्ते से ही करनी होती है।

जिस तरह इस कमरे के बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ कदम (दरवाजे तक) इस कमरे में ही चलना पड़ेगा। निःशब्दता को पाने के लिए भी कुछ देर शब्द के साथ चलना पड़ता है।

यही से मुश्किल पैदा होती है। क्योंकि दुनिया नीयत को नहीं देख पाती, वह नतीजे को देखती है, परिणाम को देखती है। इसलिए हमारी सारी कोशिशें परिणाम के लिए होती हैं, नीयत के लिए नहीं। अतः हम कविता से चूक जाते हैं। हम परिणाम पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। परिणाम जैसे पुरस्कार पाना, किताब छपवाना, सम्मान पाना, जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों, अकादमियों के पद पाना इत्यादि। ये सब चीजें हमें विचार से आगे नहीं जाने देती। शब्द के भीतर नहीं उतरने देती।

क्योंकि शब्दों में आपकी नीयत दिखती है। आप किसके पक्ष में हैं, किसके विपक्ष में हैं, किसके साथ, हैं, किसके विरोध में हैं, यह स्पष्ट दिखाई देता है। भाव के अंदर आपकी नीयत स्पष्ट नहीं दिखती। कविता के लिए आपको स्वयं के व्यक्तित्व का विसर्जन करना पड़ता है।

मेरे लिए विचार कविता जैसा कोई शब्द नहीं है। मेरा मानना है कि जहां विचार है, वहां कविता बहुत दूर है, क्योंकि विचार बुद्धि की चीज है। विचार को तर्क से काटा जा सकता है। कविता भाव जगत की चीज है और भाव को आप अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते है।

कविता बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। बुद्धि तर्क करती है। किसी व्यक्ति को तर्क से (बुद्धि से) रूपांतरित नहीं किया जा सकता। तर्क से वह हारा हुआ अनुभव करेगा, बदला हुआ नहीं। रूपांतरण भाव की छलांग है।

देखता हूं आज फिर बचकर सुरक्षित रह गया
जल गई सब पुस्तकें अक्षर सुरक्षित रह गया
जिस्म तो गिरना ही था मुरझा के उसका शाम तक
फूल ने खुशबू लुटाई औ' सुरक्षित रह गया

AI नियमित हो निरंकुश नहीं

प्रो. (डॉ.) सचिन बत्रा
शोध सलाहकार, मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली

हमें भी सिंगापुर, चीन, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ही तरह AI को कानून के अधीन या स्वाधीन बनाना होगा। हालांकि यह सच है कि AI से किसी को शिकायत तो नहीं है लेकिन वैश्विक स्तर पर उसके अनियंत्रित उपयोग को लेकर सवाल जरूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात्कार में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा था कि मैं यह तो मानता हूं कि AI मानवता को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा है लेकिन उसे सख्त नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।

पूरी दुनिया में AI आज सर्वाधिक सुलगता हुआ मुद्दा है। मान्यता यह है कि जो AI पर राज करेगा उसकी पूरी दुनिया में बादशाहत होगी। इसलिए एआइ पर तो अब गला काट प्रतिस्पर्धा ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। ताजा मामला चीन के डीपसीक एआइ चैटबॉट के मॉडल R—1 का है। जिसने वैश्विक बाजार में अपनी कम कीमत के चलते तहलका मचा दिया है। AI मामले पर चीन और अमेरिका के बीच डिजिटल युद्ध को देखते हुए भारत ने भी इसमें जोर आजमाइश की तैयारी कर ली है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान कर दिया है कि भारत भी 10 महीने के भीतर अपना एआइ चैटबॉट विकसित कर लेगा। इसमें एक दिलचस्प दावा यह भी है कि यह मॉडल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। वहीं सरकार ने एआइ के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है।

यह देखना सुखद है कि हमारा भारत भी दुनिया में AI वर्चस्व वाले देशों की पंक्ति में अपना झंडा गाड़ने को तैयार है। लेकिन असल मुद्दा तो निरंकुश AI की समस्या से निपटने का है। क्योंकि इसे लेकर कई विवाद और यक्ष प्रश्न भी सामने आए हैं। एक तरफ तो AI के लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए जो डाटा एक्सेस किया जाता है उसके लिए कॉपीराइट कंटेट इस्तेमाल करने की विधिवत अनुमति लेना ही बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कंटेंट देश का भी होगा और दूसरे देशों का भी। इसी प्रकार डाटा की सुरक्षा व निजता यानी प्राइवेसी को सुरक्षित व संरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती साबित होता है। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि डीपसीक ने भले ही 20 महीने में R—1 मॉडल को इजाद कर लिया था लेकिन न्यूयार्क की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज ने उसके 10 लाख संवेदनशील डाटा तक सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल करते हुए सुरक्षात्मक सुदृढता को कटघरे में खड़ा कर दिया।

हालांकि 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में इसके विविध पहलुओं को परखने के लिए AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसमें अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के साथ-साथ खाड़ी के देश भी एक साथ आए, जिनकी वैश्विक स्तर पर AI प्रौद्योगिकियों के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। इसमें भारत को AI के क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं और नवाचारों का अग्रणी देश माना जा रहा है। इसका कारण यह भी है कि हम AI आधारित बुनियादी सुविधाओं व समाधानों की खोज को एक देशव्यापी अभियान का रूप दे चुके हैं।

AI के विविध विकल्पों के विकास की होड़ में हम अकेले नहीं हैं। बहुत से देश AI ऐप बनाकर सेवाओं का एक संगठित कारोबार कर रहे हैं। लेकिन AI के नियमन के लिए उन्होंने बुनियादी ढांचा, नियम कायदे या कानून भी विकसित कर लिए हैं। जहां तक हमारे देश की बात करें तो दिसंबर में एक सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि यदि सदन और समाज सहमत हो तो एआइ के उपयोग के लिए कानून बनाया जा सकता है। यानी हमें भी सिंगापुर, चीन, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ही तरह AI को कानून के अधीन या स्वाधीन बनाना होगा। हालांकि यह सच है कि AI से किसी को शिकायत तो नहीं है लेकिन वैश्विक स्तर पर उसके अनियंत्रित उपयोग को लेकर सवाल जरूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात्कार में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा था कि मैं यह तो मानता हूं कि AI मानवता को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा है लेकिन उसे सख्त नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।

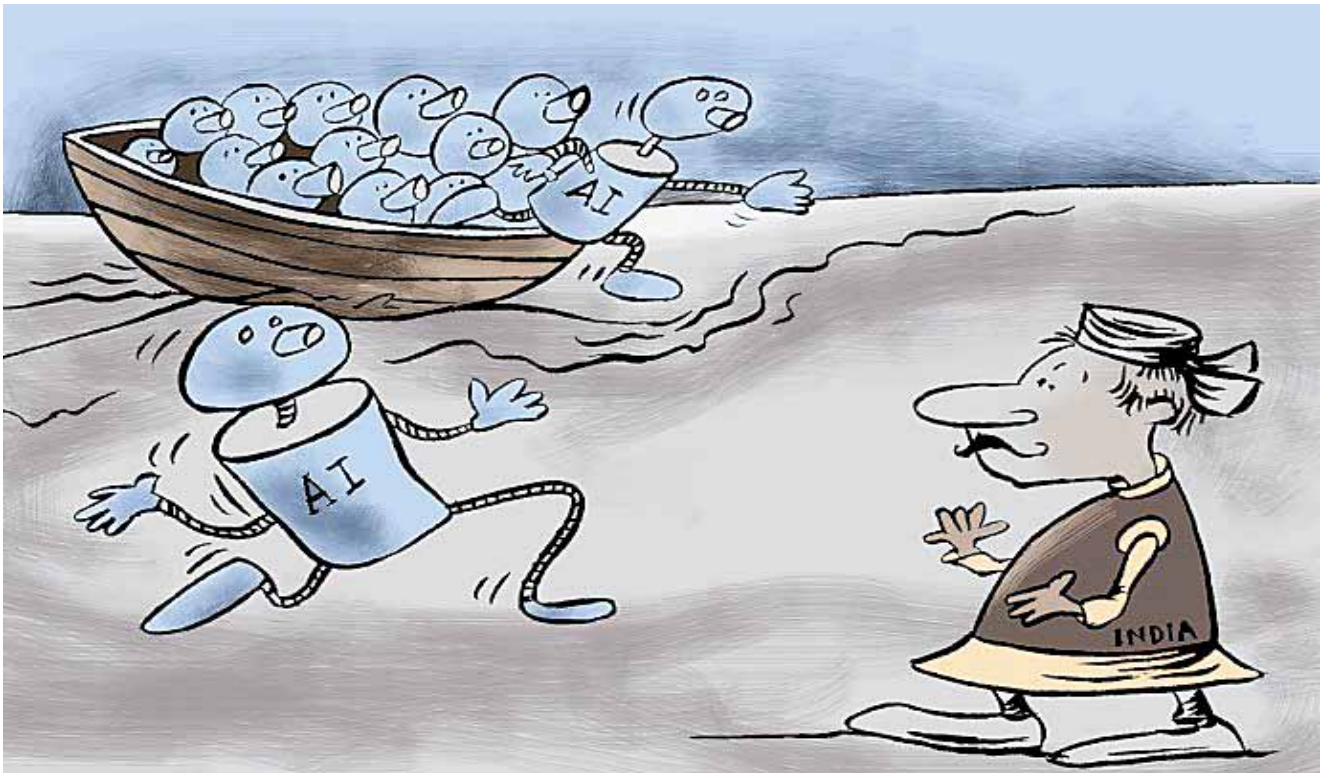

वैसे AI के फायदे तो बहुत हैं लेकिन अगर कायदों की परवाह नहीं की जाती तो निश्चय ही इससे देश, समाज और नागरिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्हीं आशंकाओं के चलते दुनिया के कई देशों ने तो 2020 में ही AI को नियमों के सुरक्षा चक्र या आंशिक प्रतिबंधों से नियमित करना शुरू कर दिया। इसमें सिंगापुर ऐसा पहला देश है जिसने AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क सहित राष्ट्रीय एआइ रणनीति भी बनाई। जिसके तहत AI के पारदर्शी और सुरक्षित उपयोग को कानून के जरिए सुनिश्चित किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन रोकने के लिए AIA यानि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लागू कर दिया। साथ ही GDPR यानि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन जैसे सख्त नियम भी बना दिए। इसी प्रकार अमेरिका ने एएए यानि एल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी एक्ट अमल में लाते हुए AI के खतरनाक प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया। जबकि वहां 1964 का सिविल राइट एक्ट और फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट जैसे कई अन्य फेडरल कानून पहले से ही अस्तित्व में थे। फिर भी AI को केंद्र में रखते हुए नया कानून लाया गया। वहीं चीन की बात करें तो वहां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान 2021—2030 के तहत पहले से ही AI को सुरक्षित, भरोसेमंद और नियंत्रित किए जाने के अनुरूप बनाकर ही जारी किया गया। हालांकि वहां भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ और पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉ भी सख्ती से लागू हैं। लेकिन चीन में सार्वजनिक स्थलों पर फेशियल रिकग्निशन सहित कई AI एप्स प्रतिबंधित हैं। इसी तरह जापान में प्रमोशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत AI को विकसित किया जाता है लेकिन निजी जानकारियों की सुरक्षा को आश्वस्त किया गया है। वहीं फ्रांस की बात की जाए तो वहां AI को विज्ञापन प्रचार व बाजारवाद के माध्यम से उपभोक्ताओं को फंसाने पर रोक है। जर्मनी ने तो लोगों की निगरानी और स्वायत्त हथियारों के मामले में AI पर पाबंदी लगा रखी है। इसी प्रकार रूस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सैन्य अभियानों और निगरानी कार्यक्रमों से अलग रखा है।

स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 127 देशों ने AI से संबंधित कानूनों या नियमों को सख्ती से लागू किया और 14 देशों ने डेटा प्रोटेक्शन कानून पारित किए। AI के नियंत्रित व घात रहित प्रयोग के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल AI कॉसिल ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और इस्तेमाल के कई सिद्धांत तय किए हैं। उसमें निष्पक्षता, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, वाजिब इस्तेमाल और मनुष्य के हित संरक्षण को सुनिश्चित करने को कहा गया है। हालांकि AI के उपयोग से परहेज करना भी संभव नहीं है। क्योंकि ओबेरलो की रिपोर्ट को आधार माना जाए तो 2022 में पूरी दुनिया के व्यापार में एआइ की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत रही। वहीं कुछ प्रमुख बिजनेस का 91 फीसदी निवेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जा रहा है। देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं, फाइनेंस, उत्पादन क्षेत्र और कस्टमर केयर जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफल और सकारात्मक उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में कार्यरत 59 फीसदी कंपनियां AI का सहयोग ले रही हैं।

> गौरतलब यह भी है कि नवभारत टाइम्स में 22 जनवरी को प्रकाशित एक समाचार में एक सर्वे का हवाला दिया है कि हमारे देश में 74 प्रतिशत कर्मचारी AI के अंधानुकरण के चलते अपनी नौकरियों को हाशिए पर मानते हुए सदमे में है। कानून बनाते समय सरकार को इन यक्ष प्रश्नों पर भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि कायदे के बिना जहां यह फायदे का सौदा साबित हुआ है वहीं डाटा डकैती और अपराध का हथियार भी बनता जा रहा है। ऐसे में AI से जुड़ी उम्मीदों ही नहीं आशंकाओं को भी नियमन या कानूनी अंकुश से हाइजीनिक व ऑर्गेनिक AI को सुनिश्चित करना होगा।

कुल मिलाकर सबको AI का नफा तो चाहिए लेकिन नुकसान नहीं। हालांकि पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई सर्वमान्य कानून तो नहीं है लेकिन अब तक करीब 37 देशों ने AI सुरक्षा और नियमन के लिए सख्त कानून बना लिए हैं। वहीं 14 देशों ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए AI के मनमाने इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारे देश में भी है। वहीं नीति आयोग के निर्देशन में 2019 में 'एआइ फॉर आल' योजना सहित AI नियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। फिर भी आजाद और निरंकुश AI के जायज इस्तेमाल के लिए सर्वमान्य कानून बहुत जरूरी है ताकि इसका उत्पादक इस्तेमाल समाज व देश हित में ही किया जाए।

वह विश्व विजय

50 साल पहले मलेशिया में उठाया था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला विश्व कप

महेंद्र सिंह लालस ✍
लेखक व कमेंटेटर

हॉकी विश्व कप विजय की स्वर्ण जयंती पर उस जीत को याद कर रहे हैं हॉकी के अंतरराष्ट्रीय कॉमेंटेटर और विश्व कप, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों जैसी स्पर्धाओं में भारतीय हॉकी के प्रदर्शन के साक्षी रहे लेखक

विश्व विजेता ट्राफी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी

बरसात रोकने के लिए टोने टोटकों का सहारा शायद कुछ काम आया होगा। ख़ासतौर पर भारत के लिए, जिसने सेमीफाइनल में मेज़बान मलेशिया को शिकस्त दे फाइनल में जगह बनाई। 15 मार्च 1975 को खचाखच भरे मरडेका स्टेडियम में दो परंपरागत प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने- सामने थीं। पहले विश्व कप का विजेता पाकिस्तान और दूसरे विश्व कप का उपविजेता भारत।

17वें मिनट में ज़ाहिद शेख ने गोल कर पाकिस्तान को 1–0 से आगे कर दिया। हाफटाइम में जब दोनों टीमें अपने- अपने खेमों में लौटीं तो दबाव भारत पर था। कोई 70,000 दर्शक थे और उनका शोर पाकिस्तान के ही पक्ष में था। मध्यांतर के बाद नवें मिनट में पिछले विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे और दुनिया के सबसे मज़बूत रक्षक कहलाने वाले सुरजीत सिंह ने कॉर्नर से गोल कर भारतीय टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब मैच एकतरफा नहीं था और पाकिस्तान को अपने ही देश में बनी ट्रॉफी अपने ही देश में ले जाने के लिए एक गोल की दरकार थी। हमले तो निरंतर होते रहे और लेस्ली फर्नांडीज की जगह भारत का गोल पोस्ट संभाल रहे अशोक दीवान ने ये सारे हमले संभाल लिए। मगर ये दिन भारतीय हॉकी के लिए अपने पसीने को जीत में बदलने के लिए ही बना था शायद। 50 मिनट हो चुके थे। एक बेहतरीन पास अशोक कुमार की स्टिक पर आया और उसने पाकिस्तान की गोल पोस्ट को भेद दिया। दादा ध्यानचंद के सपूत बेटे के इस गोल ने देश को दिलाया पहला विश्व कप। इसके 8 साल बाद वर्ष 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत को दिलाया था क्रिकेट का विश्व कप।

अशोक कुमार विनम्रता से कहते हैं, 'मुझे लगता है मुझे वो पास नहीं मिलता तो शायद गोल नहीं हो पाता, ये मेरा गोल नहीं था टीम का गोल था।'

कप्तान अजित पाल सिंह जब ये ट्रॉफी लेकर वतन पहुंचे तो देश ने इन खिलाड़ियों को पलक पावड़ो पर बिठा लिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद तक इस ख़ुशी में शामिल हुए। इन खिलाड़ियों ने फिल्म स्टार्स के साथ मुंबई के खचाखच भरे स्टेडियम में हॉकी भी खेली।

ये भारत की पहली विश्व विजय थी। इसके बाद से भारत अपने दूसरे विश्व कप की तलाश में जुटा है। वर्ष 1975 के बाद भारत ने चार बार विश्व कप हॉकी की मेज़बानी ज़रूर की, लेकिन इनमें एक बार भी हमारी टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई। अशोक कुमार बताते हैं, "टर्फ आने के बाद से यकायक हमारा प्रदर्शन गिरता गया और यूरोपीय टीमों का बोलबाला बढ़ता गया।"

विश्व कप विजेता टीम के सदस्य एच.जे.एस. चिमनी कहते हैं, "पिछले दशक से हमने हॉकी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन विश्व कप में पिछले पांच दशकों से उस प्रदर्शन की हमें दरकार है।"

विश्व विजेता ट्राफी के साथ भारतीय टीम

टीम के कोच बलबीर सिंह सीनियर ने जीत के बाद कहा, "बच्चों ने मेरी लाज रख ली। पूरे टूर्नामेंट में हम रंग दे बसंती चोला गीत गाते थे।"

टीम की सेमीफाइनल में मलेशिया के विरूद्ध जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर हरचरण सिंह बताते हैं, "मेरा जर्सी नंबर 15 था और हम 15 मार्च को ही कुआलालंपुर में विश्व कप जीते।

कौन भूल सकता है सब्स्टीट्यूट असलम शेर खान का सेमीफाइनल में वह गोल। असलम कहते हैं, " शायद वह गोल न आता तो टीम सेमीफाइनल की बाधा पार ही नहीं कर पाती। इस विजय में शायद मेरी भी आहुति लग गई।"

क्रिकेट टीम की 1983 की विजय जैसा ही था जलवा

विश्व विजेता बनने के बाद तिरंगे के साथ दर्शकों का अभिवादन करती भारतीय टीम।

▪ 2 मार्च को पूल-बी के अपने पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 2–1 से हरा कर शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से 1–1 की बराबरी पर खेला। घाना को 8 मार्च को 8–0 से रौंदा, मगर अर्जेंटीना से अगले ही दिन टीम 2–1 से हार गई। एकमात्र गोल हरचरण सिंह ने ही किया। भारत की इस विश्व विजय पर पुस्तक लिख चुके ए.अरुमुगम कहते हैं, "गनीमत ये रही कि हमने पश्चिम जर्मनी को अच्छे अंतर से हराया और उसको अपने पूल में दूसरे स्थान पर धकेलने में सफल रहे, इस तरह सेमीफाइनल में भी हम पाकिस्तान के सामने नहीं थे।"

▪ वर्ष 1975 के इस विश्व कप के बाद भारत ने 1982, 2010, 2018 और 2023 में विश्व कप हॉकी का आयोजन तो किया, लेकिन ट्रॉफी पिछले 50 सालों से भारत वापस नहीं लौटी। 1982 और 1994 के विश्व कप में इसके बाद भारत का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा जब टीम पांचवें स्थान पर रही।

▪ भारत, जर्मनी, नीदरलैंड्स और स्पेन ही ऐसे देश हैं, जो अब तक हुईं सभी 15 विश्व कप प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और सितंबर में राजगिर में तय हो जाएगा कि भारतीय टीम क्वालीफाई कर पाती है या नहीं। पिछले दो ओलिंपिक खेलों के कांस्य पदक और एफ आई एच प्रो लीग में भारत का अच्छा प्रदर्शन उम्मीद तो जगाता है कि टीम पोडियम पर शायद पहुंच जाए।

▪ टीम के मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन कहते हैं, " हम अच्छी हॉकी खेल रहे हैं, हमारे पास अच्छा संतुलन है और खिलाड़ियों में कुछ कर गुजरने का माद्दा भी, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य है क्वालीफाई करना।" फुल्टन और हरमनप्रीत की टीम अगर यूरोपीय टीमों को उन्हीं के घर में हॉकी के पाठ पढ़ा दे, तो शायद 51 साल बाद ये देश खेलों की शायद सबसे खूबसूरत ट्रॉफियों में से एक विश्व कप हॉकी की ट्रॉफी का दुबारा स्वागत कर पाएगा।

युद्ध के कारण प्रतियोगिता स्पेन में

विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान अजित पाल सिंह के साथ 2018 के विश्व कप का आंखों देखा हाल सुनाते लेखक (मध्य में)

विश्व कप हॉकी की ट्रॉफी पाकिस्तान में ही बनी थी और वहीं 1971 में पहले विश्व कप का आयोजन होना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध की वजह से प्रतियोगिता स्पेन में हुई। एयर मार्शल बशीर मुजीद की डिजाइन की हुई इस ट्रॉफी को पाकिस्तानी सेना ने ही बनाया और जब 1975 का विश्व कप जीतने के बाद इस ट्रॉफी को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हाथ में लिया तो उन्हें पाकिस्तान के नक्शे में जम्मू और कश्मीर देख कर ऐतराज हुआ। लेकिन ये ट्रॉफी इसी स्वरूप में आगे बंटती रही। वर्ष 2018 में तत्कालीन विश्व हॉकी संघ (एफआईएच) के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने साफ कह दिया कि अगर इसे सुधारा न गया तो भारतीय सीमा अधिकारी इस ट्रॉफी का भारत में प्रवेश नहीं होने देंगे। लिहाजा एफआईएच ने इस ट्रॉफी में बनी देश की सीमाओं को हटा कर सिर्फ महाद्वीपों की सीमाओं को रखा।

#फोटो साभार stick2hockey.com & hockey India#

ग्रहों की चाल

ज्योतिषी : विपुल डोभाल
ईमेल : vipravaani@gmail.com
मोबाइल : 9928424374

शनि ग्रह का राशि परिवर्तन... 29 मार्च 2025 को खगोलीय दुनिया में एक बड़ी हलचल ने अनेक राशियों को प्रभावित किया है। शनि गृह ने कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किया है। जिससे मकर राशि की साढ़े- साती समाप्त हुई है, किंतु मेष राशि के लोगों की साढ़े- साती प्रारंभ हो गई है। इसके अतिरिक्त दो और राशियां जो सीधे- सीधे प्रभावित हुई हैं, वह हैं सिंह और धनु। इन दोनों ही राशियों की ढैया प्रारंभ हुई है।

ऐसा नहीं है कि बाकी राशियां शनि के इस स्थान परिवर्तन के प्रभाव से अछूती रह जाएंगी। सभी राशियों पर कुछ अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने सुनिश्चित हैं। जब भी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उससे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद सभी राशि वालों को किसी न किसी रूप में प्रभावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सतर्कता बरतें और बड़े निर्णयों से बचें। शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह जब भी घर बदलते हैं, तब केवल मानव मात्र पर प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु बड़े आवासीय भूखंडों पर भी प्रभाव पड़ता है। सामूहिक रूप से बड़े प्राकृतिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कई बार भूकंप, सुनामी एवं महामारियां इत्यादि इसी प्रकार के योगों में घटित होती हैं।

आने वाले लगभग 4 महीनों में शनि और राहु का गोचर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालता दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा, युद्ध और क्रांतियां घटित होने की आशंकाएं रहती हैं। कॉविड-19 के अक्टूबर माह में भी इसी प्रकार का संयोग बना था, जिसकी भविष्यवाणी मेरे द्वारा एवं अनेक पंचांगों में पहले ही कर दी गई थी। शीघ्र ही मैं ज्योतिष के वैज्ञानिक आयामों पर भी विश्लेषणात्मक जानकारी आपको उपलब्ध कराउंगा, जिस पर मैंने एक इंजीनियर की दृष्टि से शोध कार्य करने की कोशिश की है।

मेष

इस राशि के जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान देने वाला रहेगा। विशेष रूप से नेत्र दोष और न्यूरो से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। कुटुंब में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। व्यय अनियंत्रित होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कोई भूमि, भवन या वाहन की खरीद कर रहे हैं तो इस महीने टाल दें।

इस माह ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप शुभ रहेगा।

वृषभ

इस राशि के जातक इस महीने सामाजिक रूप से मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। किंतु कार्य क्षेत्र में द्वंद्व की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बेवजह के विवादों से बचाव रखें। आपके संचित धन पर खतरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी व्यय पूरी प्लानिंग के साथ करें। कान से संबंधित समस्या और चर्म संबंधित एलर्जी परेशान कर सकती है।

इस माह विष्णु जी या उनके अवतारों का पूजन अर्चन शुभ रहेगा।

मिथुन

इस राशि के व्यक्ति क्रोध से बचें। व्यर्थ के विवाद की स्थितियां घर और कार्य क्षेत्र दोनों में ही बन सकती हैं। जहां तक संभव हो शांत रहकर हल निकालें। आपका भाग्य इस माह साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशे वाले लोग तनाव में दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु इस माह जॉब परिवर्तन करना कोई बहुत शुभ नहीं दिखाई पड़ रहा है।

इस दौरान सूर्य को जल चढ़ाएं और शनि देव के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें।

कर्क

इस राशि के जातक बहुत राहत महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। इस माह अपने कर्म पर विश्वास करते हुए कदम आगे बढ़ाएं। भाग्य पूरी तरह साथ नहीं दे रहा है, किंतु अंततः सफलता आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखें। उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। महिलाओं से सतर्कता रखें अन्यथा अपयश मिल सकता है।

इस माह शुक्रवार को सफेद पदार्थ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

सिंह

इस राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 29 मार्च से शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है, अतः आने वाले ढाई वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय के ऊपर बहुत विचार करके ही आगे बढ़ाना शुभ रहेगा। पत्नी को स्वास्थ्य कष्ट रहेगा। कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन सकती है और कुछ लांछन भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपकी निजी और सार्वजनिक दोनों ही जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है।

शनि देव की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी।

कन्या

इस राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। वैवाहिक युगल भी आपसी मतभेद से गुजर सकते हैं। नाभि और निचले हिस्सों में स्वास्थ्य कष्ट रह सकता है। महिलाओं को स्त्री जन्य रोग परेशान कर सकते हैं। भाग्य साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है। व्यर्थ की भागदौड़ दिख रही है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और उनकी तरफ से शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आय के साधन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान सुख योग उत्तम है।

इस माह हर गुरुवार केले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना शुभ रहेगा।

तुला

इस राशि के जातकों के लिए यह महीना पिछले कुछ महीनों की तुलना में बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे। पुराने चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे। किंतु किसी भी नए विवादों से बचें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है। दूरगामी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

इस माह शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृश्चिक

इस राशि के लिए यह माह सुख बाधक दिखाई पड़ रहा है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त एक माह के लिए रोक दें तो अच्छा रहेगा। नाभि और निचले हिस्से साथ ही लीवर आंतों का ध्यान रखना होगा। कमर के निचले हिस्से भी तकलीफ दे सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को भी कष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके कार्यक्षेत्र में भाग्य साथ देगा। आय के साधन बने रहेंगे। आपकी शनि की ढैया समाप्त हो रही है, अतः धैर्य रखें।

एक माह पश्चात जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहे हैं।

बालाजी का स्मरण और पूजन शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं।

धनु

इस राशि के जातक प्रेम प्रसंग में विवाद की स्थिति में आ सकते हैं। पहले से चली आ रही रिलेशनशिप ख़तरे में पड़ सकती है। पराई स्त्री या पुरुष के कारण मानहानि हो सकती है। आवश्यकता से अधिक रिस्क आपके लिए घातक हो सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। कार्यक्षेत्र में जितनी भागदौड़ या मेहनत करेंगे, उतना ही शुभ फल मिलेगा। पारिवारिक मामलों में तनाव की स्थिति बन सकती है। स्मरण रहे कि आप शनि की ढैया में प्रवेश कर चुके हैं, अतः आने वाले ढाई वर्ष बहुत संयमित तरीके से कदम आगे बढ़ाने होंगे। अगले ढाई वर्ष किसी भी असहाय व्यक्ति की अवहेलना ना करें और ना ही किसी को पीड़ित करें अन्यथा शनि देव आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। यूं तो आने वाले 2 वर्ष शनिदेव की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी और इस माह आप भगवान गणेश जी की स्तुति करें, शुभ रहेगा।

मकर

इस राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह मिले-जुले असर वाला रहने वाला है। प्रारंभिक 14 दिन मानसिक द्वंद्व वाले दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात मन शांत रहेगा और धन लाभ भी होता दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। मान सम्मान की प्राप्ति भी इस माह होगी।

सूर्य को जल अर्पित करना और शनि देव के मंत्रों का जाप शुभ रहेगा।

कुंभ

इस राशि के जातक इस माह एलर्जी से संबंधित रोगों के प्रति सतर्क रहें। माइग्रेन के रोगी परेशान रह सकते हैं। महीने के मध्य भाग तक कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। भूमि भवन और वाहन की ख़रीद में बाधा आ सकती है। व्यवसाय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। किसी शुभ कार्य में धन व्यय होगा। कीमती वस्तुओं को सहेज कर रखें, अन्यथा खोने का भय बना रहेगा।

इस माह हर गुरुवार चने की दाल और गुड़ का दान शुभ रहेगा। दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करें।

मीन

इस राशि के जातकों को इस माह व्यर्थ के विवादों से बचाना है। छाती और नाभि के आसपास के हिस्सों में रोग के प्रति सतर्क रहें। दांपत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाईं आंख की रोशनी पर प्रभाव आ सकता है। भाई बहनों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। इस माह शनि देव का प्रवेश मीन राशि पर होने से बहुत संयम के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। व्यवसाय में बड़े रिक्स ना लें तो अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है।

इस माह भगवान गणेश की स्तुति शुभ रहेगी, साथ ही शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी शुभ रहेगा।

मानवीय संवेदनाओं का चितेरा

फ़िल्मकार - सत्यजित रे

सुधांशु टाक ✍ लेखक, समीक्षक

सत्यजित की फिल्मों का कलेवर 'ललित कलाओं के कोलाज' सरीखा होता था। शायद यही वजह है कि मशहूर अमरीकी फ़िल्म निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी ने कहा भी है –"रे की फिल्मों में काव्य और सिनेमा को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे में घुलीमिली सी नज़र आती है।"

साल था 1955। भारतीय सिनेमा अभी मानव मूल्यों और यथार्थवाद को समझने का प्रयास कर रहा था। तभी सिनेमा के परदे पर रिलीज हुई "पथेर पांचाली" ने विश्व सिनेमा में भारी उथल पुथल मचा दी। इस फिल्म को तक़रीबन एक दर्जन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाज़ा गया। इस फिल्म को बनाने वाले व्यक्तित्व को ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी ने 'डॉक्टरेट' की मानद उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान चार्ली चैप्लिन के बाद अकेले उन्हें ही मिला था जो सिनेमा से जुड़े थे। महान जापानी फ़िल्मकार अकीरा कुरोसावा यहाँ तक कह बैठे- "इस शख़्स की फिल्मों को देखे बिना रहना, चाँद और सूरज को देखे बिना रहना है।" इसके बाद कान्स ,वेनिस ,बर्लिन और ऑस्कर सरीखे दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले वे अकेले भारतीय फ़िल्मकार बने। अपने पूरे करियर में बनाए गए कुल तीन दर्जन फिल्मों के लिए उन्हें 32 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। 'भारत रत्न' पाने वाले वे अबतक के एकमात्र फिल्म निर्देशक बने। यह मुख़्तसर सा बायोडाटा दुनिया के मानचित्र पर भारतीय फिल्मों को स्थापित करने वाले उस फ़िल्मकार का है,जिसे करीब से जानने वाले 'माणिक दा' के नाम से और दुनिया सत्यजित रे (राय) के नाम से पहचानती है।

अपनी नई सिने -दृष्टि के साथ सत्यजित रे ने तत्कालीन फिल्म निर्माण के तौर तरीके के विपरीत गैर-पेशेवर अदाकारों और टेक्निशियन्स के साथ आउटडोर लोकेशन पर रियल लाइट में फिल्मांकन किया था। सत्यजित रे इस मायने में भी अलग थे कि उनकी फिल्मों का कलेवर 'ललित कलाओं के कोलाज' सरीखा होता था। शायद यही वजह है कि मशहूर अमरीकी फ़िल्म निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी ने कहा भी है –"रे की फिल्मों में काव्य और सिनेमा को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे में घुलीमिली सी नज़र आती है।"

दिलचस्प बात यह है कि 'पथेर पांचाली' बनाने से पहले रे के पास न तो फिल्म-निर्माण का कोई अनुभव था और न ही यथार्थवादी फिल्मों का कोई बेहतर भारतीय प्रतिमान सामने था। लेकिन 'बंगाल रेनेसाँ' से प्रभावित पारिवारिक पृष्ठभूमि,शांतिनिकेतन में रहते हुए विकसित हुई कला-दृष्टि, अपने साथियों के साथ बनाए गए फिल्म क्लब में विश्व-सिनेमा से परिचित होने के मौकों ने उन्हें संवेदनशील फिल्म दर्शक ज़रूर बना दिया था।

सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। वे उनके माता – पिता की इकलौती संतान थे। वे सिर्फ 3 साल के थे जब उनके पिताजी सुकुमार रे निधन हो गया।

इस घटना के बाद उनकी माता सुप्रभा रे ने उनका बड़ी मुश्किल से पालन पोषण किया था। उनकी माँ रवींद्र संगीत की मंजी हुई गायिका थी। उनके दादाजी 'उपेन्द्रकिशोर रे' एक लेखक एवं चित्रकार थे और इनके पिताजी भी बांग्ला में बच्चों के लिए रोचक कविताएँ लिखते थे।

स्कूली शिक्षा ख़त्म होने के बाद उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढाई की। और फिर आगे की पढाई के लिए शांति निकेतन गए। लेकिन इनकी रुचि हमेशा से ही ललित कलाओं में रही। शांति निकेतन में रे पूर्वी कलाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस और बिनोद बिहारी मुखर्जी से कला के पाठ लिए। अगले पांच साल शांति निकेतन में रहने के बाद वे 1943 में फिर कलकत्ता आ गए और बतौर ग्राफिक डिजाइनर का काम करने लगे। इनके पद का नाम "लघु द्रष्टा" था और महीने के केवल अस्सी रुपये का वेतन था। जिम कॉर्बेट की 'मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं' और जवाहरलाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' के आवरण भी सत्यजीत रे ने ही डिजाइन किये थे। राय ने दो नए फॉन्ट भी बनाए "राय रोमन" और "राय बिज़ार"। राय रोमन को 1970 में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला।

सत्यजित रे एक हरफ़नमौला कलाकार थे। जिन्हें फ़िल्म के हर डिपार्टमेंट में महारत हासिल थी। डायरेक्शन के साथ साथ फ़िल्म की पटकथा, संपादन और फ़िल्म के पोस्टरों से लेकर एक्टरों की ड्रेस तक की डिजायन वे खुद करते थे। यहां तक के अपने करियर की आख़िरी फ़िल्मों में उन्होंने ही संगीत दिया था। यही नहीं मर्चेंट आइवरी की फ़िल्म 'शेक्सपीयर वाला' और बंगाली फ़िल्म 'बाक्स बदल' में भी सत्यजित रे का ही म्यूजिक है। यह बतलाना भी लाज़िमी होगा कि रबीन्द्रनाथ टैगोर के निधन के बाद सत्यजित रे ने उन पर एक बेहतरीन डॉक्युमेंट्री 'रबीन्द्रनाथ' भी बनाई थी। जिसमें उन्होंने गुरुदेव टैगोर की ज़िंदगी के अहम वाक़यात को फिल्माया है। इस डॉक्युमेंट्री की पटकथा, नरेशन और निर्देशन सत्यजित रे का ही है। 'रबीन्द्रनाथ' डॉक्युमेंट्री के अलावा सत्यजित रे ने कुछ दीगर अहम हस्तियों चित्रकार विनोद बिहारी मुखोपाध्याय, सुकुमार रे और भरत नाट्यम की नृत्यांगना बालसरस्वती पर भी वृतचित्र बनाए। उन्होंने कुछ कहानियां लिखीं।

सत्यजित रे मानवीय संवेदनाओं के चितेरे फ़िल्मकार थे। जिन्होंने सेल्युलाइड पर अपनी फ़िल्मों से कई बार करिश्मा किया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ''एक फ़िल्मकार के तौर पर मेरा मुख्य काम ऐसी कहानी की तलाश करना है, जिसमें मानव-व्यवहार और उसके बीच के रिश्तों के सच्ची पड़ताल हो। यह पड़ताल बनी-बनाई ढ़र्रे वाली न हो, न ही नकली स्टीरियोटाइप ! बल्कि उस पड़ताल में मानवीय संवेदना हों, जो तकनीकी संसाधनों के साथ उस कहानी को चाक्षुष यानी देखने लायक बनाती हो।'

सत्यजित रे, एक जीनियस फ़िल्मकार थे। फ़िल्मों में बेशुमार कामयाबी के बाद भी सत्यजित रे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्हें न तो बॉलीवुड ने लुभाया और न ही उनकी चाहत कभी हॉलीवुड जाने की हुई। जबकि सत्यजित रे को हॉलीवुड की कई फ़िल्मों के ऑफ़र मिले थे। वे कलकत्ता में ही ख़ुश थे। उन्हें वहीं दिली सुकून मिलता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद यह बात कबूली थी, ''मैं जब विदेश में होता हूं, बहुत रचनात्मक महसूस नहीं करता हूं। मुझे इसके लिए कलकत्ता में अपनी कुर्सी ही चाहिए।'' फ़िल्मी दुनिया में सत्यजित रे के अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाज़ा गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया, तो वहीं सत्यजित रे की फ़िल्मों को 32 नेशनल अवार्ड मिले। जिनमें 6 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । फ्रांस का 'लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड', 'रेमन मैग्सेसे अवार्ड', 'स्टार ऑफ़ यूगोस्लाविया' जैसे अहम पुरस्कार भी मिले ।

90 के दशक की शुरुआत में उनकी सेहत ने उनका साथ देना छोड़ दिया था और उनका चलना-फिरना भी सीमित हो गया था। 23 अप्रैल 1992 को उनका निधन हो गया। सत्यजीत रे की मौत वाले दिन जैसा दिन कोलकाता ने पहले कभी नहीं देखा था। पूरा कोलकाता उस दिन गमगीन था । अगले दिन झुलसाती गर्मी की परवाह किए बिना हजारों लोग उनके पार्थिव शरीर के साथ आगे बढ़ रहे थे। सत्यजीत रे के जाने से भारतीय सिनेमा के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। रे हमेशा याद आएंगे...

एकमात्र हिंदी फीचर फिल्म... सत्यजीत रे ने कुल 36 फिल्में बनाई . उन्हें 32 नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले.सत्यजीत रे की 'शतरंज के खिलाड़ी' हिंदी भाषा की इकलौती फीचर फिल्म थी. इस फिल्म की कहानी अवध के आखिरी मुगल वाजिद अली शाह और उनके शासन काल के ऊपर थी.

जयाप्रदा की सुंदरता के मुरीद थे... महान फिल्मकार सत्यजीत रे अभिनेत्री जयाप्रदा के सौंदर्य और अभिनय से अत्यधिक प्रभावित थे । उन्होंने जयप्रदा को विश्व की सुंदरतम महिलाओं में एक माना था। वे उन्हें सिनेमा का सबसे हसीन चेहरा मानते थे । सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म बनाने के लिए इच्छुक थे लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उनकी योजना अधूरी रह गई।

ऑस्कर अवॉर्ड घर चलकर आया

ऑस्कर अवॉर्ड की चाहत दुनिया भर के फिल्मों से जुड़े व्यक्तित्वों की होती है.1992 की शुरुआत में ऑस्कर कमेटी द्वारा उन्हें ऑनरेरी अवॉर्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की गई थी. लेकिन उस दौरान वे बहुत बीमार थे. ऐसे में ऑस्कर के पदाधिकारियों ने फैसला लिया था कि ये अवॉर्ड उनके पास पहुंचाया जाएगा. ऑस्कर के पदाधिकारियों की टीम कोलकाता में सत्यजीत रे के घर पहुंची थी और उन्हें अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसके करीब एक महीने के भीतर ही उनका निधन हो गया था.

पंजीयन क्रमांक : 1/39-40 स्थापित सन : 1919 आर.बी.आई.ला.नं. : यूबीडी राजस्थान 006(पी)

रेलवे ऐम्पलॉइज को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लि.

(जोधपुर डिवीजन), जोधपुर

पंजीकृत पता: रेलवे इंस्टीट्यूट, हरीश जोशी मार्ग, रेलवे स्टेशन रोड, जोधपुर (राजस्थान), टेलीफोन एवं टेलीफैक्स: 0291-2620690, रेलवे फोन -44054

रेलवे बैंक बॉण्ड

विनियोजित राशि 108 माह (9 वर्ष) में दुगनी, न्यूनतम राशि रु. 1000

विनियोजन रु. 1000 के गुणकों में ही स्वीकार।

आवर्ती जमा पर देय ब्याज दरें (दिनांक 16 जून 2023 से लागू)

	सामान्य	वरिष्ठ नागरिक
1 वर्ष की अवधि पर	5.50%	6.00%
2 वर्ष की अवधि पर	6.00%	6.50%
3 वर्ष की अवधि पर	6.50%	7.00%

मासिक आय योजना (MIS): ब्याज दर 6.50% वार्षिक तथा परिपक्वता पर 2% बोनस (अतिरिक्त ब्याज), यह योजना 6 वर्ष के लिए होगी तथा अधिकतम निवेश की सीमा राशि रु. 15 लाख तक होगी, चाहे ग्राहक का खाता एक या एक से अधिक नाम से हो।

*न्यूनतम जमा राशि रु. 5000, विनियोजन राशि रु. 1000 के गुणकों में ही स्वीकार।

मियादी जमाओं पर देय ब्याज दरें (दिनांक 01 जून 2024 से लागू)

*सभी अमानतें बीमित/मियादी जमाओं पर ऋण सुविधा उपलब्ध

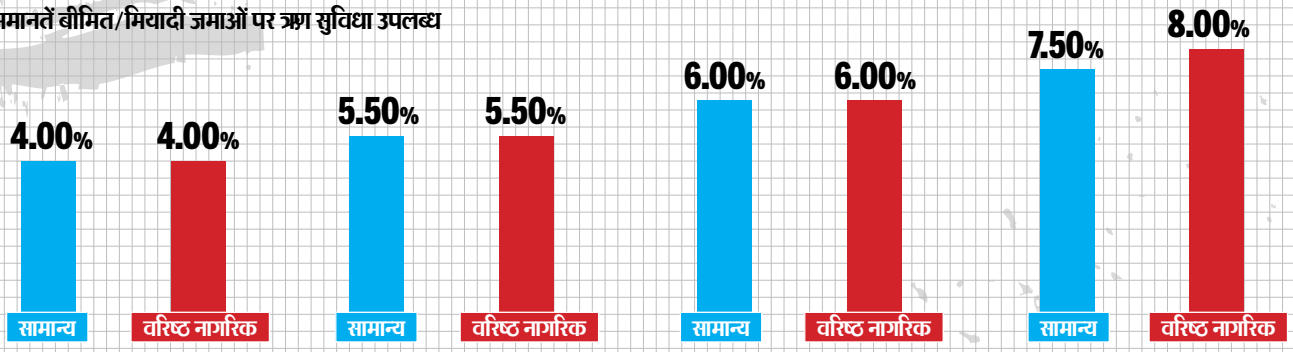

मनोज कुमार परिहार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नोट...

01. 365 दिन से अधिक एवं कम से कम रु. 10000 की मियादी जमा कराने पर ही वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति) का लाभ दिया जाएगा।
02. 365 दिन से अधिक अवधि की मियादी जमाओं पर साधारण ब्याज दर से त्रैमासिक आधार पर ब्याज राशि ग्राहक के बचत खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
03. मियादी जमाओं पर ऋण सुविधा उपलब्ध। मियादी जमाएं अधिकतम 10 वर्ष तक ही स्वीकार की जाएगी।

Sri Chaitanya
ACADEMY
IIT-JEE | NEET | FOUNDATION
Dr. B.S. Rao
(Founder Chairman)
Smt. Sushma Boppana
(CEO & Director)
With outstanding Results & 40 years Legacy
of Extraordinary Academic System...
जयपुर और सीकर के साथ अब
JODHPUR में
A Perfect HAT-TRICK RECORD
Sri Chaitanya Produced AIR-1 in JEE Main, JEE Advanced & NEET-2023
Results 2023
1 300/300 MARKS ALL INDIA RANK JEE-Main 2023
S Venkat Koundinya Appl. No. 230310124339
1 341/360 MARKS ALL INDIA RANK JEE-Advanced 2023
V Chidvilas Reddy Ht. No. 236165088
1 720/720 MARKS ALL INDIA RANK NEET-2023
B Varun Chakravarthi Ht. No. 1205120175
Sri Chaitanya Success Story
40 Years of Excellence 1986-2025
40 years Legacy
23 States
245 Cities
9.5 Lakh+ Students
950+ Branches
Lakhs Of Engineers & Doctors
Sri Chaitanya Academy Produced
AIR-1 in JEE & NEET-2024 in All-Category*
Results 2024
1 300/300 MARKS ALL INDIA RANK JEE-Main 2024
K.C. BASAVA REDDY | Appl No. 240310618179*
1 326/360 MARKS ALL INDIA RANK JEE-Advanced 2024
RAGHAV SHARMA H.T. No : 242053073*
1 720/720 MARKS ALL INDIA RANK NEET-2024
IRAM QUAZI Appl. No. 240411319060*
JEE Advanced-2024 Results Summary
6 Ranks In Top 10
AIR-1,4,5,6,9,10
Total Qualified in JEE Advanced-2024 4,187+
Below 100 All-India Open Category Ranks 30 Ranks
Below 500 All-India Open Category Ranks 122 Ranks
Below 1000 All-India Open Category Ranks 205 Ranks
Below 1000 All-India All Category Ranks 789 Ranks
JEE Main-2024 Result Summary
4 Ranks In Top 10 AIR-1,3,6,9
Total Qualified in JEE Main-2024 24,403+
Below 100 All-India Open Category Ranks 25 Ranks
Below 500 All-India Open Category Ranks 108 Ranks
Below 1000 All-India Open Category Ranks 222 Ranks
Below 1000 All-India All Category Ranks 888 Ranks
NEET-2024 Result Summary
RANKS BELOW TOP 10 IN ALL-INDIA ALL CATEGORIES
1 ALL INDIA OPEN CATEGORY RANK IRAM QUAZI Appl. No. 240411319060*
1 ALL INDIA CATEGORY RANK GUGULOTH VENKATA NRIPESH Appl. No. 240410071070
ALL INDIA 3 RANK ANIMESH SINGH RATHORE Appl. No: 240410376872^
ALL INDIA 7 RANK POREDDY PAVAN KUMAR REDDY Appl. No: 240411179822@
ALL INDIA 10 RANK KAVYA CHITARA Appl. No: 240411509978%
ALL INDIA 10 KARUPARTHI SAI PAVAN KARTHIKEYA Appl. No: 240410712558^
9 Students Scored 715 Marks And Above Out Of 720 MARKS
30 Students Scored 710 Marks And Above Out of 720 MARKS
SRI CHAITANYA RANKS in NEET-2024 22,000+
New Batches Commencement -2025/26
FOUNDATION COURSE
Class 7, 8, 9, 10 Students
Starting on 9th April
2 YEAR COURSE FOR JEE/ NEET
Class 10 to 11 Moving Students
Starting on 9th April & 16th April
1 YEAR COURSE FOR NEET/JEE
Class 11 to 12 Moving Students
Starting on 9th April & 16th April
1 YEAR COURSE FOR JEE/NEET
Class 12 Passed/Dropper Students
Starting on 9th April & 23rd April
Sri Chaitanya ACADEMY
Get up to 90% Scholarship
Appear in C-SAT
Sri Chaitanya Admission Cum Scholarship Test
on 6th April & 13th April 2025
Admissions Open
Few days left....
Launching Offer
Get direct 50% Scholarship on taking admission till 20th April, 2025
[Separate Batches for Hindi & English Medium]
Sri Chaitanya Academy Centres in Rajasthan
RIDHI SIDHI-98515 12951
155, Keshav Vihar, Riddhi Siddhi, Gopalpura Bye pass, Jaipur
GOPALPURA-92814 25109
11, Krishna Vihar, Near Indian Oil Petrol Pump Gopalpura Bye pass, Jaipur
BANIPARK-92814 25107
D-6, Banipark Opp. Chamatkareshwar Mandir, Jhotwara Road, Jaipur
VAISHALI NAGAR-92814 25105
303, Goms Defence Colony, Near Gurudwara, Vaishali Nagar, Jaipur
MAHINDRA SEZ-92814 25105
SEZ Road, Kalwara, Jaipur, Rajasthan
SIKAR-92814 25119
Shree Ganesh Tower, Piprali Road, Sikar
JODHPUR
92161 61116
Surya Tower, PWD Colony, Jodhpur-312001
Sri Chaitanya Techno Schools in Rajasthan Jaipur : Pratap Nagar (9871126129) | Sarna Dungar (9871126129) | Jagdishpuri, Ajmer Road (9871126129) | Sun City Sikar Road (9352825830) | Kamla Nehru Nagar (9001165659)
Sikar (9352825830) | Chittorgarh (9871126129) | Udaipur (9871126129) | Jodhpur (9030868705) | Bharatpur (9871126129) | Sri Ganganagar (9352825830) | Gangapur City (9871126129) | Bikaner (9352825830)
Regional office : Plot No. 155, Keshav Vihar Ridhi Sidhi, Gopalpura Bypass Road, Jaipur -302018, Rajasthan | Call us : 9851512951 | Corporate office : Plot No: 304, Kasetty Heights, Ayyappa Society, Madhapur, Hyderabad - 500081 | www.srichaitanyaacademy.net